खबरें छुपाता नहीं, छापता है

शाह टाइम्स

अधिकतम :30° C
न्यूनतम: 17° C

देहरादून, बुधवार 11 मार्च 2026 देहरादून संस्करण: वर्ष 25 अंक 212 पृष्ठ 12 मूल्य रुपये 5.00

विस्तृत खबरों के लिए QR कोड स्कैन करें। मुफ्त पढ़ें E-paper

shahtimes2015@gmail.com फाल्गुन कृष्ण पक्ष 6 विक्रमी सम्वत् 2082 21 रमज़ान 1447 हिजरी

नई दिल्ली, मुज़फ्फरनगर, देहरादून, हल्द्वानी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ व लखनऊ से प्रकाशित

मिडिल ईस्ट में युद्ध की धमक वेस्ट यूपी तक पहुंची पेज 2

आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन में अर्शदीप पर लगा जुर्माना खेल टाइम्स

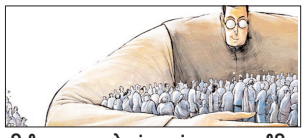

परिसीमन 2026 : लोकतंत्र का संतुलन या राजनीति की नई जंग सम्पादकीय

ईरान जंग का असर: 9 एशियाई देशों में तेल संकट गहराया पेज 12

21वां रोज़ा

दोज़ख से निजात का अशरा

इक्कीसवें रोज़े से तीसवें रोज़े तक के दस दिन/दस रातें रमज़ान माह का आखिरी अशरा कहलाती हैं। चूंकि आखिरी अशरे में ही लैलतुल कद्र/शबे-कद्र जिसमें रात जागकर अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तथा जिस रात को बहुत अज्र की रात माना जाता है। क्योंकि शबे-कद्र से क़ुरआन का नुज़ूल शुरू हुआ था, इसलिए इसे दोज़ख से निजात का अशरा भी कहा जाता है। शर्रे तरीके से रखा गया रोज़ा दोज़ख से निजात दिलाता है। क़ुरआने-पाक में इरशाद फरमाया- आप (सल्ल.)कह दीजिए कि अल्लाह ही तुमको उनसे निजात देता है। मतलब यह हुआ कि लोगों को अल्लाह ही हर रंजो-ग़म और दोज़ख से निजात देता है। सवाल यह उठता है कि अल्लाह तक पहुंचने और निजात को पाने का रास्ता और तरीका क्या है? इसका जवाब है कि सब्र और सदाकत के साथ रखा गया रोज़ा ही अल्लाह तक पहुंचने और दोज़ख से निजात पाने का रास्ता और तरीका है।

मुकद्दस रमज़ान की दिली मुबारकबाद

कोहिनूर आर्ट ज्वैलर्स

एक अनमोल रिश्ता

- ONLY HALLMARK & HUID CERTIFIED GOLD JEWELLERY SHOWROOM
- LIFE TIME FREE SERVICE

सोना, चांदी के जेवरातों के क्रेता व विक्रेता

68- Majra, Dehradun (Uttarakhand)
Mob- 7830677750, 7900900991

संक्षिप्त समाचार

विवादित अध्याय पर एनसीईआरटी ने मांगी बिना शर्त माफी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के निदेशक और सदस्यों ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक समाज की खोज: भारत और उससे आगे के एक विवादित अध्याय को लेकर मंगलवार को बिना शर्त और बिना किसी योग्यता के सार्वजनिक माफी मांगी है। विवाद पुस्तक के अध्याय-4 हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका को लेकर हुआ, जिसमें न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार से जुड़े संदर्भों का उल्लेख किया गया था। एनसीईआरटी ने कहा है कि यह पूरी पुस्तक अब वापस ले ली गई है और फिलहाल उपलब्ध नहीं है। एनसीईआरटी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि असुविधा के लिए हमें गहरा खेद है और हम सभी हितधारकों की समझदारी की सराहना करते हैं। एनसीईआरटी शैक्षणिक सामग्री में सटीकता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

जल्द समाप्त होगा ईरान से युद्ध : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प

वाशिंगटन/फ्लोरिडा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान के साथ जारी सैन्य संघर्ष पर कई महत्वपूर्ण लेकिन अलग तरह के बयान देते हुए कहा है कि युद्ध लगभग पूरा हो चुका है और अमेरिका अपने निर्धारित समय से काफी आगे चल रहा है।

ट्रम्प ने फ्लोरिडा के डोराल में मीडिया को संबोधित करते हुए दावा किया है कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक अमेरिका और इजरायल ने ईरान के पांच हजार ठिकानों पर हमले किए हैं। युद्ध को लगभग पूरा हो जाने की बात बताने के कुछ घंटों बाद फ्लोरिडा में फिर से ईरान के विषय पर बोलते हुए राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि हमने एक छोटी यात्रा की क्योंकि हमें लगा कि कुछ बुराई को खत्म करने के लिए ऐसा करना जरूरी था। उन्होंने आगे कहा कि मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि यह एक बहुत ही कम समय की यात्रा होने जा रही है। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि हमने पहले ही कई मायनों में जीत हासिल कर ली है, लेकिन हमने अभी पर्याप्त जीत हासिल नहीं की है। उन्होंने संकल्प जताते हुए कहा कि हम इस लंबे समय से चले आ रहे खतरे को हमेशा के लिए समाप्त करने और अंतिम जीत हासिल करने के लिए पहले से कहीं अधिक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अपनी औपचारिक प्रेस वार्ता के दौरान ट्रम्प ने दोहराया कि

कहा: युद्ध लगभग पूरा हो चुका, अमेरिका अपने निर्धारित समय से काफी आगे चल रहा

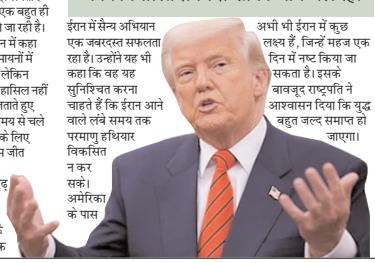

ईरान में सैन्य अभियान एक जबरदस्त सफलता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ईरान आने वाले लंबे समय तक परमाणु हथियार विकसित न कर सके। अमेरिका के पास अभी भी ईरान में कुछ लक्ष्य हैं, जिन्हें महज एक दिन में नष्ट किया जा सकता है। इसके बावजूद राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा।

ट्रम्प के ऐलान से गिरे कच्चे तेल के दाम

तेहरान/तेल अवीव / वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 100 डॉलर को पार कर चुकी कच्चे तेल की कीमतें गिरकर 90 डॉलर के नीचे आ गई हैं, जिसमें दावा किया गया है कि ईरान के खिलाफ अभियान 'लगभग पूरा' हो चुका है और युद्ध जल्द समाप्त होगा। ट्रम्प ने ईरान के साथ जारी सैन्य संघर्ष पर कई महत्वपूर्ण लेकिन अलग तरह के बयान देते हुए कहा है कि युद्ध लगभग पूरा हो चुका है और अमेरिका अपने निर्धारित समय से काफी आगे चल रहा है। उन्होंने दावा किया है कि 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक अमेरिका और इजरायल ने ईरान के पांच हजार ठिकानों पर हमले किए हैं। श्री ट्रम्प के ईरान के साथ युद्ध जल्द समाप्त होने के बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में करीब पांच प्रतिशत की गिरावट रही और यह 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया। कच्चे तेल का मानक लंदन का ब्रेंट क्रूड वायदा 4.1 प्रतिशत टूटकर 94.20 डॉलर प्रति बैरल पर रहा।

BCCI भारतीय टीम को 131 करोड़ का इनाम देगा

मुंबई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने टी-20 विश्व कप खिताब का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली भारतीय टीम के लिए 131 करोड़ रुपये के नकद इनाम की घोषणा की है। बीसीसीआई ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बीसीसीआई खिलाड़ियों, सपोर्ट स्टाफ और चयनकर्ताओं को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए एक बार फिर बधाई देता है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। रविवार को हुए फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया था। भारत ने रिकॉर्ड तीसरी बार टी-20 विश्व कप जीता।

देश में यूसीसी लागू करने का समय आ गया: सुप्रीम कोर्ट

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने का समय आ गया है। इस पर फैसला करना कोर्ट के बजाय संसद का काम है। सुप्रीम कोर्ट शरीयत कानून 1937 की कुछ धाराओं को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इन धाराओं से मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव का आरोप था।

सीजेआई सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा कि शरीयत कानून की धाराएं रद्द कर दी गईं तो मुस्लिम समुदाय में संपत्ति के बंटवारे को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं बचेगा। इससे कानूनी खालीपन पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी कई बार सरकार से समान नागरिक संहिता लागू करने को कह चुका है। अलग-अलग समुदायों के लिए अलग नियम हैं, लेकिन

कहा: संसद फैसला करे, शरीयत कानून में सुधार की जल्दबाजी न करें, इससे नुकसान की संभावना

एसआईआर पर न्यायिक अधिकारियों के काम में बाधा न हो: कोर्ट

नई दिल्ली। प. बंगाल में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने राज्य सरकार व चुनाव आयोग से कहा है कि न्यायिक अधिकारियों को अपना काम सुचारू रूप से करने के लिए उचित और निर्बाध परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाएं।

तीन जजों की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस आर. महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल थे, ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में तैनात न्यायिक अधिकारियों ने अब तक मतदाता सूची से हटाए जाने के खतरे का सामना

सुप्रीम कोर्ट ने दिए बंगाल सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश

कर रहे लोगों की 10.16 लाख आपत्तियों और दावों पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में कोई भी नया अनिवार्य कदम तब तक लागू न किया जाए, जब तक उसे कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी न मिल जाए। साथ ही अदालत ने निर्देश दिया कि चुनाव आयोग के पोर्टल में आने वाली तकनीकी दिक्कतों को तुरंत दूर किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आगे ऐसी समस्याएं न हों।

इसका मतलब यह नहीं कि हम सीधे किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दें। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कोर्ट यह घोषित कर सकती है कि मुस्लिम महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, अगर शरीयत कानून की कुछ धाराएं रद्द होती हैं, तो ऐसे मामलों में भारतीय उत्तराधिकार कानून लागू किया जा सकता है।

केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस पर लगाया एस्मा

शाह टाइम्स ब्यूरो

नई दिल्ली। सरकार ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आई बाधाओं को देखते हुए देश में रसोई गैस (एलपीजी) का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर आवश्यक वस्तु अधिनियम (एस्मा) लगा दिया है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 के अनुसार, घरेलू पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) की आपूर्ति, परिवहन के लिए सीएनजी की आपूर्ति, एलपीजी उत्पादन, और पाइपलाइन कॉम्प्रेशर फ्यूल तथा अन्य अनिवार्य पाइपलाइन परिचालन जरूरतों को प्राथमिकता सेक्टर-1 में रखा गया है। इन उपभोक्ताओं को पिछले छह महीने की औसत के बराबर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। वहीं अन्य क्षेत्रों के लिए आपूर्ति में कटौती की जाएगी। इस संबंध में जारी गजट अधिसूचना में कहा गया है कि 'पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष' के मद्देनजर वितरण में समानता और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किया गया है। उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता सेक्टर-2 में रखा गया है। उन्हें पिछले छह महीने की औसत के 70 प्रतिशत तक आपूर्ति की जाएगी। साथ ही यह पाबंदी होगी कि वे इसका इस्तेमाल किसी और उद्देश्य के लिए नहीं कर सकेंगे। प्राथमिकता सेक्टर-3 में चाय उद्योग, विनिर्माण संयंत्रों तथा अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं को रखा गया है। वे पिछले छह महीने की औसत के 80 प्रतिशत तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सिटी गैस वितरकों को दी गई है। पेट्रो रसायन संयंत्रों और विद्युत संयंत्रों को भी गैस की आपूर्ति में पूरी तरह या आंशिक तौर पर कटौती की जाएगी। सरकार ने सभी तेल शोधन कंपनियों को एलपीजी का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कहा है, ताकि आम लोगों के लिए इसकी कमी न हो।

देश में रसोई गैस का उत्पादन बढ़ाने की कवायद, उद्योगों को आपूर्ति में होगी कटौती

कोविड वैक्सीन के दुष्प्रभाव पर केंद्र मुआवजा नीति बनाए: SC

नई दिल्ली। कोविड-19 वैक्सीन से जुड़े गंभीर दुष्प्रभावों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा निर्देश दिया है।

अदालत ने कहा कि सरकार ऐसी नीति तैयार करे, जिसके तहत कोविड वैक्सीन लेने के बाद अगर किसी व्यक्ति को गंभीर नुकसान होता है, तो उसे नो-फाल्ट मुआवजा दिया जा सके। यह फैसला जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता

सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ा निर्देश दिया

की बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने कहा कि फिलहाल टीकाकरण के बाद होने वाले दुष्प्रभावों की निगरानी के लिए जो मौजूदा व्यवस्था है, वही जारी रहेगी। इसके लिए किसी नए अदालत द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ पैनल की जरूरत नहीं है।

उत्तराखंड में पहचान छिपाकर शादी करने वालों को अब होगी जेल

शाह टाइम्स ब्यूरो

गैरसैंण। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को और अधिक प्रभावी और सख्त बनाने की दिशा में धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बजट सत्र में पेश होने के बाद अब प्रदेश में समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) अध्यादेश, 2026 लागू हो गया है। उत्तराखंड में अब पहचान छिपाकर शादी करने वालों को जेल होगी।

वहीं, लिव-इन के नियम भी कड़े हो गए हैं। प्रदेश में समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड (संशोधन) अध्यादेश, 2026 लागू हो गया है। यूसीसी को और अधिक प्रभावी और सख्त बनाने की दिशा में धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश को मंजूरी के साथ ही राज्य में विवाह, पंजीकरण और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो गए हैं। अब यदि विवाह का कोई भी पक्षकार अपनी पहचान के विषय में गलत जानकारी देता है तो इसे विवाह शून्य करने का आधार माना जाएगा। इसके साथ ही, अपनी पहचान या वैवाहिक स्थिति छिपाकर शादी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ अब भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।

लिव-इन-रिलेशनशिप को लेकर बेहद कड़े प्रावधान जोड़े

अध्यादेश में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर बेहद कड़े प्रावधान जोड़े गए हैं। यदि कोई व्यक्ति बल, दबाव या धोखाधड़ी के माध्यम से लिव-इन संबंध स्थापित करता है तो उसे सात साल तक के कारावास और जुर्माने की सजा होगी। धारा 380(2) के उल्लंघन जैसे खून के रिश्तों या प्रतिबंधित श्रेणियों में लिव-इन में रहने पर भी सात साल की जेल का प्रावधान है। किसी वयस्क द्वारा नाबालिग के साथ लिव-इन में रहने पर छह माह की जेल और 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा।

उप्र में कर्मचारियों की संपत्ति की वार्षिक घोषणा अनिवार्य हुई

लखनऊ (ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति और निवेश पर सख्ती, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में पारदर्शिता, ग्रामीण परिवहन सेवा का विस्तार तथा आवास योजनाओं से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं। कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्रियों ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की चल-अचल संपत्ति की वार्षिक घोषणा अनिवार्य कर दी है। अब सभी कर्मचारियों को हर वर्ष अपनी संपत्ति का विवरण देना होगा। इसके साथ ही यदि कोई कर्मचारी अपने छह महीने के मूल वेतन से अधिक राशि शेयर या स्टॉक मार्केट में निवेश करता है, तो उसे इसकी जानकारी देनी होगी। ऐसे मामलों में जांच अनिवार्य होगी और दोषी पाए जाने पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से पहले विक्रेता की पहचान और मिल्कियत की पूरी जांच खतौनी के आधार पर की जाएगी। बिना खतौनी सत्यापन के रजिस्ट्री नहीं होगी। विक्रेता के लिए अपनी मिल्कियत खतौनी में दर्ज कराना अनिवार्य होगा। साथ ही स्टाम्प शुल्क सर्किल रेट के आधार पर ही लिया जाएगा और नगर निगम क्षेत्रों में 2 प्रतिशत अतिरिक्त विकास शुल्क भी लगाया जाएगा। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना 2026 को भी मंजूरी दी है।

बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव: 50 से ज्यादा सांसदों ने पक्ष में वोट किया

नई दिल्ली। लोकसभा में मंगलवार को विपक्ष स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया। 50 से ज्यादा सांसदों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इसके बाद पीठासीन ने प्रस्ताव पेश करने की परमिशन दे दी। अब इस प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा होगी।

विपक्ष ने ओम बिरला पर सदन की कार्यवाही में पक्षपात करने का आरोप लगाया है। बहस की शुरुआत कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने की। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान 20 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को रोका-टोका गया। उन्हें बार-बार रूलिंग बुक दिखाई गई। उन्होंने अपनी स्पीच में एक आर्टिकल का हवाला दिया। इस पर उन्हें मना किया गया, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसदों ने भारत में बैन किताबें सदन में दिखाईं। उनसे कुछ नहीं कहा गया। इस तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं है।

लोकसभा में विपक्ष के 50 सांसदों ने प्रस्ताव के समर्थन में खड़े होकर समर्थन किया। गोगोई ने कहा कि बिरला बोलने नहीं देते, माइक बंद किया, 2 फरवरी को नेता विपक्ष राहुल गांधी जब बोल रहे थे, तब उन्हें बार-बार रोका गया। स्पीकर सर ने उनके तर्क पर सबूत देने को कहा। 9 फरवरी को

मोदी सरकार ने छीन ली है लोकसभा अध्यक्ष की आजादी : प्रियंका

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि मोदी सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष नाम की संस्था की आजादी खत्म कर दी है, लेकिन विपक्ष उसे बचाने में लगा है। उन्होंने कहा कि इसी मसले पर व्यापक चर्चा के मकसद से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। श्रीमती वाड्रा ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि मोदी सरकार ने अध्यक्ष की स्वतंत्रता छीन ली है। ये लोग हर संस्था को खत्म करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि हम हर उस संस्था को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जिनके ऊपर भारत का लोकतंत्र टिका हुआ है। भाजपा के लोगों को यही बातें पचती नहीं हैं, इसलिए वे सदन को मुद्दों से भटकाने की कोशिश करते हैं। मेरी दादी इंदिरा जी कहती थीं कि कोई नकली बनने की कोशिश करे या झूठी इमेज दिखाए, देश की जनता उसकी सच्चाई जान ही जाएगी।

गोगोई बोले- राहुल गांधी को 20 बार टोका गया, रिजिजू का जवाब- प्रियंका को नेता प्रतिपक्ष बनाते, तो अच्छा होता

शशि थरूर जब बोल रहे थे, तब उनका माइक बंद कर दिया गया। सरकार ने कहा कि बोलिए, लेकिन हम कैसे बोल सकते हैं जब माइक ऑफ किया गया हो। संसद में ऐसी नई-नई चीजें हो रही हैं। आज महिला सांसदों के उद्देश्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ओम बिरला जी ने पीएम मोदी के समय कहा था कि महिला सांसदों ने पीएम की चेयर घेर ली है।

संक्षिप्त समाचार

ईरान-इजरायल युद्ध की आंच में तपा संगमरमर उद्योग

आगरा। मध्य पूर्व में जारी ईरान-इजरायल युद्ध का असर अब आगरा के संगमरमर हथकरघा उद्योग पर भी पड़ने लगा है। मध्य-पूर्वी देशों के ग्राहकों ने करोड़ों रुपये के ऑर्डर फिलहाल रोक दिए हैं, जिससे आगरा का मार्बल हैंडीक्राफ्ट कारोबार लगभग ठप पड़ गया है। कारोबारियों के अनुसार फैक्टरियों में काम बंद होने की स्थिति बन गई है और हजारों कारीगरों व मजदूरों को काम मिलना बंद हो गया है। आगरा से हर साल करोड़ों रुपये का मार्बल हैंडीक्राफ्ट माल निर्यात किया जाता है, जिसका बड़ा बाजार मध्य-पूर्वी देशों में रहा है। व्यापारियों का कहना है कि इन देशों के बड़े कारोबारी आगरा से बड़ी मात्रा में मार्बल हैंडीक्राफ्ट मंगाते रहे हैं, लेकिन युद्ध की स्थिति के कारण नए ऑर्डर मिलने बंद हो गए हैं। साथ ही पहले से मिले कई ऑर्डर भी फिलहाल रोक दिए गए हैं, जिससे अधूरे तैयार माल में कारोबारियों के करोड़ों रुपये फंसे हुए हैं।

मदुरै एयरपोर्ट को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु के मदुरै एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक के बाद बताया कि चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरै तमिलनाडु के तीन बड़े शहर हैं। लंबे समय से स्थानीय लोग मदुरै एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। यह पुराना सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक केंद्र है। इस फैसले के बाद वहां विकास को और गति मिलेगी।

लाल बत्तियों के बंदरबांट की अटकलों फिलहाल अभी लगा विराम

उप्र में अभी और लंबा खिचेगा मंत्रिमंडल विस्तार

लखनऊ, वार्ता

पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद ही लिया जाएगा निर्णय

उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच फिलहाल इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां तत्काल विस्तार के पक्ष में नजर नहीं आ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु सहित पांच राज्यों के आगामी विधानसभा चुनावों के बाद ही योगी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार पर निर्णय ले सकती है।

सूत्रों के मुताबिक इससे पहले बिहार में नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण की प्रक्रिया भी पूरी होनी है। इसके बाद ही उत्तर प्रदेश में टीम योगी में बदलाव या विस्तार की संभावना जताई जा रही है। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और संगठन इन राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार कुछ समय के लिए टल सकता है। गौरतलब है कि वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव से करीब छह महीने पहले 26 सितम्बर 2021 को भी योगी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार किया गया था। उस समय कुल सात मंत्रियों ने शपथ ली थी। इनमें जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, जबकि पल्टू राम, संजय कुमार गौड, संगीता बलवंत बिंद, धर्मवीर प्रजापति, दिनेश खटीक और छत्रपाल सिंह गंगवार को राज्य मंत्री बनाया गया था। वर्तमान में मुख्यमंत्री सहित योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कुल 53 मंत्री शपथ ले चुके हैं। इनमें से कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद अब केंद्र सरकार में मंत्री बन चुके हैं, जबकि राज्य मंत्री अनूप प्रधान वाल्मीकि लोकसभा सदस्य बन गए हैं। इस कारण मंत्रिमंडल में दो पद खाली हो गए हैं। विधायकों की संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश में अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में अभी भी मंत्रिमंडल में नौ पद रिक्त हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भाजपा नेतृत्व इन पदों को भरने पर फैसला करेगा। पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल का विस्तार बंगाल चुनाव के बाद ही होने की संभावना है। केंद्रीय नेतृत्व की व्यस्तता के चलते फिलहाल ऐसी स्थितियां बनती नहीं दिख रही हैं। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ताओं की नजर मंत्रिमंडल विस्तार पर लंबे समय से टिकी हुई है। कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी उत्सुकता से लंबे समय से इसका वहीं की राजनीति में ब्राह्मण समाज एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है।

ब्राह्मण व सवर्ण समाज की नाराजगी अंडरकंट के रूप में उभर सकती है, भाजपा भयभीत

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ब्राह्मण वोट बैंक और यूजीसी मुद्दे को लेकर सवर्ण समाज की नाराजगी राज्य की राजनीति में एक अहम अंडरकरंट के रूप में उभर सकता है और इसका खामियाजा सत्तारूढ़ पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। प्रदेश की कुल आबादी में लगभग 10 से 12 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाला ब्राह्मण समाज कई विधानसभा क्षेत्रों में निर्णायक प्रभाव रखता है। ऐसे में सभी प्रमुख राजनीतिक दल इस वर्ग को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हाल के कुछ घटनाक्रमों ने यह बहस तेज कर दी है कि समुदाय के कुछ वर्गों में सनातन भारतीय जनता पार्टी के प्रति असंतोष की भावना है, हालांकि भाजपा नेताओं ने ऐसे दावों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है।

मिडिल ईस्ट में युद्ध की धमक वेस्ट यूपी तक पहुंची

शाह टाइम्स ब्यूरो

मेरठ/ मुजफ्फरनगर। अमेरिका- इजरायल और ईरान के बीच युद्ध के चलते मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, सहारनपुर और शामली में तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। पेट्रोलियम उत्पाद, गैस और कच्चे माल के दाम दोगुना हो गए हैं। ऐसे में घर की रसोई से लेकर इन जिलों के लाखों उद्योग प्रभावित हो रहे हैं।

होटल, रेस्टोरेंट, विवाह आयोजनों में भी गैस की किल्लत बनी हुई है। मेरठ में गृहिणी सुनीता ने बताया कि बुकिंग कराने के बाद भी गैस मिलने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा मेरठ की गढ़ रोड समेत कई एजेंसियों पर गैस के लिए लोग परेशान दिखे। ब्रेवुरा होटल के संचालक शेखर भल्ला ने बताया कि जिन होटलों में पीएनजी है, वहां भी लाइव स्टाल लगाने के लिए सिलेंडर नहीं हैं। होटल, रेस्टोरेंट के अलावा सर्वाधिक दिक्कत कैटरिंग वालों के सामने आ रही है। मेरठ होटलियर्स एंड रेस्टूरेंट एसोसिएशन के महामंत्री विपुल सिंघल ने बताया कि सिलेंडर की कमी के चलते पकौड़ी की दुकान से लेकर बड़े होटलों तक में दिक्कत हो रही है। सरकार ने घरेलू गैस सिलिंडर के दाम तो बढ़ा दिए हैं, इसके साथ ही कमर्शियल सिलिंडर के दाम भी बढ़े हैं। सहारनपुर में होटल एवं रेस्टोरेंट में पाइप के जरिए सप्लाई होने वाली गैस आपूर्ति को बंद कर दिया गया है। बता दें, कि जिले में 8.33 लाख गैस उपभोक्ता हैं। हर दिन औसतन 17 हजार गैस सिलिंडर की बुकिंग की जाती है। जनपद में गैस एजेंसी की 61 शाखाएं हैं। सरकार ने 21 दिन की अवधि को बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। अब गैस उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग के लिए 25 दोनों का इंतजार करना होगा। इसके बाद ही सिलेंडरों की आपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा कई उपभोक्ताओं ने बताया कि गैस बुकिंग करने के चार से पांच दिन बाद भी सिलिंडर की डिलीवरी घर पर नहीं हो पा रही है। शामली में

मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली, बागपत और सहारनपुर में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति हो रही प्रभावित

व्यावसायिक गैस सिलिंडरों की आपूर्ति तीन दिन से प्रभावित है। इससे होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकान करने वालों के सामने संकट खड़ा हो गया है। कुछ के पास पुराना स्टाक बचा है, जबकि कुछ का खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल के मंडल अध्यक्ष धनश्याम दास गर्ग ने मामले को लेकर जिलाधिकारी से मिलने की बात कही है।

मुजफ्फरनगर जिले में करीब छह लाख घरेलू गैस उपभोक्ता हैं। फिलहाल गैस आपूर्ति की कोई दिक्कत नहीं है। आईजीएल की ओर से पीएनजी सप्लाई की जाती है, लेकिन यह सप्लाई भीच ल रही है। बागपत में कामर्शियल गैस सिलिंडर की आपूर्ति रोक दी गई है। घरेलू गैस सिलिंडर की आपूर्ति सामान्य रखने के लिए ऐसा किया गया है। जिले में हर महीने कामर्शियल दो हजार सिलिंडर की आपूर्ति है। इसके अलावा सिलिंडर बुकर करने का समय निर्धारित करने के कारण अब एजेंसी पर सिलिंडर की गाड़ी रोज़ाना की जगह एक दिन बाद आ रही है। बिजनौर में घरेलू गैस सिलिंडर की डिमांड बढ़ गई है और लोग आने वाले दिनों में समस्या को देखते हुए अतिरिक्त सिलिंडर की व्यवस्था करने में लगे हैं।

ट्रम्प के सामने नतमस्तक हैं पीएम मोदी: केजरीवाल

नई दिल्ली, वार्ता

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह अपनी किसी मजबूरी के कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के सामने नतमस्तक हैं और देश उसी की सजा भुगत रहा है।

केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर मंगलवार को कहा कि देश भर में, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों को छोड़कर बाकी सभी व्यावसायिक संस्थानों को एलपीजी की कोई कमी नहीं। आज सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम लगाकर गैस कंट्रोल कर रही है। रिफाइनरियों को गैस डायवर्ट करने के आदेश दे रही है और घरेलू सिलेंडर की बुकिंग भी 25 दिन कर दी गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि सूत्र झूठ बोल रहे थे या सरकार? पश्चिम एशिया का युद्ध अब भारत की रसोई और रोजगार तक पहुंच चुका है। आज ढाबे, होटल, छोटे रेस्टोरेंट और लाखों छोटे कारोबार कमर्शियल गैस की कमी से जूझ रहे हैं।

भुगत रहा है? दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि चार दिन पहले तक 'सरकारी सूत्र' कह रहे थे- देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं। आज सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम लगाकर गैस कंट्रोल कर रही है। रिफाइनरियों को गैस डायवर्ट करने के आदेश दे रही है और घरेलू सिलेंडर की बुकिंग भी 25 दिन कर दी गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि सूत्र झूठ बोल रहे थे या सरकार? पश्चिम एशिया का युद्ध अब भारत की रसोई और रोजगार तक पहुंच चुका है। आज ढाबे, होटल, छोटे रेस्टोरेंट और लाखों छोटे कारोबार कमर्शियल गैस की कमी से जूझ रहे हैं। क्या आज देश उसी की सजा

भाजपा सरकार में किसानों को कृषि लागत भी नहीं मिल रही: अखिलेश

शाह टाइम्स ब्यूरो

भाजपा के नेता चुनाव प्रचार के लिए तो उपलब्ध रहते हैं, लेकिन किसानों की परेशानी और दिक्कतों के लिए उनके पास समय नहीं है

लखनऊ। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाजार में आलू के गिरते दाम को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आलू के दाम गिरने से किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गए हैं, लेकिन किसान और खेती विरोधी भाजपा सरकार पूरी तरह लाप. रवाह होकर बैठी है और किसानों की मांगों की अनदेखी कर रही है।

यादव ने मंगलवार को एक्स पर लिखा, भाजपा को सिर्फ अपनी राजनीतिक सत्ता से मतलब है। भाजपा के नेता चुनाव प्रचार के लिए तो उपलब्ध रहते हैं, लेकिन किसानों की परेशानी और दिक्कतों के लिए उनके पास समय नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा का पूरा खेल ही यही है कि पैदावार के दाम इतने कम करवा दो कि किसानों की लागत तक न निकले। वो थक-हार कर खेतीबाड़ी का काम ही छोड़ दें और अपनी जमीनें भाजपा के समर्थक अमीरों को कौड़ियों के दाम बेचने पर मजबूर हो जाएं।

फिर ए भाजपाई पैसेवाले, किसान को उसके अपने खेत में ही मालिक से मजदूर बना दें। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपाइयों की साजिश ही ये है कि वो किसानों की जमीन हड़प कर बड़े स्तर पर खेती करके खाद्यान्न और फसलों की पैदावार को अपने हाथों में ले लें और फिर मनमानी कीमत जनता से वसूलें। इसीलिए भाजपा की भ्र्-अधिग्रहण बिल लाती है, कभी तीन कृषि काले कानून या फिर भारत की खेती-किसानों के लिए प्राणघातक अमेरिकी डील करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि यही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब कि आज के खेत का मालिक किसान, कल को अपने ही खेत की पैदावार को खरीदने पर मजबूर हो जाएगा। भाजपा दल नहीं दलाल है।

काम कोर्स उदास क्यों?
अधिक संतुष्टि, हैरतअंगेज़ पावर, शीघ्रपतन, नपुंसकता, बवंधन की गलतियों से हमेशा के लिए छुटकारा।
फोन कर घर बैठे औषधियां डाक द्वारा प्राप्त करें।
ऋषि इन्टरनेशनल
08899787114
09808917010

स्त्री के सामने लज्जित होने से बेहतर है
आज ही इलाज करा लेना खोई हुई मर्दाना ताकत दोबारा प्राप्त करने के लिए आज ही मिलें या फोन करें।
काजीजादा, अमरोहा-UP
हाशमी दवाखाना
9997161320, 8272800800

Cipzer
— HEALTH WITH CARE —
जॉन्डिस क्योर
लिवर का जिगरी दोस्त
भूख की कमी, बदहज़मी जॉन्डिस, फैटी लीवर, एल्कोहलिक लिवर डिजीज़ आदि से लड़ने की ताकत देता है ताकि आप रहें फिट एण्ड एक्टिव
प्रमुख मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध!
86 8484 5757 info@cipzer.com

अर्थ व्यापार

सेंसेक्स 78205.98
निफ्टी 24261.60

सोना 159409
प्रति 10 ग्राम (24 कैरेट)

चांदी रु. 263210
प्रति किलो

गिरावट से उबरे शेयर बाजार सेंसेक्स 640 अंक मजबूत

मुंबई, वार्ता

घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को तेजी लौट आई और बीएसई का सेंसेक्स 639.82 अंक (0.82 फीसदी) चढ़कर 78,205.98 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी 233.55 अंक यानी 0.97 प्रतिशत ऊपर 24,261.60 अंक पर पहुंच गया। गत 26 फरवरी के बाद छह कारोबारी दिवस में दोनों प्रमुख सूचकांक 5.7 प्रतिशत टूट गए थे। इस दौरान सिर्फ एक दिन बाजार में तेजी रही थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ईरान युद्ध जल्द समाप्त होने संबंधी बयान के बाद वैश्विक स्तर पर सभी शेयर बाजारों में तेजी देखी गई।

घरेलू शेयर बाजारों पर भी इसका असर दिखा। मझौली और छोटी कंपनियों में ज्यादा लिवाली रही। निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.60 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 2.12 प्रतिशत की बढ़त में रहा। आईटी और तेल एवं गैस को छोड़कर अन्य सभी सेक्टरों में तेजी रही। ऑटो, वित्त, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद, बैंकिंग, रियलिटी, फार्मा, धातु, मीडिया और रसायन समूहों में लिवाली ज्यादा रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा और इंडिगो के शेयर साढ़े तीन प्रतिशत के आसपास मजबूत हुए। मारुति सुजुकी, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील और एक्सिस बैंक के शेयर दो से तीन प्रतिशत के बीच चढ़े। कोटक महिंद्रा बैंक, टाइटन, बजाज फिनसर्व, बीईएल, भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और पावर ग्रिड के शेयर एक प्रतिशत से अधिक की बढ़त में रहे। आईटीसी, एलएंडटी, ट्रेंट और सन फार्मा को शेयर भी हरे निशान में रहे। इटरनल और इंफोसिस के शेयर करीब डेढ़ फीसदी टूट गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर भी एक प्रतिशत से अधिक गिर गए। भारती एयरटेल और टीसीएस में भी गिरावट रही।

कच्चा तेल टूटा 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे पहुंचा

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ईरान के साथ युद्ध जल्द समाप्त होने के बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में करीब पांच प्रतिशत की गिरावट रही और यह 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया। कच्चे तेल का मानक लंदन का ब्रेंट क्रूड वायदा 4.1 प्रतिशत टूटकर 94.20 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। अमेरिकी वेस्ट टेक्सस क्रूड 4.89 प्रतिशत उतरकर 90.3 डॉलर प्रति बैरल बोला गया।

इससे पहले सोमवार को कच्चे तेल में जबरदस्त तेजी देखी गई थी और एक समय यह 119 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया था। अमे. रिका और इजरायल द्वारा 28 फरवरी को एक संयुक्त सैन्य अभियान में ईरान पर किए गए हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। ईरान पर हमले और उसकी जवाबी प्रतिक्रिया के कारण पश्चिमी एशिया में इन दोनों गंभीर धू राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। इससे कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति और उत्पादन दोनों बाधित हुए हैं।

चावल नरम, गेहूं मजबूत, दालों और खाद्य तेलों में रही घट-बढ़

नई दिल्ली, वार्ता

घरेलू थोक जिंस बाजारों में मंगलवार को चावल के औसत भाव टूट गए। वहीं गेहूं में तेजी रही। चीनी के भाव कमोबेश स्थिर रहे, जबकि दालों और खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा। औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत नौ रुपये घटकर 3,847 रुपये प्रति क्विंटल रह गई। गेहूं तीन रुपये महंगा हुआ और 2,813 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा।

आटे के भाव में टिकाव रहा। दाल-दलहनों में तुअर दाल औसतन 32 रुपये प्रति क्विंटल सस्ती हुई। मसूर दाल की कीमत 22 रुपये और चना दाल की 20 रुपये घट गई। मूंग दाल में नौ रुपये की गिरावट रही। वहीं उड़द दाल दो रुपये प्रति क्विंटल मजबूत हुई। विदेशों में मलेशिया के बुरसा मलेशिया डेरिवेटिव एक्सचेंज में पाम ऑयल का मई वायदा 139 रिंगिट फिसलकर 4,428 रिंगिट प्रति टन रह गया। मई का अमे. रिकी सोया तेल वायदा 0.12 प्रतिशत की बढ़त में 66.18 सेंट प्रति पौंड बोला गया। स्थानीय बाजारों में सूरजमुखी तेल 73 रुपये और पाम ऑयल 63 रुपये प्रति क्विंटल महंगा हुआ।

मूंगफली तेल की कीमत 39 रुपये बढ़ी। सरसों तेल और सोया तेल आठ-आठ रुपये मजबूत हुए। वनस्पति 16 रुपये प्रति क्विंटल फिसल गया। मीठे के बाजार में आज गुड़ का औसत भाव सात रुपये प्रति क्विंटल टूट गया। चीनी की कीमत कमोब. श अपरिवर्तित रही।

आईजीआरएस रिपोर्ट में रामपुर अव्वल शाहजहांपुर-बाराबंकी दूसरे स्थान पर

शाह टाइम्स ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शिकायतों के त्वरित निस्तारण और विकास कार्यों की निगरानी के लिए लागू एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) की फरवरी माह की रिपोर्ट में रामपुर जिले ने शत-प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। शाहजहांपुर और बारा. बंकी ने बराबर अंक प्राप्त कर संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया है, जबकि जालौन तीसरे स्थान पर है। आईजीआरएस के माध्यम से प्रदेश के जिलों में जन शिकायतों, राजस्व मामलों और विकास कार्यों की नियमित निगरानी की जाती है।

हर माह 49 विभागों के 109 कार्यक्रमों की विभिन्न मानकों के आधार पर समीक्षा कर जिलों की रैंकिंग जारी की जाती है। फरवरी की रिपोर्ट में रामपुर ने निर्धारित 140 में से पूरे 140 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि आईजीआरएस रिपोर्ट प्रशासनिक दक्षता, विकास कार्यों की गुणवत्ता और राजस्व प्रबंधन के आधार पर जिलों के प्रदर्शन का आकलन करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप जिले में विकास कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप रामपुर को आईजीआरएस और सीएम डैशबोर्ड दोनों में पहला स्थान मिला है। शाहजहांपुर के जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जिले में विकास परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाती है और जन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के संतुष्टिपूर्ण फीडबैक के आधार पर ही आईजीआरएस रिपोर्ट तैयार होती है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। रिपोर्ट के अनुसार शाहजहांपुर और बारा. बंकी ने 137-137 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि जालौन ने 136 अंक के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। बरेली, श्रावस्ती और हाथरस ने 135-135 अंक हासिल कर चौथा स्थान प्राप्त किया। वहीं बलिया, आजमगढ़ और भदोही ने 134 अंक प्राप्त कर पांचवें स्थान पर जगह बनाई। टॉप-10 जिलों में अंबेडकरनगर, प्रयागराज, कन्नौज, पीलीभीत और हमीरपुर भी शामिल हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार आईजीआरएस की नियमित निगरानी से विकास कार्यों में तेजी आई है और जन शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी और पारदर्शी हुई है।

राजनीतिक रोटी सेंकने को लाया गया अविश्वास प्रस्ताव: रिजिजू

नई दिल्ली, वार्ता

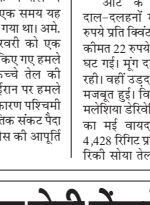

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को राजनीतिक रोटी सेंकने का प्रयास बताते हुए कहा कि सदन के अंदर के क्रियाकलापों के लिए हर सदस्य श्री बिरला को धन्यवाद देता रहेगा, क्योंकि उन्होंने सभी को समान मौका दिया है।

रिजिजू ने विपक्ष की ओर से सदन में पेश अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के विरोध में अपनी बात रखते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री सिर्फ सत्तारूढ़ दल का नहीं होता है। कांग्रेस के साठ साल के इतिहास को देखना चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री पर टिप्पणी करने से पहले अपना इतिहास देखना चाहिए। सदन के संचालन का पूरा अधिकार अध्यक्ष का है। अध्यक्ष के निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। अध्यक्ष के निर्णय को किसी ने आज तक चुनौती नहीं दी है लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि सदन में बोलने के लिए उन्हें किसी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि सदन में अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि चाहे वह प्रधानमंत्री हों, विपक्ष के नेता हों या कोई अन्य सांसद, लेकिन अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन में कोई नहीं बोल सकता है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष किसी को कभी भी बोलने की अनुमति दे सकता है यह उनका अधिकार है। अध्यक्ष के पास कुछ शक्तियां ऐसी हैं, जो कार्यसूची में शामिल नहीं हैं। संसदीय परंपरा में कई चीजें पहली बार होती है तब भी अध्यक्ष को निर्णय लेना होता है। अध्यक्ष की भूमिका भी विपक्ष तय करना चाहते हैं, यह कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि जो नियम में शामिल नहीं है, तो उस पर निर्णय करने की शक्ति भी अध्यक्ष के पास होता है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि भाजपा के नेताओं ने कभी कागज फाड़कर आसन की तरफ नहीं फेंका है। 1951 के बाद भाजपा के किसी सदस्य ने आसन की तरफ कागज फाड़कर नहीं फेंका है, लेकिन विपक्ष आज सारी सीमाओं का लांघने का काम कर रहा है।

बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर रास में हंगामा

नई दिल्ली। विपक्षी दलों ने राज्यसभा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में अनियमित. ताओं का मुद्दा एक बार फिर उठाते हुए मंगलवार को जोरदार हंगामा किया और इस पर चर्चा करने की मांग नहीं मानने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया।

तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि नेता सदन जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को विपक्ष का नाम लेकर सदन में एसआईआर का मुद्दा उठाया था। तृणमूल सदस्य ने कहा कि पश्चिम बंगाल में अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वह सही नहीं है और इसमें हो रही अनियमितताओं पर सदन में चर्चा कराई जानी चाहिए। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी श्री ओ' ब्रायन का समर्थन करते

चर्चा नहीं किए जाने पर विपक्ष का बहिर्गमन

हुए कहा कि सदस्य ने महत्वपूर्ण विषय उठाया है और राज्यों में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है वह सही नहीं है। उन्होंने भी इस मुद्दे पर सदन में चर्चा करने की मांग की।

सभापति ने कहा कि वह विपक्ष के सदस्यों को कई बार इस विषय पर बात करने का अवसर दे चुके हैं लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने इसका फायदा नहीं उठाया है। सदस्यों के नियम 267 के तहत उठाए गए मुद्दों पर उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में कई बार आसन की ओर से व्यवस्था पहले ही दी जा चुकी है। इस बीच कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्ष के अनेक सदस्य आसन के निकट आकर एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा के लिए नारेबाजी करते रहे।

सदन में गूंजा मानव-वन्य जीव संघर्ष का मुद्दा

■ बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान जमकर हुई चर्चा

शाह टाइम्स ब्यूरो

गैरसैंण। उत्तराखंड की गीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान वन विभाग से जुड़े मुद्दों पर जमकर चर्चा हुई। मानव-वन्य जीव संघर्ष, मुआवजा, रोपवे परियोजना और वन कानूनों को लेकर सत्ता और विपक्ष दोनों के विधायकों ने वन मंत्री सुबोध से तीखे सवाल किए।

प्रश्नकाल की शुरुआत होते ही वन विभाग से जुड़े मुद्दों पर सदन में गरमागरम बहस देखने को मिली। अधिकांश सवाल वन मंत्री सुबोध उनियाल से पूछे गए, जिनमें मानव-वन्य जीव संघर्ष, फॉरेस्ट क्लीयरेंस, जंगली जानवरों से फसल नुकसान और रोपवे परियोजनाओं जैसे विषय शामिल रहे।

सबसे पहले डोईवाला के भाजपा विधायक बृजभूषण गैरोला ने प्रदेश में बढ़ते मानव-वन्य जीव संघर्ष का मुद्दा उठाया और वन मंत्री सुबोध उनियाल से सवाल किया.

उन्होंने पूछा कि वन्य जीवों के हमलों से अब तक कितने लोग प्रभावित हुए हैं और सरकार सुरक्षा के लिए क्या कदम उठा रही है?

साथ ही प्रभावित लोगों को मिलने वाले मुआवजे और उसमें होने वाली देरी पर भी सवाल किया गया। जवाब में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने सदन को बताया कि वर्ष 2000 से 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश में मानव-वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में 1296 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6624 लोग घायल हुए हैं। मंत्री ने बताया कि सरकार ने ऐसे मामलों में मुआवजे की राशि बढ़ाई है और मृतकों के परिजनों को अब 10 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है. हालांकि मुआवजा वितरण में देरी को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने सरकार को घेरा। इसी दौरान यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने यमुनोत्री-खरसाली रोपवे परियोजना को लेकर सवाल उठाया. इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि परियोजना के लिए नई कंपनी को टेंडर दिया गया है और जल्द ही काम को आगे बढ़ाया जाएगा। वहीं भाजपा विधायक खजान दास ने वन कानूनों को लेकर सरकार से सवाल किया. उन्होंने कहा कि क्या देश के अलग-अलग राज्यों में वन कानून अलग-अलग तरह से लागू होते हैं और उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश का जिक्र किया. इस पर सदन में कांग्रेस विधायकों ने भी चुटकी ली।

खजान दास ने यह भी पूछा कि उत्तराखंड में सड़कों से जुड़े कई प्रोजेक्ट वर्षों तक फॉरेस्ट क्लीयरेंस के कारण क्यों अटके रहते हैं? इसके जवाब में वन मंत्री ने कहा कि पिछले कुछ समय में फॉरेस्ट क्लीयरेंस की प्रक्रिया में तेजी आई है. सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले साल चॅक, पेयजल और विद्युत सहित छह विभागों से जुड़े 713 प्रकरणों में स्वीकृति दी गई है।

सदन में पहाड़ी क्षेत्रों में जंगली जानवरों से कृषि को हो रहे नुकसान का मुद्दा भी जोर-शोर से उठा. विधायक खजान दास, महेश जीना और विनोद कंडारी ने इस विषय पर सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की और कहा कि जंगली जानवरों से फसलें बर्बाद हो रही हैं, जिससे ग्रामीणों की आजीविका प्रभावित हो रही है। वहीं वन (संरक्षण) अधिनियम और वनों से जुड़े स्थानीय लोगों के हक-हकूक को लेकर भी सदन में बहस हुई. इस दौरान भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सरकार से पॉइंटेड सवाल पूछे. मंत्री की ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। स्पीकर ऋतु खंडूड़ी ने वन मंत्री से कहा कि यह प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं. इसलिए इन पर गंभीरता के साथ स्पष्ट जवाब दिया जाए. खास बात यह रही कि आज केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के वरिष्ठ विधायक खजान दास, विनोद चमोली और मुन्ना सिंह चौहान भी कई मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगते नजर आए. सवालों की बौछार के बीच वन मंत्री सुबोध उनियाल को कई बार स्पष्टीकरण देना पड़ा, जिससे प्रश्नकाल के दौरान सदन का माहौल काफी गर्म रहा।

वन्य जीवों से नुकसान पर मुआवजे का दायरा बढ़ा

शाह टाइम्स ब्यूरो

■ भालुओं से फसल चौपट होने के मामलों में भी मुआवजे पर सरकार गंभीर
■ मकान को क्षति पहुंचने पर मुआवजे का पहले ही हो चुका है निर्णय
■ ततैंया और मधुमक्खी के काटने पर भी अब मिल रहा है मुआवजा

देहरादून। वन्य जीवों से होने वाले कई तरह के नुकसान पर अभी तक मुआवजे की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन धामी सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेकर लोगों को राहत प्रदान की है। राहत देने के लिए सरकार के प्रयास अभी थमे नहीं हैं। अब धामी सरकार भालुओं से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान को भी मुआवजे के दायरे में लाने की कोशिश में जुटी है। भालुओं से मकान-भवनों को होने वाले नुकसान पर धामी सरकार पहले ही मुआवजे की व्यवस्था कर चुकी है।

धामी सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में वन्य जीवों से लोगों के नुकसान पर मुआवजे को लेकर गंभीरता दिखाई है। वन्य जीवों के हमले से मौत पर मिलने वाले मुआवजे को छह लाख करना बेहद अहम फैसला रहा है। पहले ऐसे मामलों में चार लाख मुआवजा दिया जा रहा था। इसी तरह, ततैंया, मधुमक्खी के हमले में भी मुआवजे की सरकार ने व्यवस्था की है। बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि भालुओं के व्यवहार में आए परिवर्तन और इससे हो रहे नुकसान पर भी सरकार की निगाह है। इसी लिए, भारतीय वन्य जीव संस्थान को इस विषय पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार जरूरी कदम उठाएगी। उनियाल ने जानकारी दी कि भालुओं से फसल के नुकसान पर मुआवजा देने के संबंध में भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।

राज्य सरकार ने एक वर्ष में पांच करोड़ से ज्यादा का पिरूल खरीदा

शाह टाइम्स ब्यूरो

■ वनाग्नि रोकने के गंभीर प्रयासों से बढ़ी उम्मीदें
■ पहली बार मिला फायर वाचर्स को सुरक्षा कवच, दस लाख का सामूहिक बीमा
■ प्रधानों की अध्यक्षता में कमेटी ग्राम पंचायत को 30 हजार की प्रोत्साहन राशि

देहरादून। प्रदेश में वनाग्नि को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिन गंभीर प्रयासों को शुरू किया गया है, उनसे सार्थक परिणामों की उम्मीदें बढ़ रही हैं। सरकार ने वन विभाग के माध्यम से एक वर्ष के भीतर ग्रामीणों से पांच करोड़ 42 लाख रूपये का पिरूल खरीदा है। चीड़ के जंगलों में आग लगने के मूल कारण को खत्म करने के लिए ग्रामीणों से वर्ष 2025 में 5532 टन पिरूल खरीदा गया है। इस लक्ष्य को अब बढ़ाकर 8555 टन कर दिया गया है। सरकार की ये ही मंशा है कि पिरुल एकत्रित कर आग की आशंका को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा दिया जाए।

वनाग्नि को रोकने के लिए धामी सरकार के प्रयासों में जनजागरूकता पर भी फोकस किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर 1239 जागरूकता कैंप लगाए गए हैं। सबसे अहम काम सरकार ने यह किया है कि ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी गठित की है, जो विभाग के साथ मिलकर जंगल बचाने में जुट रही हैं। इसके लिए संबंधित ग्राम पंचायत को 30 हजार रूपये प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। मंगलवार को बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने यह जानकारी साझा कीं।

फायर वाचर्स की धामी सरकार ने की चिंता

वनाग्नि के दौरान फायर वाचर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए धामी सरकार ने पहली बार बीमे का सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया है। फायर वाचर्स का दस लाख का सामूहिक बीमा किया गया है। 5600 फायर वाचर्स ने पिछले वर्ष वनाग्नि रोकने में अपना योगदान दिया था।

नन्दादेवी राजजात के लिए 109 करोड़ स्वीकृत: महाराज

शाह टाइम्स प्रमुख संवाददाता

■ संस्कृति मंत्री ने सदन को बताया कि यात्रा को सुगम व सुव्यवस्थित बनाने के लिए चल रही हैं तैयारियां

देहरादून/ गैरसैंण। प्रदेश के पर्यटन, धर्मस्व, संस्कृति, लोक निर्माण, सिंचाई, पंचायतीराज, ग्रामीण निर्माण एवं जलागम मंत्री सतपाल महाराज ने भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा के प्रथम सत्र 2026 के दूसरे दिन सदन में विधान सभा सदस्य बृजभूषण गैरोला की और से पूछे गए तारांकित प्रश्न के जवाब में कहा कि हिमायली कुंभ के नाम से प्रसिद्ध श्री नंदादेवी राजयात्रा जिसका प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजन होता है। उससे सम्बन्धित सभी तैयारियां विभिन्न स्तरों से की जा रही हैं।

धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने सदन को बताया कि नदादेवी राजजात यात्रा को सुगम व सुव्यवस्थित बनाने के लिए मुख्य विकास अधिकारी चमोली को यात्रा अधिकारी नामित किया गया है। जिलाधिकारी चमोली द्वारा नन्दादेवी राजजात यात्रा की तैयारियों हेतु प्रभागीय वनाधिकारी बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर तथा उप जिलाधिकारी चमोली, कर्णप्रयाग एवं थराली को जोनल मजिस्ट्रेट नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक पड़ाव के लिए भी पड़ाव अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है।

महाराज ने पूछे गये प्रश्न के उत्तर में सदन को यह भी बताया कि नन्दादेवी राजजात यात्रा के लिए वर्तमान तक सम्बन्धित विभिन्न विभागों द्वारा 48 कार्यों हेतु कुल रू0 109.65 करोड़ (रू० एक सौ नौ करोड़ पैंसठ लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसके क्रम में सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने स्तर से कार्य करवाये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र 19 अक्टूबर 2025 द्वारा भी नन्दादेवी राजजात यात्रा की तैयारियों के अन्तर्गत विभिन्न आवश्यक लघु प्रकृति के कार्यों के शीघ्र सम्पादन हेतु जिलाधिकारी चमोली को 20.00 करोड़ (बीस करोड मात्र) की धनराशि निर्गत की गयी है। जिसके सापेक्ष आस्था पथ से लेकर विभिन्न यात्रा पड़ावों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा एवं अन्य व्यवस्थाओं हेतु सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने स्तर से कार्यवाही की जा रही है।

उत्तराखंड में हर परिवार की होगी अलग आईडी

शाह टाइम्स ब्यूरो

■ देवभूमि परिवार आईडी में होगा मुखिया के तौर पर परिवार की वरिष्ठतम महिला सदस्य का नाम

गैरसैंण। कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभार्थियों तक पारदर्शी तरीके से सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने मंगलवार को "देवभूमि परिवार विधेयक-2026" को सदन पटल पर रख दिया है। इस विधेयक के कानून बन जाने पर प्रदेश में एकीकृत और सत्यापित परिवार-आधारित डेटाबेस "देवभूमि परिवार" की स्थापना हो सकेगी।

विधेयक का उद्देश्य विभिन्न विभागों में बिखरे लाभार्थी डेटा को एक मंच पर लाकर योजनाओं के संचालन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समन्वित बनाना है।

देवभूमि परिवार आईडी में मुखिया के तौर पर परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की वरिष्ठतम महिला सदस्य का नाम दर्ज होगा। वर्तमान में राज्य के अलग-अलग विभाग अपनी-अपनी योजनाओं के लिए अलग लाभार्थी डेटाबेस का उपयोग करते हैं।

इसके कारण कई बार लाभार्थी आंकड़ों का दोहराव, पुनः सत्यापन की जटिल प्रक्रियाएँ और विभागों के बीच समन्वय की कमी जैसी समस्याएँ सामने आती हैं। इससे न केवल प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त भार पड़ता है, बल्कि योजनाओं के आकलन और प्रभावी क्रियान्वयन में भी बाधाएँ उत्पन्न होती हैं।

अब इस विधेयक के माध्यम से राज्य में एक एकीकृत परिवार-स्तरीय डेटा भंडार स्थापित किया जाएगा, जो विभिन्न विभागों और एजेंसियों के लिए लाभार्थी संबंधी सूचनाओं का एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में कार्य करेगा।

> देवभूमि परिवार विधेयक-2026 सुशासन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे प्रशास. निक दक्षता बढ़ेगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और उत्तराखंड के नागरिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से पहुँच सकेगा।
>
> **पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री**

इससे योजनाओं का बेहतर लक्ष्योन्मुखी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सकेगा और जरूरतमंद परिवारों तक सरकारी सहायता अधिक प्रभावी ढंग से पहुँच सकेगी।

इसके साथ ही, इस डेटा प्रणाली के प्रभावी प्रबंधन, संरक्षण और संरचनात्मक सुधारों के लिए एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र का भी गठन किया जाएगा।

प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत विभागों के बीच सुरक्षित और विनियमित डेटा आदान-प्रदान की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी, जिससे योजनाओं के बेहतर लक्षित वितरण और समन्वय को मजबूती मिलेगी। यह पूरी व्यवस्था डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 (डीपीडीपी एक्ट 2023) के प्रावधानों के अनुरूप संचालित की जाएगी, ताकि नागरिकों के डेटा का उपयोग सहमति, पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ सुनिश्चित किया जा सके।

ये विधेयक भी किए गए प्रस्तुत

- उत्तराखंड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026
- उत्तराखंड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा शर्त) (संशोधन) विधेयक, 2026
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993) (संशोधन) विधेयक, 2026
- उत्तराखंड जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2026
- उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2026
- उत्तराखंड सार्वजनिक द्यूत रोकथाम, विधेयक, 2026
- उत्तराखंड भाषा संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2026
- उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
- उत्तराखंड कारागार व सुधारात्मक सेवाएं (संशोधन) विधेयक, 2026

भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई के लिए जाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।

कांग्रेस ने जन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा

शाह टाइम्स संवाददाता

भराड़ीसैंण/चमोली। भराड़ीसैण में चल रहे विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस ने विभिन्न जन मुद्दों को लेकर सरकार को बुरी तरह घेरा। इसके चलते दूसरे दिन भराड़ीसैण की सड़कों पर सरकार के खिलाफ महासंग्राम देखने को मिला।

दरअसल कांग्रेस ने गैरसैण स्थाई राजधानी, मंहगाई, बेरोजगार, अंकिता हत्याकांड, महिला सुरक्षा समेत तमाम मुद्दों को लेकर बजट सत्र के दूसरे दिन विधानसभा घेराव का कार्यक्रम निर्धारित किया था। इसके तहत मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा, पूर्व मंत्री डा. हरक सिंह रावत, बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला, पूर्व विधायक डा.जीत राम व रणजीत सिंह रावत समेत तमाम कांग्रेसी दिग्गज कार्यकर्ताओं संग विधानसभा घेराव को सड़क पर उतर आए। इसके तहत गढ़वाल की ओर से जंगलचट्टी तथा कुमाऊं की ओर से कालीमाटी से कांग्रेस कार्यकर्ता जुलूस प्रदर्शन की शक्ल में विधानसभा घेराव को निकल पड़े। घेराव कार्यक्रम के तहत दोनों ओर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हुजुम दीवालीखाल पहुंचा। दीवालीखाल में पुलिस ने विधानसभा मार्ग पर चार बैरियर लगा रखे थे। दीवालीखाल में तो जब कांग्रेसी जमा हुए तो एक तरह से दीवालीखाल महासंग्राम का केंद्र बिंदू बन गया। इससे गढ़वाल तथा कुमाऊं की ओर से आ जा रहे वाहनों की आवाजाही भी ठप्प हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता दीवालीखाल से आगे बढ़ने लगे थे कि पहले ही बैरियर को पार करने के लिए कार्यकर्ताओं को खासा पसीना बहाना पड़ा। इस सब के बीच कुछ कांग्रेसी तो बैरियर को फांद कर आगे बढ़ गए। पुलिस लगातार रो. कने का प्रयास करती रहीं किंतु कांग्रेसियों के झुंड के चलते बैरियर टूट पड़ा और कांग्रेसी आगे बढ़कर दूसरे बैरियर से आगे निकलने की जद्दोजहद में जुट गए। बैरियर की ऊंचाई काफी अधिक होने के कारण कांग्रेस वर्करों के बैरियर को फांद कर आगे बढ़ने के प्रयास निरर्थक साबित हुए। इस तरह दूसरा बैरियर पुलिस और कांग्रेसियों के बीच संग्राम का केंद्र बिंदु बन गया। इस बैरियर फांद कर निकलने के प्रयास जब असफल हुए तो कांग्रेसी वहीं पर सरकार के खिलाफ नारेबा. जी और प्रदर्शन करने लगे। यहां पर भी कई कांग्रेसियों ने कुर्सियों को जरिए बैरियर को पार करने की रणनीति बनाई किंतु इसमें भी सफलता नहीं मिल पाई। पुलिस ने कांग्रे. सियों को आगे न बढ़ने देने के लिए वाटर कैनिंग के जरिए पानी की बौछार लगाई। काफी देर तक संघर्ष चलता रहा।

■ भराड़ीसैण की सड़कों पर देखने को मिला महासंग्राम

सरकार को चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा: गोदियाल

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि इस कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा विधायकों ने प्रतिभाग कर जन मुद्दों को लेकर अपने समर्पण का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आगे भी जनसरोक. ारों से जुड़े सवालों को लेकर संघर्ष की भूमिका में रहेगी। सरकार को चैन से बैठने नहीं दिया जाएगा।

अब भाजपा सरकार की विदाई तय: हरीश रावत

पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि आम जनता भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों से त्रस्त होकर रह गई है। इसलिए अब भाजपा सरकार की विदाई तय है। जनता ने भाजपा को सत्ता से हटाने का मन पूरी तरह बना लिया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगे भी इसी तरह जन मुद्दों को लेकर संघर्ष की भूमिका में खड़े रहने का आह्वान किया। कहा कि भाजपा की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ गांव-गांव तक लोगों को एकजुट करना होगा। इसमें ही कांग्रेस का सुनहरा भविष्य छिपा है।

धामी सरकार के चार साल में बने 819 पंचायत भवन

शाह टाइम्स ब्यूरो

■ प्रदेश में सात हजार किमी से अधिक सड़कें हुई गड्ढा मुक्त

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के बीते चार साल में प्रदेश में 819 पंचायत भवनों का निर्माण पुननिर्माण किया गया है।

प्रदेश में पंचायत भवनों की संख्या 5867 है। इसमें से 1134 पंचायत भवन लंबे समय से जीर्णशीर्ण चल रहे थे।

इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायतीराज विभाग को अभियान चलाकर जीर्ण- शीर्ण भवनों का पुनर्निमाण करने के निर्देश दिए थे।

इसके बाद गत चार वर्ष में विभाग ने 819 पंचायत भवनों का निर्माण- पुनर्निर्माण कर लिया है। शेष भवनों पर भी कार्य किया जा रहा है। मंगलवार को विभागीय मंत्री सतपाल महाराज ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह जानकारी सदन के सामने रखी।

7 हजार किमी से अधिक सड़कें गड्ढा मुक्त: प्रदेश में लोकनिर्माण विभाग नवंबर के प्रथम सप्ताह तक सात हजार से अधिक किमी सडकों को गड्ढा मुक्त कर चुका है।

सदन में विभाग की ओर से प्रस्तुत जानकारी के अनुसार प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के क्रम में विभाग ने वर्ष 2025-26 में मानसून काल से पूर्व 3134 किमी लंबी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया। जबकि मानसून के बाद 10 नवंबर 2025 तक 4149.17 किमी लंबी सड़कों को गड्ढा मुक्त किया। इस दौरान अकेले हरिद्वार जनपद में 313 किमी से अधिक लंबी सड़कों को गड्ढामुक्त किया गया।

रोपवे परियोजनाओं पर काम तेज

प्रदेश में विभिन्न तीर्थ स्थलों को रोपवे से जोड़ने की प्रक्रिया गतिमान है। पर्यटन मंत्री ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि विभाग ने कद्दूखाल से सुरकंडा देवी मंदिर के लिए पीपीपी मोड़ में रोपवे का संचालन शुरु कर दिया है। इसके अलावा जनपद चम्पावत में ठुलीगाड़ से पूर्णागिरी रोपवे भी पीपीपी मोड में निर्माणाधीन है। साथ ही जनपद उत्तरकाशी में जानकी चट्टी से यमुनोत्री मंदिर तक के लिए भी रोपवे पीपीपी मोड में विकसित किया जा रहा है। साथ ही साथ गौरीकुंड से केदारनाथ धाम, गोविंदघाट से हेमकुंड साहिब के लिए भी रोपवे निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है।

सदन में विपक्ष का हंगामा, हरीश धामी ने खोला मोर्चा

भराड़ीसैंण। गैरसैंण विधानसभा बजट सत्र में उस समय हंगामा हो गया जब कांग्रेस विधायक हरीश धामी वेल में पहुंच गए।

कुछ देर सदन स्थगित होने के बाद कार्यवाही फिर से शुरू हुई। उन्होंने धारचूला की ब्लॉक प्रमुख का मामला उठाया। धामी ने आरोप लगाया कि नेपाली मूल की महिला को गलत प्रमाण पत्र पर ब्लॉक प्रमुख बनाया गया है। इस पर विपक्षी विधायकों और स्पीकर के बीच तीखी बहस हो गई। देखते ही देखते सदन में विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। धारचूला विधायक हरीश धामी ने व्यवस्था के प्रश्न के तहत उठाया था मुद्दा। उन्होंने अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया।

मुद्दों पर बहस से भागकर कांग्रेस कर रही जनता से विश्वासघात: चौहान

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स

■ कहा, जन सरोकारों के मुद्दे को राजनैतिक विरोध की भेंट चढ़ाने की कोशिश

देहरादून। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस जन सरोकारों के मुद्दे को राजनैतिक विरोध की भेंट चढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनता इस विश्वासघात का समय पर जवाब देगी।

सदन और विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए चौहान ने कहा कि अब विरोध के लिए विरोध कांग्रेस का चरित्र हो गया है। यह उसका गैरजिम्मेदाराना कदम है, क्योंकि वह उस जनता के प्रति जवाबदेह है जिसने उन्हे सदन मे भेजा है। उन्होंने गैरसैण बजट सत्र कांग्रेस के रुख पर नाराजगी जताते हुए इसे राजनीतिक स्टंट बताया है। क्योंकि विगत 4 वर्षों में जिस तरह धामी सरकार में प्रदेश का चहुंमुखी विकास हुआ है उसको देखते हुए विपक्ष के पास मुद्दों का अकाल पड़ गया है।चौहान ने कहा कि विकास, जन कल्याण, कानून व्यवस्था, रोजगार सहित राज्य की संस्कृति के सरंक्षण तथा डेमोग्राफी चेंज के लिए कई कानून बने हैं जिससे कांग्रेस असहज है। जिस तरह का संतुलित और समग्र विकास का कल्याणकारी बजट मुख्यमंत्री धामी लेकर आए हैं। उसके आधार पर वर्तमान वित्त वर्ष में उत्तराखंड के विकास की रफ्तार और गति पकड़ेगी। उन्होंने कहा कि आम जन की राय से बने बजट को कांग्रेस पचा नही पा रही है। अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय नेतृत्व की शह पर उसका मकसद देवभूमि की तरक्की को बाधित करना है। कांग्रेस सच को स्वीकार करने से बच रही है।

तल्लानागपुर चोपता क्षेत्र में गहराया पेयजल संकट

■ टैंकरों से भी नहीं बुझ रही ग्रामीणों की प्यास, दूर-दराज के जलस्रोतों से पानी ढोने को मजबूर लोग,

शाह टाइम्स संवाददाता

ऊखीमठ/रुद्रप्रयाग। तल्लानागपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले चोपता क्षेत्र में इन दिनों पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। क्षेत्र के प्राकृतिक जलस्रोतों के सूखने और पानी के स्तर में गिरावट आने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि जल संस्थान विभाग द्वारा टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति किए जाने के बावजूद भी लोगों को बूंद-बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है।

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार इस वर्ष सर्दियों में अपेक्षाकृत कम हिमपात और वर्षा होने के कारण क्षेत्र के अधिकांश नौले, धारे और गदेरे सूखने लगे हैं। जिन जलस्रोतों से वर्षों से गांवों की प्यास बुझती थी, वे अब धीरे-धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इसके चलते चोपता क्षेत्र के कई गांवों में पेयजल का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। पेयजल संकट को देखते हुए जल संस्थान विभाग द्वारा कुछ गांवों में टैंकरों से पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन यह आपूर्ति ग्रामीणों की जरूरत के अनुरूप नहीं पहुंच पा रही है। टैंकर से पानी की सप्लाई नियमित न होने के कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई ग्रामीणों को मजबूरी में दूर-दराज के जलस्रोतों से पानी ढोकर लाना पड़ रहा है।

इस समस्या से महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें प्रतिदिन कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। कई स्थानों पर पानी देर रात और सुबह तड़के पानी भरने के लिए लाइन लगाते देखे जा रहे हैं, जिससे लोगों की दैनिक दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। जिला पंचायत सदस्य संपेन नेगी का कहना है कि यदि शीघ्र ही पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया गया तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है। उन्होंने प्रशासन और जल संस्थान विभाग से मांग की है कि क्षेत्र में स्थायी समाधान के लिए नई पेयजल योजनाओं को शीघ्र शुरू किया जाए तथा मौजूदा योजनाओं की मरम्मत और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाए।

वहीं, क्षेत्र पंचायत सदस्य फलासी दिनेश नेगी का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जलस्रोतों के संरक्षण और वर्षाजल संचयन की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। यदि समय रहते जल संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो आने वाले वर्षों में पेयजल संकट और गहरा सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता पंचम नेगी का कहना है कि विभाग द्वारा प्रतिदिन लगभग 40 हजार लीटर पानी टैंकरों के माध्यम से सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से कुछ तोकों में नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

उधर, विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पेयजल योजना के मूल स्रोत में जल स्तर काफी कम हो जाने के कारण आपूर्ति सुचारू रूप से करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

महिला जनसुनवाई कार्यक्रम 11 मार्च को

रुद्रप्रयाग। महिलाओं की समस्याओं के त्वरित समाधान और उन्हें न्याय दिलाने के उद्देश्य से 11 मार्च को विकास भवन में महिला जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस जनसुनवाई में महिलाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को सुना जाएगा तथा उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यगण द्वारा की जाएगी। जनसुनवाई के दौरान जिले भर से आने वाली महिलाएं अपनी समस्याएं सीधे आयोग के समक्ष रख सकेंगी। इस अवसर पर जनपद के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, ताकि प्राप्त शिकायतों पर मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई करते हुए उनका समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

रुद्रप्रयाग में स्मैक तस्कर गिरफ्तार

■ एसपी के निर्देश पर नशे के खिलाफ अभियान तेज, एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज

शाह टाइम्स संवाददाता

रुद्रप्रयाग। जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रुद्रप्रयाग पुलिस की एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने कोतवाली रुद्रप्रयाग क्षेत्र से एक तस्कर को 5.30 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक सुश्री नीहारिका तोमर के निर्देश पर जनपद की एसओजी सहित सभी थाना और कोतवाली प्रभारियों को मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में एसओजी टीम ने स्थानीय सूचना तंत्र के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त आशुतोष पंवार पुत्र सुंदर सिंह पंवार, निवासी वार्ड नंबर 09, पौड़ी रोड, राजश्री विहार, अपर भक्तियाना, श्रीनगर, जिला पौड़ी गढ़वाल के कब्जे से 5.30 ग्राम स्मैक बरामद की गई। इस संबंध में कोतवाली रुद्रप्रयाग में मु.अ.सं. 15/2026 के तहत धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई है। पुलिस ने अभियुक्त को न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक रणजीत खनेड़ा (प्रभारी एसओजी), आरक्षी रविन्द्र सिंह, आरक्षी देवेन्द्र सिंह मौजूद थे।

एसपी ने कहा कि जनपद में नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

तिलवाड़ा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर सवाल, रसूखदारों को बचाने के आरोप

शाह टाइम्स संवाददाता

रुद्रप्रयाग। केदारनाथ हाईवे पर तिलवाड़ा क्षेत्र में चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर भेदभाव के गंभीर आरोप लगने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जहां एक ओर सामान्य और गरीब लोगों के अतिक्रमण को तेजी से हटाया जा रहा है, वहीं तथाकथित रसूखदारों को बचाने के लिए प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। इससे कार्रवाई की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

जानकारी के अनुसार तिलवाड़ा में केदारनाथ हाईवे-107 पर इन दिनों एनएच विभाग और तहसील प्रशासन की संयुक्त टीम अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है। लेकिन आरोप है कि अधिकारियों की कथित मिलीभगत से हाईवे की भूमि पर कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा नए निर्माण और अतिक्रमण किए जा रहे हैं, जबकि ठीक बगल में अन्य लोगों के अतिक्रमण को हटाया गया है।

भरदार विकास मंच के महासचिव भगत चौहान ने आरोप लगाया कि प्रशासन की कार्रवाई में स्पष्ट भेदभाव दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि गरीब और सामान्य लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, जबकि रसूखदारों के अतिक्रमण को बचाया जा रहा है और उन्हें निर्माण कार्य करने की छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन और एनएच विभाग की संयुक्त टीम तिलवाड़ा में अतिक्रमण हटाने का कार्य कर रही है, लेकिन इस पूरी कार्रवाई में निष्पक्षता नहीं दिख रही है। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में यह मामला जनाक्रोश का रूप ले सकता है।

चौहान ने यह भी कहा कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार में नौकरशाही हावी होती नजर आ रही है। अधिकारियों की मनमानी से आम लोग परेशान हैं और रसूखदारों के साथ मिलकर हाईवे की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण से प्रभावित कुछ लोगों ने न्याय के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। उनका कहना है कि यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के भेदभाव को रोका जा सके। वहीं, मामले में अधिशासी अभियंता ओंकार पांडे ने कहा कि हाईवे चौड़ीकरण को लेकर 14 मीटर के हिस्से को लिया जाना है, जबकि अतिक्रमण के बगल में हटाए गए अतिक्रमण और रसूखदार को छूट दिए जाने के सवाल के जवाब पर उन्होंने कोर्ट जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अतिक्रमण से समस्या हो रही है, वे कोर्ट की शरण ले सकते हैं। इधर, उप जिलाधिकारी एसएस सैनी ने कहा कि अतिक्रमण की कार्यवाही लगातार जारी है। जिन लोगों ने दो सालों से अतिक्रमण नहीं हटाया है, उन पर भी कार्यवाही की जा रही है।

डीएम ने सुनी समस्याएं, कई शिकायतों का मौके पर समाधान

शाह टाइम्स संवाददाता

ऊखीमठ/रुद्रप्रयाग। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासन-प्रशासन तक उनकी सीधी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जनपद रुद्रप्रयाग में आयोजित तहसील दिवस कार्यक्रम के तहत मंगलवार को विकासखंड ऊखीमठ स्थित खंड विकास कार्यालय के सभागार में जिलाधिकारी विशाल मिश्रा की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में जिलाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों ने आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। तहसील दिवस में कुल 70 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 32 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए।

तहसील दिवस के दौरान स्थानीय

ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से प्रशासन को अवगत कराया। ग्रामीणों ने केदार घाटी क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री का मुद्दा प्रमुखता से उठाया, जिस पर जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग को क्षेत्र में नियमित अभियान चलाकर अवैध शराब के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ओंकारेश्वर मंदिर मोटरमार्ग के क्षतिग्रस्त होने तथा मार्ग में पड़ने वाले गदेरे से हो रहे कटाव की समस्या भी उठाई गई। इस पर संबंधित विभाग को सड़क की मरम्मत और सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही ऊखीमठ क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऊखीमठ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकृत करने की मांग भी रखी गई, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।ग्रामीणों ने पिंगलापानी पेयजल योजना का कार्य शीघ्र शुरू कराने की मांग भी उठाई। वहीं ग्राम पाब जगपुड़ा के ग्रामीणों ने पीएमजीएसवाई के अंतर्गत तालादुबंगराली मोटर मार्ग के किमी पांच पर पाब-दुर्गाधार मोटरमार्ग में बने 30 मीटर स्पान स्टील गार्डर पुल को अप्रोच सड़क से न जोड़ने की शिकायत की।

ग्राम उषाड़ा के ग्रामीणों ने हर घर जल योजना के तहत पेयजल आपूर्ति सुचारु न होने तथा गांव में सौर ऊर्जा लाइट लगाने की मांग रखी। इसके अतिरिक्त तहसील दिवस में सड़क मरम्मत, गड्ढा भरान, विद्युत आपूर्ति, पेयजल व्यवस्था और मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम से जुड़ी समस्याएं भी सामने आईं।

इस अवसर पर जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार तहसील दिवस, सरकार जनता के द्वार और बहुउद्देशीय शिविरों का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनना और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि आज ऊखीमठ क्षेत्र में पहुंचकर क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी गईं और अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।उन्होंने कहा कि कुछ शिकायतें निर्माण कार्यों तथा वन विभाग से संबंधित फॉरेस्ट क्लीयरेंस के कारण लंबित हैं, जिन पर शासन स्तर पर कार्रवाई जारी है। तहसील दिवस में प्राप्त सभी शिकायतों को सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर अपडेट कर उनकी नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और शिकायतकर्ताओं को की गई कार्रवाई की जानकारी भी दी जाएगी। इस अवसर पर नगर पंचायत ऊखीमठ अध्यक्ष कुब्जा धर्मवान, मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत, उपजिलाधिकारी भगत सिंह फोनिया, तहसीलदार रमेश सिंह, खंड विकास अधिकारी अनुष्का, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामप्रकाश, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. आशीष रावत, जिला समाज कल्याण अधिकारी टी. आर. मलेठा, प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ विनोद भास्कर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

चिन्यालीसौड़ पालिका ने स्वच्छता को लेकर आयोजित की प्रतियोगिता

शाह टाइम्स संवाददाता

चिन्यालीसौड़ : स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत नगर पालिका परिषद चिन्यालीसौड़ में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पालिका अध्यक्ष मनोज कोहली और अधिशासी अधिकारी वीरेन्द्र पंवार ने पालिका सभागार में छात्र-छात्राओं के बीच निबन्ध ,स्वच्छता चित्रकला प्रतियोगिता और स्वच्छता शपथ समारोह का आयोजन किया गया।

इस दौरान पालिका अध्यक्ष मनोज कोहली ने अपने संबोधन में कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में स्वच्छता के प्रति विद्यार्थियों, युवाओं और शिक्षकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।

उन्होंने शहर को कचरा मुक्त बनाने, खुले स्थानों और नालों में कचरा न फेंकने, डोर टू डोर कलेक्शन में मदद करने, कूड़े को अलग-अलग रखने, गीले कूड़े से होम कंपोस्टिंग बनाने और प्लास्टिक के उपयोग से बचने की महत्वपूर्ण जानकारी दी।

पेंटिंग प्रतियोगिता में बिरजा प्राइमरी स्कूल से देवांश नौटियाल ने प्रथम स्थान,अर्पित चौहान ने द्वितीय स्थान व

वैष्णवी बडोनी मॉडल स्कूल बड़ेथी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में भी बिरजा प्राइमरी स्कूल से

आदित्य नेगी ने व राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बड़ेथी की आरुषि नौटियाल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

इस मौके पर नगर पर पालिका अध्यक्ष कार्यक्रम के अंत में विजेता प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार से सम्मानित करके सभी छात्र-छात्राओं का उत्साहवर्धन किया गया।

यमुनोत्री सड़क चौड़ीकरण: विकास बन रहा विनाश

■ सड़क कटिंग का मलबा उड़ेला जा रहा यमुना में, तबाही का अलर्ट,यमुनोत्री हाईवे चौड़ीकरण बना आफत धूल और मलबे से यात्री बेहाल

चिरंजीव सेमवाल

उत्तरकाशी : यमुनोत्री राजमार्ग पर चल रहे ऑल वेदर परियोजना के तहत चौड़ीकरण कार्य के चलते उड़ रही धूल और जगह-जगह फैले मलबे से स्थानीय ग्रामीण और राहगीर परेशान हैं।

सड़क चौड़ीकरण पालीगाड से क्षेत्र के नेन गांव के पास चल रहा सड़क चौड़ीकरण का कार्य अब विकास से ज्यादा विनाश का प्रतीक बनता जा रहा है।

खासकर रानाचट्टी, हनुमानचट्टी और स्यानाचट्टी क्षेत्र में उड़ती धूल और मलबा के कारण स्थानीय पर्यावरण मानवको की अनदेखी कतई भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यमुनोत्री हाईवे के मलबा को यदि अनियंत्रित डंप किया गया तो कार्यदाई संस्था का चालन काटा जायेगा।

प्रशांत आर्य जिलाधिकारी उत्तरकाशी

ग्रामीणों और राहगीरों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ रही।

पहाड़ी की अनियंत्रित कटिंग, नियमों की खुली अनदेखी और निर्माण एजेंसी की मनमानी ने पूरे इलाके को खतरे के मुहाने पर ला खड़ा किया है। सबसे बड़ी लाप. रवाही यह है कि कटिंग से निकला हजारों टन मलबा वैज्ञानिक निस्तारण के बजाय सीधे यमुना नदी में उड़ेला जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता शेरा सिंह चौहान ने बताया कि यमुनोत्री हाईवे पर बहुत डेंजर पॉइंट है सड़क चौड़ीकरण होने से चारधाम यात्रा में जाम की स्थिति नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल से पहले ही हाईवे पर कार्य संभव यात्रा शुरू होते की कार्य थम जाएगा।

उन्होंने हाईवे सड़क चौड़ीकरण पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सड़क चौड़ीकरण कार्य के दौरान उड़ रही धूल से स्थानीय लोग और दुकानदार परेशान है। वहीं मलवा को भी यमुना नदी में डंप किया जा रहा। मामले में उन्होंने जिलाधिकारी उत्तरकाशी से भी बातां की है। उन्होंने जिलाधिकारी प्रशांत आर्य को कार्यदाई संस्था पर आवश्यक कार्रवाई करनी की भी मांग उठाई है।

वहीं भाजपा नेता संदीप राणा का आरोप है कि यह सिर्फ पर्यावरणीय अपराध नहीं, बल्कि भविष्य की बड़ी तबाही की नींव है।

उन्होंने यमुनोत्री हाईवे चौड़ीकरण में मनकों की अनदेखी हो रही। कुछ स्थानों पर हाईवे को महज दश मिटर चौड़ीकरण किया जा रहा है। नदी का गला घोंट रहा मलबा, महा. विनाश का खतरा

यमुनोत्री हाईवे चौड़ीकरण का मलबा कार्य दाय संस्था द्वारा सीधे यमुना नदी में उड़ेला जा रहा। बता दें चीन दिनों यमुना नदी का जलप्रवाह कम है, इसलिए मलबे का असर तुरंत दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पर्यावरण विशेषज्ञों की मानें तो आने वाला वर्षा काल इस लापरवाही को महाविनाश में बदल सकता है। जब जलस्तर बढ़ेगा, तो नदी में जमा यह मलबा जलप्रवाह वाले क्षेत्रों में बाढ़ और भारी भू-कटाव का सबब बनेगा। उत्तरकाशी के पर्यावरणविद् सुरेश भाई ने भी इस स्थिति पर चिंता जताते हुए इसे यमुना के अस्तित्व के लिये बेहद घातक बताया है।

बता दें कि बीते मानसून सीजन में स्याना चट्टी में झील बनने से जहां यमुनोत्री यात्रा ठप्प हो गई वहीं स्थानीय लोगों का भारी नुकसान पहुंचा है।

शिकायत पर फौरन गांव पहुंचीं जिलाधिकारी

शाह टाइम्स संवाददाता

कोटद्वार। सरकार की मंशा है कि प्रशासन जनता के द्वार तक पहुंचे और समस्याओं का त्वरित समाधान हो। इसका एक सशक्त उदाहरण तब देखने को मिला, जब जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने कुण्डाली गांव में पेयजल न आने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए स्वयं गांव पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और समस्या के समाधान के लिए तत्काल निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों के साथ गांव में पेयजल व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ संवाद कर उनकी समस्याओं को विस्तार से सुना और नलों से आने वाले पेयजल की स्वयं जांच भी की, ताकि वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके।निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वर्तमान में उपलब्ध टैंक की क्षमता गांव की जरूरत के अनुरूप पर्याप्त नहीं है। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल ग्रैविटी और पॉपिंग आधारित पेयजल योजनाओं की समीक्षा करते हुए जल टैंक की क्षमता को 5 किलोलीटर से बढ़ाकर 17 किलोलीटर किए जाने के निर्देश दिए, ताकि गांव में पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से हो सके। इसके साथ ही उन्होंने नलों पर कंट्रोल लगवाने के निर्देश भी दिए, जिससे पानी का दबाव संतुलित रहे और प्रत्येक घर तक समान रूप से पेयजल पहुंच सके। जिलाधिकारी की इस त्वरित पहल से ग्रामीणों में संतोष और विश्वास का माहौल देखने को मिला। ग्राम प्रधान संतोष नेगी ने कहा कि प्रशासन के इस सक्रिय और संवे. दनशील रवैये से उनकी लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान की उम्मीद जगी है। यह पहल दर्शाती है कि जब प्रशासन संवेदनशीलता के साथ सीधे जनता के बीच पहुंचता है, तो समस्याओं का समाधान भी तेजी और प्रभावी तरीके से संभव हो जाता है।

डीएम ने लिया चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा

■ यात्रा शुरू होने से पूर्व सभी मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करने के निर्देश

शाह टाइम्स संवाददाता

उत्तरकाशी : जिलाधिकारी प्रशान्त आर्य ने गंगोत्री धाम पहुंचकर अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया।

मंगलवार को जिलाधिकारी ने यात्रा मार्ग ,स्नान घाटों और श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण से पूर्व जिलाधिकारी ने गंगोत्री धाम में मॉदर समिति के पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिन्हित भूस्खलन जोन

तथा यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले प्रमुख पड़ावों,पार्किंग स्थलों और संवे. दनशील स्थानों की समीक्षा की। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए पेयजल,शौचालय,सफाई,स्वास्थ्य सेवाओं और ठहरने की व्यवस्थाओं की भी विस्तार से समीक्षा की। जिलाधिकारी ने स्नान घाट के सौंदर्यीकरण करने एवं नगर पंचायत के अंतर्गत चल रहे निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने गंगोत्री सीवरेज प्लांट में किचन और बाथरूम का पानी समाहित न होने देने के लिए नगर पंचायत और जल संस्थान को संयुक्त रूप से चेकिंगअभियान चलाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मंदिर परिसर में समुचित प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश उरेडा को दिए। साथ ही आपदा प्रभावित परिवारों के आजीविका संवर्द्धन के लिए यात्रा मार्ग के प्रमुख पड़ावों पर क्योस्क स्थापित करने के निर्देश रीप को दिए।

इस दौरान जिलाधिकारी ने धराली में आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। प्रभावित परिवारों द्वारा रखी गई मांगों पर उन्होंने हर संभव निस्तारण करने का भरोसा दिलाया। इसके अलावा जिलाधिकारी ने बीआरओ को धराली में सड़क मार्ग पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव करने के निर्देश दिए, ताकि ग्रामीणों को धूल की समस्या से राहत मिल सके। उन्होंने चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व सड़क मार्ग पर डामरीकरण कार्य पूर्ण करने के भी निर्देश बीआरओ को दिए।

इस दौरान एसडीएम शालिनी नेगी,सीओ जनक पंवार,ईई मनोज गुसाईं,सचिन सिंघल,परियोजना प्रबन्धक उरेडा मयंक नोटियाल,परियोजना प्रबन्धक रीप कपिल उपाध्याय, खण्ड विकास अधिकारी डॉ.अमित मंमगाईं,जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शार्दुल गुसाईं सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

पीएम के मन की बात को सुनने का आह्वान

श्रीनगर। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गहड़ में छात्र-छात्राओं को ड्रेस वितरित की गई। कैबिनेट मंत्री डा. धन सिंह रावत के सौजन्य से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान पूर्व राज्यमंत्री अतर सिंह असवाल ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और बच्चों को बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं। इसके बाद वार्ड नंबर 3 के बूथ संख्या 159 गहड़ में भाजपा की बैठक आयोजित हुई। जिसमें कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया गया।कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष विनय घिल्डियाल, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रमिला भंडारी, खंड शिक्षा अधिकारी अश्वनी, जिला महामंत्री गणेश भट्ट सहित कई कार्यकर्ता व स्थानीय लोग मौजूद रहे।

पैतृक शिल्प को बनाया रोजगार, रिंगाल शिल्प से आत्मनिर्भर बने हलना के बलवीर लाल

शाह टाइम्स संवाददाता

पुरोला/उत्तरकाशी। उत्तराखंड की देवभूमि सदैव से परिश्रम, परंप. रा और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा देती आई है। इसी भावना को साकार कर रहे हैं उत्तरकाशी जनपद के हलना गांव निवासी बलवीर लाल, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने पैतृक शिल्प को अपनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की है।

बलवीर लाल का जन्म एक साधारण एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में हुआ। उनके पिता स्वर्गीय गुदड़िया लाल एक कृषक होने के साथ-साथ रवांई क्षेत्र के प्रसिद्ध पारंपरिक शिल्पकार भी थे। परिवार में तीन पुत्र और तीन पुत्रियों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी उन्होंने कृषि और शिल्प कला के माध्यम से निभाई और बच्चों को मेहनत व संस्कारों का पाठ पढ़ाया।समय के साथ परिवार पर दुखों का पहाड़ भी टूटा। वर्ष 2021 में माता के निधन के बाद वर्ष 2022 में पिता का भी स्वर्गवास हो गया। इसके बाद परिवार की जिम्मेदारी और पैतृक शिल्प परंपरा को आगे बढ़ाने का दायित्व सबसे छोटे पुत्र बलवीर लाल के कंधों पर आ गया।बलवीर लाल ने अपने पिता से सीखी हुई पारंपरिक शिल्प कला को ही जीवन का आधार बनाया और रिंगाल (पर्वतीय बाँस) से सुंदर व आकर्षक वस्तुएँ बनाना शुरू किया। उत्तरकाशी के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला रिंगाल प्राकृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है और इससे बनी वस्तुएँ पर्यावरण के अनुकूल होती हैं।

आज बलवीर लाल रिंगाल से घरों की सजावट, रेस्टोरेंट व कैफे की

डेकोरेशन, वेडिंग प्वाइंट और पूजा घरों के लिए विभिन्न प्रकार की आकर्षक वस्तुएँ तैयार करते हैं। उनकी कला की मांग लगातार बढ़ रही है और वे दिल्ली, देहरादून सहित देश के कई शहरों में अपने शिल्प के स्टॉल भी लगा चुके हैं।

मुख्यमंत्री ने भराड़ीसैंण में अग्निवीर कैडेट्स से किया संवाद

अग्निवीरों के भविष्य की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी: धामी

■ वर्दीधारी पदों में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था ■ सैनिकों के अनुशासन और समर्पण से प्रेरणा लेकर जनता की सेवा कर रहा हूँ: मुख्यमंत्री

शाह टाइम्स ब्यूरो

गैरसैंण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को भराड़ीसैंण में अग्निवीर सैनिकों के रूप में भर्ती होने वाले कैडेट्स के साथ संवाद किया। संवाद के दौरान कैडेट्स ने मुख्यमंत्री से विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका मुख्यमंत्री ने सहजता से उत्तर दिया।

इस अवसर पर अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिक सीमांत और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा करते हैं। देवभूमि उत्तराखण्ड की विशेषता है कि यहां लगभग हर परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना या अर्द्धसैन्य बलों में सेवाएं दे रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना तेजी से आत्मनिर्भर बन रही है। रक्षा क्षेत्र में भारत का निर्यात भी लगातार बढ़ रहा है और भारतीय सेना वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और सक्षम सेना के रूप में स्थापित हुई है। सेना में निरंतर आधुनिक. ीकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सैनिकों और पूर्व सैनिकों के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। देहरादून में भव्य सैन्यधाम का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें राज्य के वीर बलिदानियों की गौरवगाथाएं और स्मृतियां संजोई जाएंगी। उन्होंने कहा कि वे पूर्व सैनिकों को अपने अभिभावक के रूप में देखते हैं। इस अवसर पर यूथ फाउंडेशन के संस्थापक कर्नल अजय कोठियाल (सेनि.), पूर्व सैनिकगण तथा अग्निवीर उपस्थित थे। हिमांशु रौतेला ने प्रश्न किया कि प्रदेश के मुखिया होने के नाते आप अपने परिवार को कैसे समय दे पाते हैं? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब कोई व्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सक्रिय होता है तो उसकी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। सीएम से सवाल करने वालों में ओ.पी. कण्डारी, रितेश पंवार, अमन सेमवाल शामिल रहे।

कैडेट्स ने किए सीएम से सवाल

संवाद के दौरान शंकर सिंह राणा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि सैनिक पुत्र होने के कारण आपने सैनिकों के जीवन और गतिविधियों को नजदीक से देखा है, क्या आपका मन सेना में जाने का नहीं हुआ? इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सेना में जाना अन्य सेवाओं की अपेक्षा अत्यंत सम्माननीय माना जाता है। उन्होंने कहा कि वे अपने जीवन को भी एक सैनिक के जीवन की तरह अनुशासित और समर्पित मानकर कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने पिताजी के साथ रहते हुए उन्होंने सेना के अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा को करीब से देखा है। जिस प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ हमारे सैनिक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, उसी भावना से वे प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में उत्तराखण्ड की देवतुल्य जनता की सेवा करने का प्रयास करते हैं।

पूर्व उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन के लिए 289.98 करोड़ की व्यवस्था

■ धामी सरकार ने लिया बड़ा निर्णय

शाह टाइम्स ब्यूरो

गैरसैंण। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में पूर्व उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट में इस मद के लिए 289 करोड़ 98 लाख 29 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपनल कर्मियों ने विभिन्न विभागों में लंबे समय तक महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।

इसी सोच के साथ राज्य सरकार ने समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था को लागू करने हेतु बजट में पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह निर्णय सरकार की समावेशी और संवेदनशील शासन व्यवस्था का प्रतीक है।

सरकार लगातार कर्मचारियों के कल्याण, प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और प्रदेश में पारदर्शी व उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से पूर्व उपनल कर्मियों को राहत मिलेगी और वे अधिक उत्साह के साथ राज्य के विकास में योगदान दे सकेंगे।

विकास लक्ष्य रैंकिंग में उत्तराखंड अव्वल, पर चुनौती बरकरार

■ विकास की दौड़ में डेटा प्रबंधन और विजन 2047 पर मंथन

शाह टाइम्स संवाददाता

देहरादून। विकास भवन सभागार, सर्वे चौक में मंगलवार को जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय द्वारा एक दिवसीय महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में सतत् विकास लक्ष्य, प्रधानमंत्री गतिशक्ति और उत्तराखण्ड विजन 2047 जैसे गंभीर विषयों पर जनपद स्तरीय अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों ने प्रतिभाग किया।

कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी शशिकांत गिरि ने विषय की महत्ता पर प्रकाश डाला। मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित सेतु आयोग के निदेशक डॉ. मनोज पंत ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2023-24 की रैंकिंग में उत्तराखंड ने केरल राज्य के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि प्रशंसनीय है, लेकिन इस स्थान को भविष्य में भी बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, जिसके लिए सभी विभागों को कड़ी मेहनत करनी होगी।नियोजन विभाग के विशेषज्ञ शैलेन्द्र कुमार ने पोर्टल के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2024-25 में जनपद देहरादून राज्य स्तर पर सातवें स्थान पर रहा है। उन्होंने जोर दिया कि आगामी वर्षों में दून को पहले स्थान पर लाने के लिए रणनीतिक प्रयास करने होंगे। विशेषकर कम प्रगति वाले संकेतकों पर ध्यान केंद्रित कर आंकड़ों के प्रबंधन में सुधार की आवश्यकता है। कार्यशाला के समापन पर अपर सांख्यिकीय अधिकारी धीरज गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नगर आयुक्त ऋषिकेश, परियोजना निदेशक, मुख्य शिक्षा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सहित तमाम जनपदीय अधिकारी उपस्थित रहे।

सूबे के हर प्राथमिक विद्यालयों में बनेंगे बालिका शौचालय: डॉ. रावत

■ शौचालय विहीन 141 विद्यालयों को 5.34 करोड़ आवंटित

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून। सूबे के शत प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में बालिका शौचालय बनाये जाएंगे ताकि यहां पढ़ने वाली बेटियों को शौचालय की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा। प्रदेश में शौचालय विहीन रह गये 141 प्राथमिक विद्यालयों में सुरक्षित टॉयलेट को राज्य सरकार ने 5.34 करोड़ की धनराशि आवंटित कर दी है। विभागीय अधिकारियों को इन विद्यालयों में मार्च माह तक शत-प्रतिशत बालिका शौचालय के निर्माण का लक्ष्य दिया गया है, साथ ही जिन विद्यालयों में शौचालय निष्क्रिय पड़े हैं उन्हें शीघ्र चालू करने को कहा गया है।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि विद्यालयों में फर्नीचर, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों के लिए घर से बाहर सुरक्षित शौचालय की व्यवस्था सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, इसलिए सरकार इस दिशा में विशेष प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है।

डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेश के 11 जनपदों के 141 राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय बालिका शौचालय विहिन रह गये हैं। इन विद्यालयों में युद्ध स्तर पर बालिका शौचालयों का निर्माण किया जायेगा।

जिसमें रूद्रप्रयाग व बागेश्वर जनपद में 7-7, पिथौरागढ़ व ऊधमसिंह नगर 6-6, नैनीताल 25, देहरादून 16, उत्तराकशी 10, चम्पावत 5, अल्मोड़ा 4, पौड़ी 2 जबकि टिहरी में सर्वाधिक 53 विद्यालयों में बालिका शौचालय बनाये जायेंगे। जिसके लिये 5 करोड़ 34 लाख 39 हजार की धनराशि आवंटित कर दी गई है। जिसमें रूद्रप्रयाग व बागेश्वर जनपद के लिये 26.53-26.53 लाख की धनराशि आवंटित की गई है। इसी प्रकार पिथौरागढ़ व ऊधमसिंह नगर के लिये 22.74-22.74 लाख, नैनीताल 94.75 लाख, देहरादून 60. 64 लाख, उत्तरकाशी 37.90लाख, चम्पावत 18.95 लाख, अल्मोड़ा 15.16लाख पौड़ी 7.58 लाख तथा टिहरी जनपद को 2 करोड़ 87 हजार की धनराशि जारी कर दी गई है।

उन्होंने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे सभी निष्क्रिय शौचालयों को आगामी 31 मार्च तक चालू कर छात्र-छात्राओं के उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए।

राष्ट्रीय औसत से आगे है उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति आय

■ राज्य सरकार ने उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को लेकर पेश किया तुलनात्मक चार्ट

एस. आलम अंसारी

गैरसैंण/देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण उत्तराखंड की वर्ष 2025-26 की रिपोर्ट में कई सुखद बातें सामने आई हैं।

धामी सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े जो आंकड़े पेश किए हैं उनके मुताबिक बीते वर्षों में उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय लगातार राष्ट्रीय औसत से अधिक बनी हुई है। मुख्यमंत्री धामी ने राज्य सरकार की इस उपलब्धि को मजबूत होती अर्थव्यवस्था का संकेत बताया है।

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान राज्य सरकार ने उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति को लेकर एक तुलनात्मक चार्ट प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य की प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत के साथ दिखाया गया है। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक से अधिक समय से उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय लगातार देश के औसत से अधिक बनी हुई है और आने वाले वित्तीय वर्ष में इसके और बढ़ने का अनुमान लगाया गया है।

उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से आगे: सरकार द्वारा प्रस्तुत ग्राफ के अनुसार वर्ष 2011-12 में देश की प्रति व्यक्ति आय जहां लगभग 63,462 रुपये थी, वहीं उत्तराखंड में यह 1,00,314 रुपये के करीब दर्ज की गई. इसके बाद से हर वर्ष राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी आगे बनी रही. वर्ष 2012-13 में देश की प्रति व्यक्ति आय करीब 70,983 रुपये रही, जबकि उत्तराखंड में यह 1,09,591 रुपये तक पहुंच गई।

आंकड़ों के मुताबिक 2013-14 में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 79,118 रुपये रही, जबकि उत्तराखंड में यह 1,26,356 रुपये दर्ज की गई. इसी तरह 2014-15 में राष्ट्रीय औसत करीब 86,647 रुपये रहा, जबकि राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,36,099 रुपये के आसपास पहुंच गई. इसके बाद भी राज्य की अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ोत्तरी देखने को मिली।

वर्ष 2015-16 में जहां देश की प्रति व्यक्ति आय करीब 94,797 रुपये रही, वहीं उत्तराखंड में यह 1,47,936 रुपये तक पहुंच गई. 2016-17 में भारत की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,03,870 रुपये रही, जबकि उत्तराखंड में यह 1,61,752 रुपये दर्ज की गई। इसके बाद 2017-18 में राष्ट्रीय औसत करीब 1,15,224 रुपये रहा, जबकि राज्य में यह 1,80,858 रुपये तक पहुंच गया। सरकार के आंकड़ों के अनुसार 2018-19 में देश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,25,946 रुपये रही, जबकि उत्तराखंड में यह 1,86,207 रुपये दर्ज की गई। वहीं 2019-20 में भारत का औसत करीब 1,32,341 रुपये रहा, जबकि राज्य में यह 1,90,558 रुपये तक पहुंच गया। कोविड काल में भी बढ़ी प्रति व्यक्ति आय: कोविड काल के दौरान भी राज्य की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से ऊपर बनी रही। वर्ष 2020-21 में देश का औसत करीब 1,27,244 रुपये रहा, जबकि उत्तराखंड में यह लगभग 1,74,526 रुपये दर्ज की गई। इसके बाद 2021-22 में राष्ट्रीय औसत करीब 1,50,906 रुपये रहा, जबकि राज्य में यह 1,94,670 रुपये तक पहुंच गया। सरकार द्वारा प्रस्तुत संशोधित अनुमान के अनुसार 2022-23 में देश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 1,69,496 रुपये रही, जबकि उत्तराखंड में यह 2,19,850 रुपये दर्ज की गई। वहीं 2023-24 के संशोधित अनुमान के मुताबिक राष्ट्रीय औसत करीब 1,88,892 रुपये और राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2,32,457 रुपये बताई गई है.

आने वाले वर्षों के अनुमान भी राज्य के लिए सकारात्मक संकेत दे रहे हैं. 2024-25 के अनुमान के अनुसार देश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,05,324 रुपये रहने का अनुमान है, जबकि उत्तराखंड में यह 2,50,736 रुपये तक पहुंच सकती है। वहीं 2025-26 के अग्रिम अनुमान में राष्ट्रीय औसत करीब 2,19,575 रुपये और उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय 2,73,921 रुपये तक पहुंचने का अनुमान जताया गया है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कहना है कि राज्य में पर्यटन, सेवा क्षेत्र, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश को बढ़ावा देने वाली नीतियों के कारण आर्थिक गति. विधियों में तेजी आई है। इसी का असर प्रति व्यक्ति आय में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी के रूप में दिखाई दे रहा है। बजट सत्र में पेश किए गए इन आंकड़ों को सरकार ने राज्य की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का संकेत बताया है।

पुलिस ने शातिर चोर को दबोचा, चोरी का वाहन बरामद

देहरादून। राजधानी की पटेलनगर पुलिस ने वाहन चोरी की गुत्थी सुलझाते हुए एक शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की गई स्कूटी भी बरामद कर ली है।23 फरवरी 2026 को संगम विहार (जीएमएस रोड) निवासी हरी सिंह ने अपनी सफेद रंग की स्कूटी चोरी होने के संबंध में कोतवाली पटेलनगर में ई-एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 303(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। एसएसपी देहरादून के निर्देशों पर गठित पुलिस टीम ने घटना स्थल और उसके आसपास के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने संदिग्धों पर नजर रखी। मंगलवार, 10 मार्च को पुलिस टीम ने सटीक सूचना के आधार पर आर्मी ग्राउंड, पटेलनगर के पास से वसीम अली को घेराबंदी कर दबोच लिया। गिरफ्तार अभियुक्त वसीम अली, मेहुँवाला का निवासी है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर चोरी की गई सफेद रंग की स्कूटी बरामद कर ली है।

उत्तराखंड बजट में मातृशक्ति के सशक्तिकरण को प्राथमिकता : दीप्ति रावत

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा के चल रहे बजट सत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रस्तुत बजट प्रदेश के समग्र विकास के साथ-साथ मातृशक्ति के सशक्तिकरण को समर्पित है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह बजट महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं को निरंतर आगे बढ़ाया जा रहा है। इनमें नंदा गौरा योजना के माध्यम से बेटियों के जन्म और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वहीं मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के तहत नवजात शिशुओं और माताओं को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है।

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि०
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम) कॉरपोरेट आईडेन्टीटी नं० U40109UR2001SGCO25867/2358
विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, देहरादून
फोन: 91-135-2763672-76 फैक्स: 91-135-2760289

पत्रांक : 175/EE(CM)/UPCL/A-2 दिनांक : 10.03.2026

ई-निविदा विस्तार सूचना

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रकाशित ई-निविदा विशिष्टीकरण संख्या सी.सी.पी. -II/23/2025 -2026 के अन्तर्गत आर०डी०एस०एस० योजना के तहत टर्नकी आधार पर ऋषिकेश में 33/11 के.वी. इन्डोर टाइप जी.आई.एस उपस्थान (i) रामझूला -2x10एम.वी.ए. (ii) बैराज-2/ गुमानीवाला-2x12.5 एम.वी.ए. एवं सम्बन्धित 11 के.वी. एवं 33 के.वी. विद्युत लाइन का निर्माण का कार्य की तिथि को अपरिहार्य कारणों से विस्तारित किया जाता है। ई-निविदा क्रय एवं जमा दिनांक 17.03.2026 को 17:00 बजे तक की जा सकती है। ई-निविदा का भाग-एक दिनांक 18.03.2026 को 15:30 बजे खोला जायेगा।

अन्य नियम व शर्तें मूल ई-निविदा के अनुसार रहेंगी। अन्य विवरण के लिए कृपया वेबसाईट www.uktenders.gov.in. को देखें।

अधीक्षण अभियन्ता कारपोरेट (अनुबन्ध एवं क्रय-द्वितीय)

"राष्ट्र हित में बिजली बचायें, बिजली बचाने हेतु एल.ई.डी. बल्ब का प्रयोग करें।
(टोल फ्री नं0 1912) विद्युत बिलों के 24X7 ऑनलाईन भुगतान हेतु www.upcl.org पर जाएँ
(विद्युत चोरी की सूचना टोल फ्री नं0 18001804185/फैक्स नं0 0135-2760911 पर दें)

झंडे जी के दर्शन के लिए उमड़ी संगत नगर परिक्रमा में दिखा आस्था का संगम

शाह टाइम्स संवाददाता

देहरादून। झंडे जी के आरोहण के तीसरे दिन मंगलवार को नगर परिक्रमा निकाली गई। श्रीमहंत देवेंद्र दास महाराज की अगुवाई में हजारों श्रद्धालु नगर परिक्रमा में शामिल हुए। सुबह से ही संगत बड़ी संख्या में दरबार साहिब में जुटी थी इसके बाद नगर परिक्रमा शुरू हुई।

श्रीमहंत देवेंद्र दास महाराज ने कहा कि गुरु की शरण में आकर ही मनुष्य को सच्चे मार्ग का ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु की वाणी अमृत के समान है जो मानव जीवन को पवित्र और सफल बनाती है। उन्होंने कहा कि भक्ति, सेवा और सत्कर्म ही मानव जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरु का स्मरण करता है, उस पर सद्गुरु की असीम कृपा बरसती है। दरबार साहिब से नगर परिक्रमा शुरू हुई। इसके बाद सहारनपुर चौक, कांवली रोड होते हुए एसजीआरआर बिंदाल, तिलक रोड, चकराता रोड, घंटाघर, पलटन बाजार से होकर दरबार साहिब पहुंचकर सम्पन्न हुई। इस दौरान एसजीआरआर में गन्ने का प्रसाद बांटा गया। मेला अधिकारी विजय गुलाटी ने बताया कि नगर परिक्रमा दूनवासियों के लिए भी ऐतिहासिक क्षण होता है, जब देश-विदेश की संगत उनके बीच होती है।

एसएसपी ने 417 नवनियुक्त पुलिस आरक्षियों को सौंपे नियुक्ति पत्र

देहरादून। राजधानी के पुलिस लाइन में मंगलवार को आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा उत्तराखंड पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस/पीएसी सीधी भर्ती-2025 में सफल रहे 417 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। पुलिस विभाग में आधिकारिक रूप से शामिल होने पर चयनित युवाओं के चेहरों पर उत्साह और भविष्य के प्रति संकल्प दिखाई दिया।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसएसपी देहरादून ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को पुलिस परिवार का हिस्सा बनने पर हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पुलिस के सामने तकनीक और अपराध के बदलते स्वरूपों के कारण कई नई चुनौतियां उभरी हैं। इन चुनौतियों का कुशलतापूर्वक सामना करने और आम जनता के बीच पुलिस की छवि को और अधिक बेहतर व विश्वसनीय बनाने के लिए एक पुलिसकर्मी का शारीरिक तथा मानसिक रूप से सुदृढ़ होना आवश्यक है। एसएसपी ने युवाओं को आधारभूत प्रशिक्षण के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने अभ्यर्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि आगामी ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाने वाली हर बात को पूर्ण लगन और मनोयोग से आत्मसात करें। उन्होंने जोर दिया कि प्रशिक्षण के दौरान सीखी गई बातें ही भविष्य में फील्ड में कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान काम आएंगी।अंत में एसएसपी देहरादून ने सभी नवनियुक्त आरक्षियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें पूरी निष्ठा के साथ जनसेवा करने का मंत्र दिया।

विद्युत आपूर्ति को सुचारू एवं विश्वसनीय बनाए रखें

■ आगामी चारधाम यात्रा एवं ग्रीष्मकाल को लेकर दिए निर्देश

शाह टाइम्स संवाददाता

देहरादून। देवभूमि उत्तराखण्ड में शीघ्र प्रारम्भ होने वाली विश्वविख्यात चारधाम यात्रा तथा ग्रीष्मकाल के दौरान प्रदेश में विद्युत मांग में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रबन्ध निदेशक, यूपीसीएल द्वारा विद्युत व्यवस्था को सुचारू, विश्वसनीय एवं उपभोक्ता हितैषी बनाए रखाने हेतु सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

यूपीसीएल प्रदेश के सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण, सतत एवं किफायती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए निरन्तर प्रतिबद्ध है। ग्रीष्मकाल में तापमान वृद्धि के साथ विद्युत की मांग में तीव्र वृद्धि होने की संभावना रहती है। साथ ही आगामी चारधाम यात्रा के दौरान राज्य में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए विद्युत आपूर्ति की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रबन्ध निद. ेशक ने विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि चारधाम यात्रा मार्गों, धाम क्षेत्रों तथा प्रमुख पड़ावों में गुणवत्तापूर्ण एवं स्थिर वोल्टेज के साथ विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि यात्रियों, स्थानीय निवासियों एवं यात्रा प्रबंधन से जुड़े संस्थानों को किसी प्रकार की विद्युत समस्या का सामना न करना पड़े। यूपीसीएल द्वारा यात्रा मार्गों पर स्थित विद्युत अवसंरचना की पूर्व समीक्षा एवं आवश्यक सुदृढ़ीकरण कार्य भी सुनिश्चित किए जा रहे है। प्रबन्ध निदेशक स्वयं चारधाम यात्रा से संबंधित विद्युत व्यवस्था की सतत निगरानी कर रहे हैं।

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
कारपोरेट आईडेन्टीटी संख्या : U40109UR2001SGC025867, कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, (दक्षिण), 18-ई0सी0 रोड, देहरादून

विद्युत बाधित सूचना

कृपया उपरोक्त विषयक आपके संज्ञान में लाना है कि इस खण्ड के अन्तर्गत आने वाले उपखण्ड-निरंजनपुर के क्षेत्राधीन 33/11 के०वी० उपसंस्थान निरंजनपुर के अन्तर्गत 33 के0वी0 माजरा-निरंजनपुर लाईन पर अनुरक्षण एवं सुपरविजन का कार्य किया जाना प्रस्तावित है, जिस कारण 33/11 के0वी0 उपसंस्थान निरंजनपुर से पोषित होने वाले समस्त क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति अंकित तिथि में पूर्ण/आंशिक रूप से बाधित रहेगी।

दिनांक	समय	33/11 उपसंस्थान का नाम	11 के०वी० फीडर का नाम	बाधित क्षेत्र
12.03.2026, 14.03.2026, 16.03.2026 एवं 17.03.2026	प्रातः 10:00 से सांय 5:00 बजे तक	निरंजनपुर	समस्त फीडर	33/11 के0वी0 उपसंस्थान से पोषित समस्त क्षेत्र

अतः समस्त सम्मानित उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की जाती है।

No.:- 176/EE(CM)/UPCL/A-2 Date:- 10.03.2026 अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्र हित में बिजली बचायें, बिजली बचाने हेतु एल0ई0डी0 बल्ब का प्रयोग करें। (टोल फ्री नं0 1912) विद्युत बिलों के 24x7 ऑनलाइन भुगतान हेतु www.upcl.org पर जाए। (विद्युत चोरी की सूचना टोल फ्री नं0 1800 180 4185/फैक्स संख्या- 0135-2760911 पर दें।)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०
विद्युत वितरण खण्ड, बड़कोट
CAN- UA 40109 UP 2001 SGC 025867

ई-निविदा सूचना

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बड़कोट के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यों को कराने हेतु जो कि आयकर, जी०एस०टी० में पंजीकृत हों, से मुहरबन्द निविदायें दो भागों में (प्रथम भाग में धरोहर धनराशि, निविदा प्रपत्र, सम्बन्धित प्रपत्र, नियम शर्तें एवं द्वितीय भाग में दरें) जो कि अनुबन्ध की तिथि से 180 दिन तक वैध हों, ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, निविदा में प्रथम भाग में लगाये जाने वाले प्रपत्र का मूल्य विवरण तथा अन्य समस्त नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र से अवलोकन करना सुनिश्चित करे, जो कि उत्तराखण्ड शासन की ई-निविदा वेबसाइट www.uktenders.gov.in पर प्राप्त किये जा सकते है।

ई-निविदा संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (जी०एस०टी० अतिरिक्त) रू० लाख में	निविदा शुल्क (जी०एस०टी० सहित) रू० लाख में	धरोहर धनराशि रू० लाख में	निविदा क्रय करने हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं समय	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन एवं ऑफ लाईन जमा करने की अन्तिम तिथि एवं समय	ऑनलाईन एवं ऑफ लाईन निविदा खुलने की तिथि एवं समय
28/2025-26	विद्युत वितरण खण्ड बड़कोट के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड बडकोट के लिए किराये पर 01 नं० डीजल चालित वाहन बोलेरो मय चालक सहित दो वर्ष हेतु। (वाहन का माडल 2024 से पूर्व का ना हों)	7.89	1180.00	0.24	27.03.2026 (16:30 बजे तक)	27.03.2026 (16:30 बजे तक)	28.03.2026 (12:30 बजे तक)
29/2025-26	विद्युत वितरण खण्ड बडकोट के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड बडकोट के लिए किराये पर 01 नं० डीजल चालित वाहन बोलेरो मय चालक सहित दो वर्ष हेतु। (वाहन का माडल 2024 से पूर्व का ना हों)	7.89	1180.00	0.24	27.03.2026 (16:30 बजे तक)	27.03.2026 (16:30 बजे तक)	28.03.2026 (12:30 बजे तक)
30/2025-26	विद्युत वितरण खण्ड बडकोट के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड पुरोला के लिए किराये पर 01 नं० डीजल चालित वाहन बोलेरो मय चालक सहित दो वर्ष हेतु। (वाहन का माडल 2024 से पूर्व का ना हों)	7.89	1180.00	0.24	27.03.2026 (16:30 बजे तक)	27.03.2026 (16:30 बजे तक)	28.03.2026 (12:30 बजे तक)

पत्रांक : 847/वि०वि०ख०ब०/टी०-7 दिनांक : 09/03/2026 अधिशासी अभियंता

"राष्ट्र हित में बिजली बचायें" "टोल-फ्री नं० -1912"

बाइक चोरी गैंग का पर्दाफाश, एक मैकेनिक सहित दो गिरफ्तार, 10 दोपहिया वाहन बरामद

कप्तान ने ज्वालापुर पुलिस की थपथपाई पीठ

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं का पुलिस ने खुलासा करते हुए दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे और निशानदेही पर चोरी की 10 दोपहिया गाड़ियां बरामद की गई हैं, जिनमें 8 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी शामिल हैं। बरामद वाहनों में पांच वाहन देहरादून जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज चोरी के मामलों से संबंधित पाए गए हैं।पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है।

हरिद्वार एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने ज्वालापुर कोतवाली में प्रेस वार्ता कर बताया कि जनपद में वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में ज्वालापुर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने बताया कि 5 मार्च को शुभम कुमार पुत्र जहान सिंह निवासी इस्माइलखेड़ा, थाना पिरान कलियर ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनकी एचएफ डीलक्स बाइक 4 मार्च को ज्वालापुर स्थित ऊंचा पुल के पास महाराजा फर्नीचर के निकट से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई है। इस संबंध में ज्वालापुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी।घटना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी जुटाई। साथ ही संभावित ठिकानों पर दबिश देते हुए लगातार चेकिंग अभियान चलाया गया। 9 मार्च 2026 को पुलिस टीम ने नहर पटरी स्थित रेगुलेटर पुल के पास चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध युवकों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने ज्वालापुर क्षेत्र से बाइक चोरी करने की बात कबूल की। एसपी सिटी अभय प्रताप ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर पुरानी कांवड़ पटरी के पास एक खंडहर में छिपाकर रखे गए 8 मोटरसाइकिल और 02 स्कूटी बरामद कीं। आरोपियों ने बताया कि वे हरिद्वार और देहरादून के विभिन्न इलाकों से बाइक और स्कूटी चोरी कर सुनसान स्थानों पर छिपा देते थे और मौका मिलने पर उन्हें बेचने की फिराक में रहते थे। ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मौसिन पुत्र जावेद आलम तथा गुलशन पुत्र वलीन निवासी ग्राम गढ़ोवाली, थाना पथरी, जनपद हरिद्वार के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपी कम पढ़े-लिखे हैं। मौसिन राजमिस्त्री का काम करता है जबकि गुलशन मैकेनिक है और वाहनों की जानकारी होने के कारण चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। पुलिस के अनुसार बरामद वाहनों में पांच वाहन देहरादून जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज चोरी के मामलों से संबंधित पाए गए हैं। आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाई जा रही है।

पुलिस टीम में कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा, वरिष्ठ उप निरीक्षक खेमेंद्र गंगवार, चौकी बाजार प्रभारी उप निरीक्षक अंकुल अग्रवाल, उप निरीक्षक मनीष भंडारी, उप निरीक्षक गंभीर तोमर, कां. गणेश तोमर, कां. रवि चौहान, कां. कपिल गोला, कां. आलोक नेगी, कांस्टेबल नितेश कुमार, कांस्टेबल मनोज डामवाल, कां. अंकुर चौधरी शामिल रहे। प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह, सीओ ज्वालापुर संजय चौहान, आदि मौजूद रहे।

कुंभ मेला की तैयारियां तेज, भीमगोडा कुंड का होगा सौंदर्यीकरण

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। आगामी कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए मेला प्रशासन द्वारा कुंभ क्षेत्र के पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों के जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण की योजना पर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में पौराणिक महत्व वाले भीमगोडा कुंड के सौंदर्यीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका के निर्देश पर मंगलवार को अपर मेलाधिकारी दयानन्द सरस्वती ने तकनीकी विशेषज्ञों की टीम के साथ भीमगोडा कुंड का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुंड में पौराणिक स्रोत से जल आपूर्ति की व्यवस्था, कुंड में एकत्रित जल की समुचित निकासी, संरचनात्मक सुधार तथा सौंदर्यीकरण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान स्थानीय पार्षद सुमित चौधरी और क्षेत्रीय नागरिकों ने भी सुझाव दिए गए, ताकि विकास कार्य स्थानीय परंपराओं और भावनाओं के अनुरूप किए जा सकें। निरीक्षण दल में कुंभ मेला तकनीकी प्रकोष्ठ के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार, सहायक अभियंता एस.के. तोमर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

अपर मेलाधिकारी दयानन्द सरस्वती ने बताया कि भीमगोडा कुंड के पौराणिक स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए इसे अधिक आकर्षक और सुविधाजनक बनाया जाएगा। कुंड में निरंतर स्वच्छ जल उपलब्ध कराने के लिए प्राचीन जल स्रोत से पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और जल निकासी की समुचित व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे स्वच्छता बनी रहे। उन्होंने बताया कि कुंड के चारों ओर एक सुंदर पार्क विकसित किया जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैठने हेतु बेंच, सुरक्षा के लिए मजबूत रेलिंग, सुरक्षित मार्ग तथा समुचित प्रकाश व्यवस्था भी की जाएगी। कुंभ मेले में देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को इस पौराणिक स्थल के दर्शन कराने और इसकी ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से मेला प्रशासन इस कार्य पर विशेष ध्यान दे रहा है। भीमगोडा कुंड का धार्मिक और पौराणिक महत्व भी अत्यंत विशेष माना जाता है। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों के वनवास के दौरान भीम ने अपनी गदा अथवा चरण प्रहार से यहां जल स्रोत प्रकट किया था, जिसके कारण यह स्थल भीमगोडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। समय के साथ यह स्थान श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया और हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु यहां दर्शन व जल स्पर्श को अत्यंत पुण्यकारी मानते हैं।

मारपीट कर शांति व्यवस्था भंग करने वाले छह आरोपी गिरफ्तार

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। नगर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर शांति व्यवस्था भंग करने के मामले में पुलिस ने छह आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।

नगर कोतवाली प्रभारी रितेश शाह ने बताया कि शिवमूर्ति चौक मायापुर के पास सोमवार रात एक दुकान से सामान खरीद रहे व्यक्ति के साथ किसी बात को लेकर छह युवकों ने एक राय होकर जमकर मारपीट कर दी। घटना के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया और तस्दीक के बाद मारपीट कर क्षेत्र की शांति व्यवस्था भंग करने वाले छह आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सभी के खिलाफ शांति भंग करने के मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपियों में नीरज पुत्र अनिल कुमार निवासी राजीव नगर कॉलोनी मायापुर, अश्विनी उर्फ गोल्डी पुत्र धर्मेंद्र निवासी राजीव नगर मायापुर, सौरभ उर्फ अमन बेदी पुत्र नंदलाल निवासी राजीव नगर कॉलोनी मायापुर, अंकुश पुत्र अनिल कुमार निवासी राजीव नगर मायापुर, सुजल पुत्र विकास निवासी राजीव नगर मायापुर और आशीष पुत्र अनिल कुमार निवासी राजीव नगर मायापुर शामिल हैं। पुलिस टीम में नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह, मायापुर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक आशीष नेगी, अपर उपनिरीक्षक दिनेश कुमार, कांस्टेबल अर्जुन कुमार और कांस्टेबल अनिल कुमार शामिल रहे।

डीएम ने एआरटीओ कार्यालय का किया औचक निरीक्षण

आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए दिए निर्देश

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। जनपद में सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने और आमजन को मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लेने के क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मंगलवार को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) कार्यालय हरिद्वार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कार्यालय की व्यवस्थाओं, नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं और प्रवर्तन गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि परिवहन कार्यालय में अपने कार्यों के लिए आने वाले लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर और समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली पारदर्शी और जनहितकारी होनी चाहिए तथा लोगों का विश्वास बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। जिलाधिकारी ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया की भी बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ड्राइविंग लाइसेंस केवल निर्धारित नियमों और उचित ड्राइविंग परीक्षण के आधार पर ही जारी किए जाएं। ताकि सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके और अयोग्य व्यक्तियों को लाइसेंस न मिल सके। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने एआरटीओ कार्यालय परिसर और आसपास की व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय परिसर में साफ-सफाई की स्थिति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिसर में नियमित रूप से स्वच्छता बनाए रखी जाए और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यालयों में स्वच्छ और व्यवस्थित वातावरण होना बेहद आवश्यक है, जिससे वहां आने वाले लोगों को सकारात्मक अनुभव मिले। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने कार्यालय परिसर के बाहर संचालित दुकानों और ढाबों के संबंध में भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यालय परिसर के आसपास किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को बैठने या दुकान लगाने की अनुमति न दी जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी गतिविधियों के कारण अनावश्यक भीड़भाड़ होती है और लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है, इसलिए इसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। प्रवर्तन कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से चेकिंग अभियान चलाए जाएं। साथ ही उन्होंने रात्रिकालीन चेकिंग को भी नियमित रूप से संचालित करने के निर्देश दिए, ताकि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से यह भी कहा कि परिवहन विभाग की सेवाओं को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए तकनीकी संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाए। उन्होंने आमजन को ऑनलाइन सुविधाओं के बारे में भी जागरूक करने पर जोर दिया, जिससे लोगों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। निरीक्षण के दौरान एआरटीओ (प्रशासन) निखिल शर्मा, एआरटीओ (प्रवर्तन) नेहा झा सहित विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

पहले ही प्रयास में सीए बनी आयुषी अग्रवाल को सम्मानित

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। श्री वैश्य बंधु समाज मध्य क्षेत्र हरिद्वार के पदाधिकारियों ने पहले ही प्रयास में सीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली गोविंदपुरी निवासी कु. आयुषी अग्रवाल पटका पहनाकर एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। श्री वैश्य बंधु समाज मध्य क्षेत्र हरिद्वार के संस्थापक अशोक अग्रवाल ने कहा कि संस्था से जुड़े डा.अजय अग्रवाल एवं पूजा अग्रवाल की पुत्री आयुषी अग्रवाल ने मेहनत, लगन और समर्पण से पहले ही प्रयास में प्रतिष्ठापूर्ण सीए परीक्षा समस्त वैश्य समाज का नाम रोशन किया है। आयुषी की सफलता से अन्य छात्र-छात्राओं को भी प्रेरणा मिलेगी। आयुषी अग्रवाल ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता

और अध्यापकों को देते हुए कहा कि परिवार से मिले सहयोग और गुरूजनों के मार्गदर्शन से वे ही सफलता हासिल कर पायी हैं। संस्था के अध्यक्ष विनीत अग्रवाल, रविंद्र कुमार गुप्ता, महावीर प्रसाद मित्तल एवं माध्विक मित्तल ने भी आयुषी अग्रवाल को बधाई दी।

बाणगंगा में अवैध खनन का आरोप लगाया

अवैध खनन के लिए जिम्मेदार लोगों पर की जाए कार्रवाई : फैजान

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ताओं ने बाण गंगा में अवैध खनन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए भारतीय किसान यूनियन तोमर के मीडिया सलाहकार फैजान ने बताया कि निहंदपुर सुठारी गांव के पास बहने वाली बाणगंगा नदी में परमिशन की आड़ में पोकलैंड और जेसीबी मशीनों से बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा है। जिससे नदी और आसपास के क्षेत्र को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। फैजान ने बताया कि खनन करने वाले लोग नदी क्षेत्र में गहरे गहरे गड्ढे खोद रहे हैं। इसके साथ ही गरीबों को आवंटित किए गए पट्टों की जमीन भी खोदी जा रही है। अवैध खनन के लिए खोदे गए गड्ढों के कारण कई बार हादसे हो चुके हैं। गड्ढों के कारण कई ग्रामीणों की जान भी जा चुकी है। इसके बावजूद अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अवैध खनन पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। खनन केवल सरकार द्वारा तय नीतियों और नियमों के अनुसार ही कराया जाना चाहिए, ताकि पर्यावरण और स्थानीय लोगों की सुरक्षा बनी रहे। उन्होंने मांग की कि सरकारी भूमि पर आवंटित किए गए पट्टों की भी निष्पक्ष जांच कराई जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रेसवार्ता में आदिल हसन, गुलजार मोहम्मद, खालिद, भी मौजूद रहे।

ज्वालापुर में किराये के कमरों का ताला तोड़कर कब्जा, विरोध करने पर धमकी

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में किराये पर देने के लिए बने कमरों का ताला तोड़कर कब्जा करने और विरोध करने पर मकान मालिक को धमकाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भूपतवाला की पीपल वाली गली निवासी हरीशचंद्र शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी जमीन ज्वालापुर के अहबाबनगर, अहमदपुर कड़च्छ क्षेत्र में स्थित है। यहां उन्होंने किराये पर देने के लिए करीब दस कमरे बनवा रखे हैं, जिनमें से दो कमरों में लंबे समय से किरायेदार रह रहे थे।

आरोप है कि 27 फरवरी की दोपहर भूपेंद्र नामक व्यक्ति अपने 15 से 20 साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और दोनों कमरों के ताले तोड़ दिए। इसके बाद किरायेदारों का सामान बाहर फेंककर कमरों पर कब्जा कर लिया। मकान मालिक के अनुसार सूचना मिलने पर जब वह मौके पर पहुंचे तो आरोपितों ने उनके साथ अभद्रता की और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच के आधार पर नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज्वालापुर कोतवाली प्रभारी कुंदन सिंह राणा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

स्वामी शांति स्वरूपानंद को झूठे केस में फंसाने की राजिश रचने के आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए : रविंद्रपुरी

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद एवं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने म.मं. स्वामी शांति स्वरूपानंद को रेप के झूठे केस में फंसाने की साजिश की निंदा करते हुए मध्य प्रदेश सरकार से आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग की है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने कहा कि म.मं. स्वामी शांति स्वरूपानंद को पद से हटाने के लिए उन्हें रेप के झूठे केस में फंसाने की राजिश रचने वाली पूर्व म.मं. मंदाकिनी पुरी और उसके सहयोगी मीडियाकर्मी पर सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दोनों को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। श्रीमहंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि म.मं. स्वामी शांति स्वरूपानंद विद्वान और प्रतिष्ठित संत हैं। म.मं. स्वामी शांति स्वरूपानंद ने उज्जैन में चारधाम मंदिर की स्थापना की है। धर्म प्रचार के साथ वे विभिन्न सेवा प्रकल्पों के माध्यम से मानव कल्याण में भी योगदान कर रहे हैं। ऐसे संत के खिलाफ साजिश रचकर पूरे संत समाज की छवि धूमिल करने का प्रयास करने वाले कालनेमियों के खिलाफ अखाड़ा परिषद अपने स्तर से भी कड़ी कार्रवाई करेगा। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ तथाकथित संत धन और पद के लोभ में वरिष्ठ संतों को निशाना बना रहे हैं। संतों को झूठे मामलों में फंसाकर पूरे संत समाज की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। जल्द ही अखाड़ा परिषद की बैठक बुलाकर तथाकथित संतों ओर कालनेमियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और श्रद्धालु भक्तों को भी जागरूक किया जाएगा। युवा भारत साधु समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी शिवम महंत, राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी रविदेव शास्त्री, स्वामी दिनेश दास, स्वामी नागेंद्र महाराज, महंत गोविंद दास ने भी म.मं. स्वामी शांति स्वरूपानंद को झूठे मामले में फंसाने की साजिश की निंदा करते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड सरकार से संत महापुरूषों को बदनाम कर सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश कर रहे साधुवेश धारी कालनेमियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

दो थाना क्षेत्रों से दो नाबालिग किशोरियां लापता, पुलिस ने शुरू की तलाश

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। नगर कोतवाली और कनखल थाना क्षेत्र से दो नाबालिग किशोरियों के लापता होने के मामले सामने आए हैं। एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया गया है, जबकि दूसरी घर से सामान लेने निकली थी और वापस नहीं लौटी। पुलिस ने दोनों मामलों में शिकायत दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

नगर कोतवाली क्षेत्र के लालजीवाला निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी 15 वर्षीय पुत्री आठ मार्च की रात घर से अचानक गायब हो गई। परिजनों का आरोप है कि पड़ोस में रहने वाला अजीत चौहान उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है।

वहीं, कनखल थाना क्षेत्र में भी 14 वर्षीय किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। परिजनों के अनुसार वह आठ मार्च की शाम करीब साढ़े सात बजे घर से बर्गर लेने के लिए घर से निकली थी, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने आसपास के इलाकों, रिश्तेदारों और परिचितों के यहां तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा।

दोनों मामलों में संबंधित थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि किशोरियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें लगाई गई हैं और आसपास के क्षेत्रों में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित, सैकड़ों लोगों ने कराई जांच

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। वार्ड 60 की पार्षद आकर्षिका के नेतृत्व में जया मैक्सवेल हॉस्पिटल द्वारा जर्स कंट्री, ज्वालापुर में निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ पार्षद आकर्षिका ने किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना उनका मुख्य उद्देश्य है और ऐसे शिविर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने लोगों की स्वास्थ्य जाँच कर आवश्यक परामर्श दिया। इसमें डॉ. यश (जनरल फिजिशियन), डॉ. गौरी लक्ष्मी (स्त्री रोग विशेषज्ञ), डॉ. शिवम शर्मा (जनरल सर्जन) और डॉ. मौसम जाफरिन (हृदय रोग विशेषज्ञ) शामिल रहे। डॉक्टरों ने मरीजों की जांच करने के साथ ही उन्हें स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए जरूरी सलाह भी दी।

शिविर में ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर की निःशुल्क जांच की गई, जिससे लोगों को अपनी स्वास्थ्य स्थिति की तुरंत जानकारी मिल सकी। क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोगों ने शिविर में पहुंचकर अपनी स्वास्थ्य जांच कराई और विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श लिया। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने कहा कि ऐसे शिविरों से उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों से सीधे परामर्श लेने का अवसर मिलता है, जो सामान्य अस्पतालों में समय और खर्च के कारण कई बार संभव नहीं हो पाता। पार्षद आकर्षिका ने कहा कि भविष्य में भी क्षेत्र में ऐसे जनहित कार्य और स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि नियमित स्वास्थ्य जांच और समय पर परामर्श से कई गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। ज्वालापुर में आयोजित यह शिविर लोगों के लिए लाभकारी साबित हुआ और इससे क्षेत्र में स्वास्थ्य जागरूकता भी बढ़ी।

अपर मेलाधिकारी को दिया ज्ञापन

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष डा. विशाल गर्ग के नेतृत्व में व्यापारियों ने अपर मेलाधिकारी दयानंद सरस्वती को ज्ञापन देकर कुंभ मेला क्षेत्र में दुकानों पर लगाए जा रहे बोर्ड पर जीएसटी एवं मोबाइल नंबर अंकित करने की मांग की है। इस दौरान डा.विशाल गर्ग ने कहा कि कुंभ मेला क्षेत्र में दुकानों के समक्ष एक समान बोर्ड लगाए जा रहे हैं और उन पर दुकानदारों और दुकानों के नाम अंकित किए जा रहे हैं। लेकिन बोर्ड पर जीएसटी नंबर एवं मोबाइल नंबर नहीं अंकित किए जा रहे हैं। मेला प्रशासन को बोर्ड पर जीएसटी नंबर एवं दुकानदार का मोबाइल नंबर भी अवश्य अंकित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल पंजीकृत और मान्यता प्राप्त व्यापारिक संगठन है। इसलिए कुंभ मेला प्रशासन द्वारा आयोजित की जा रही बैठकों की सूचना प्रांतीय नगर उद्योग व्यापार मंडल को भी दी जाए।

होली पर्व के दिन रंग खेलने को लेकर हुई मारपीट में पांच के खिलाफ मुकदमा दर्ज

शाह टाइम्स संवाददाता

पथरी। थाना क्षेत्र के गांव बिशनपुर झरडा होली पर पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षो में झगड़ा हो गया था। एक पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार होली पर्व पर दो पक्षो के बीच हुए झगड़े में एक पक्ष सुशीला की तहरीर पर पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित की माँ सुशीला ने बताया मेरा बेटा हर्ष अपने घर से खाने का सामान लेने के लिये गाँव में ही दुकान पर जा रहा था तभी रास्ते में पहले से रंजीश रखते हुए निशु पुत्र पवन, उमाकान्त पुत्र सन्तराम, जशबीर पुत्र स्व० नन्दकिशोर, विनीत पुत्र मदन, शुभम पुत्र स्व० सौराज निवासी ग्राम बिशनपुर ने हर्ष को रोककर गंदी गंदी मां बहन की गाली गलोच करने लगे। हर्ष के विरोध करने पर सभी व्यक्तियों ने उस पर जानलेवा हमला करते हुए सर पर हथौड़े से हमला कर दिया जिस से हर्ष बेहोश होकर नीचे गिर गया अन्य व्यक्तियों ने उस पर कई वार लाठी डंडों से हमला दिया। मोके पर गाली गलोच का शोर सुनकर मौके पर राजेश, मोन्टी, हिमांशु, मौके पर पहुँचे इन्होने बीच बचाव छुडाने का प्रयास किया तो इन भी लाठी डंडों से जान लेवा हमला कर दिया। तभी हर्ष को सरकारी हॉस्पिटल लेकर गये हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार होन के बाद डा. द्वारा हर्ष की तबीयत खराब देखते हुऐ हर्ष को हायर सेन्टर रेफर कर दिया। हर्ष को वहा से भूमानन्द हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जहाँ पर डॉक्टरों ने हर्ष की गंभीर अवस्था को देखते हुए आई.सी.यू. में भर्ती कर दिया है। एसओ पथरी मनोज नोटियाल ने बताया होली पर्व पर बिशनपुर में हुए झगड़े में एक पक्ष की ओर से पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है जांच कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

बिजली संशोधन बिल के विरोध में केंद्र सरकर के खिलाफ प्रदर्शन

ऊर्जा निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों ने बिल वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी

शाह टाइम्स संवाददाता

हरिद्वार। विद्युत संशोधन बिल के विरोध में ऊर्जा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और बिल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के विद्युत एमेण्डमेन्ट बिल-2025 वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन और विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर मायापुर स्थित ऊर्जा निगम कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान अभियंता संघ के उपाध्यक्ष अनिल कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया कि सरकार ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण करने जा रही है। इसलिए विद्युत संशोधन बिल को संसद में पेश करने की तैयारी की जा रही है। अनिल मिश्रा ने आरोप लगाया कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बिल लाया गया है। यदि यह बिल पास होता है, तो आने वाले समय में निजी कंपनियां अपनी मनमर्जी के अनुसार उपभोक्ता चुनेंगी। बीपीएल, किसान और मजदूर वर्ग को सस्ती बिजली नहीं देंगे। इसके साथ ही ऊर्जा निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों की नौकरी खतरे में आ जाएगी। निजी क्षेत्र की कम्पनियां मनमाने ढंग से कार्य करेंगी। बिल ऊर्जा निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों की उपेक्षा का प्रयास है। ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता दीपक सैनी ने चेतावनी देते हुए कहा यदि सरकार विद्युत संशोधन बिल 2025 को वापस नहीं लेती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर उत्तराखंड के सभी विद्युत अधिकारी और कर्मचारी बड़े स्तर पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। प्रदर्शन करने वालों में अधिशासी अभियंता दीपक सैनी, अनूप सैनी, आशुतोष तिवारी, सैयद सिराज उस्मान, सहायक अभियंता प्रियंका अग्रवाल, अश्वनी कुमार, आलोक चौहान, मनोज कंसल, रीता राजपूत, अमित कुमार, दिवाकर गौड़, लेखाकार मुकेश वार्ष्णेय, हेमंत मलिक, आई.पी.सिंह, सचिव स्वयं सहायता समूह सुनील कुमार, प्रदीप बलौदी, सत्य प्रकाश, कुलदीप सिंह, दिव्या चौधरी, सुनील कुमार, रिजवान अली, राहुल कुमार, नीरज कुमार, सुनील कुमार, धर्म सिंह समेत अन्य विद्युत अधिकारी और कर्मचारी शामिल रहे।

पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में मारपीट

महिला सहित आठ लोगों पर क्रॉस मुकदमा दर्ज

शाह टाइम्स संवाददाता

पथरी। क्षेत्र के गांव कटारपुर में दो पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते मामूली बात को लेकर गाली गलौज व मारपीट हो गई। मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर क्रॉस मुकदमा दर्ज किया है। मामले की जांच कर कार्रवाई अमल में लाई जायेगी। पुलिस के अनुसार थाना पथरी क्षेत्र के गांव कटार पुर में 26 फरवरी को साम लगभग आठ नौ बजे पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में किसी बात को लेकर गाली गलोज व मारपीट हो गई। मामले में एक पक्ष के मांगेराम पुत्र चौहल सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि गांव के ही रहने वाले आदित्य, अल्का, परवीन और नितिश ने वादी के पुत्र की मोटरसाइकिल रास्ते में रोककर गाली गलौज करते हुए रात घुसो से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी है। वही, दूसरे पक्ष कटार पुर निवासी प्रवीण पुत्र नाथीराम ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि मांगेराम पुत्र चौहल, अभिनव, हिमांशु पुत्र मांगे राम और पुत्री तमन्ना द्वारा सभी एक राय होकर वादी के घर में घुसकर गाली गाली गलौज करते हुए रात घुसो से मारपीट की है, और जाते समय जान से मारने की धमकी दी है। सोमवार को मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर क्रॉस मुकदमा दर्ज कर किया है। दोनों पक्षों की तहरीर पर महिला सहित आठ लोगों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में जांच के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पथरी थाना अध्यक्ष मनोज नौटियाल ने बताया कि दोनों पक्षों की और से तहरीर आई है। तहरीर आधार पर मारपीट के मामले में संबंधित धाराओं में क्रॉस मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच कर कार्रवाई की जायेगी।

सूचना (संबंध विच्छेद)

मैंने अपने पुत्र इन्तजार, शाहजहां पत्नी इन्तजार व इस्तकार, रिहाना उर्फ रीना पत्नी इस्कार को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर अपने सभी संबंध विच्छेद कर लिये है। भविष्य में इन सभी के किसी भी कृत्य व लेन-देन की जिम्मेदारी मेरी व मेरे परिवार की नीं होगी। मुस्तकीम पुत्र कासिम व श्रीमती आसिया पत्नी मुस्तकीम, निवासीगण रामपुर थाना को0 गंगनहर, तहसील रूड़की, जिला हरिद्वार।

हरिद्वार में समाचार व विज्ञापन के लिये सम्पर्क करें।

सैफ सलमानी

ब्यूरो चीफ

शाह टाइम्स हरिद्वार

कार्यालय : रामनगर, तहसील के पीछे, ज्वालापुर, हरिद्वार

मो.: 9639554327, ई-मेल : shahtimeshr2026@gmail.com

उत्तराखंड में छाएगा बिजली संकट! निजीकरण के खिलाफ हड़ताल का ऐलान, कर्मचारियों ने दी सरकार को चेतावनी

बड़कोट : निजात के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने किया धरना-प्रदर्शन

शाह टाइम्स संवाददाता

उत्तरकाशी : उत्तराखंड में निजीकरण के खिलाफ उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल), उत्तराखंड जल विद्युत निगम (यूजेवीएनएल) और पिटकुल (पीटीसीयूएल) के समस्त अधिकारी, कर्मचारी और अभियंता मुखर होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली संशोधन बिल 2025 और निजीकरण की प्रस्तावित नीतियों के विरोध में कर्मचारियों ने देशव्यापी आंदोलन के साथ उत्तराखंड में भी अपने-अपने खंड (क्पअपेपवद) और मंडल (ब्पतबसम) स्तर पर आंदोलन शुरू कर दिया है।

मंगलवार को उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने यमुना घाटी के

विद्युत वितरण खंड बड़कोट कार्यालय में समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है।

इस दौरान बिजली कर्मचारीयों ने निजीकरण को जनविरोधी कदम मानते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की हैं। उनका मानना है कि निजीकरण से बिजली की दरें बढ़ेंगी और आम उपभोक्ताओं व किसानों पर बोझ पड़ेगा। वहीं यूपीसीएल के संविदा कर्मी (न्च्छस् कर्मी) भी निजीकरण के फैसले से प्रभावित होगा, क्योंकि इससे उनकी नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है।

उत्तराखंड में बिजली कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ कार्य बहिष्कार और राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने की चेतावनी दी है, जिससे राज्य में बिजली संकट पैदा हो सकता है।

इस मौके पर उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा से यमुना घाटी से संयोजक अजय सेमवाल, अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह मराठा, सचिव संतोष शाह, उपाध्यक्ष जगत नेगी, संगठन मंत्री मोहन विश्वकर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज कुमार, नीरज नौटियाल, मनीषा ज्याडा, मीना देवी, बुद्धि सिंह, प्रेम लाल, सुमन सेमवाल, आशीष कुमार, नवीन कुमार, सुनील राणा, सुनील शाह, नरेश लाल कार्यवाहक अध्यक्ष विपिन रावत आदि मौजूद रहे है।

निजीकरण की नीति पर पुनर्विचार करें सरकार:

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावित हड़ताल और आंदोलन के दौरान यदि बिजली आपूर्ति में किसी तरह का व्यवधान होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ।प्च्म्थ् ने केंद्र और राज्य सरकारों से अपील की है कि वे निजीकरण की नीति पर पुनर्विचार करें और सार्वजनिक हित में बिजली क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कर्मचारियों के साथ सार्थक बातचीत करें।

कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने सुमन पार्क को खोलने की मांग

नई टिहरी। ऐतिहासिक सुमन पार्क, जिसका पिछले एक लम्बे समय से जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था,वह संपन्न हो चुका है। सुमन पार्क से रिश्ता रखने वाले नागरिकों ने पार्क में उठना-बैठना शुरू भी कर दिया है लेकिन पार्क के गेट पर अभी भी ताला लगा हुआ है। मजबूरीवश लोग दीवार फांदकर अंदर बाहर कर रहे हैं।सूत्रों के अनुसार अभी पार्क का उद्घाटन होना है इसलिए ताला लगा हुआ है। खबरों के मार्फत संज्ञान में आया था कि उद्धघाटन हेतु पार्क में काफी दिनों पहले कुर्सियां भी लगी थी लेकिन टिहरी विद्यायक,जिनको उद्धघाटन करना था पहुंचे नहीं और कार्यक्रम स्थगित हो गया। सवाल यह है कि जब पार्क बन संवर कर तैयार हो गया है तो जनता की प्रोपर्टी को, जनसमुदाय के लिए खोलने में हीलाहवेली क्यों? वैसे भी सुमन पार्क इस नगर की गति. विधियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है।

उत्तराखंड सरकार के बजट पर टिहरी कांग्रेस ने जताया कड़ा विरोध

शाह टाइम्स संवाददाता

नई टिहरी। गैरसैंण में राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत उत्तराखंड बजट पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्ट ने बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में पूरी तरह असफल साबित होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बजट में केवल घोषणाओं का पुलिंदा पेश किया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि इन योजनाओं के लिए धन कहां से आएगा।

प्रदेश प्रवक्ता भट्ट ने कहा कि प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और वर्तमान में राज्य पर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज हो चुका है। वर्ष 2016-17 में जहां राज्य पर लगभग 35 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था, वहीं अब यह बढ़कर एक लाख करोड़ से अधिक हो गया है, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने कहा कि यह बजट कर्ज लेकर घी पीने जैसा है। सरकार के पांचवें बजट में भी युवाओं के लिए रोजगार सृजन की कोई स्पष्ट योजना नहीं दिखाई देती। प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और लाखों शिक्षित युवा रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिससे युवाओं में निराशा का माहौल है।

भट्ट ने पर्वतीय क्षेत्रों से बढ़ते पलायन को भी गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि बजट में पलायन रो. कने के लिए कोई ठोस नीति या प्रभावी कार्यक्रम नजर नहीं आता। गांव लगातार खाली हो रहे हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में संवे. दनशील नहीं दिख रही है। उन्होंने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को भी बजट में निराशाजनक बताया। कहा कि टिहरी में मेडिकल कालेज को लेकर पिछले नौ वर्षों से भाजपा बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन बजट में इसका जिक्र तक नहीं किया गया। इसके अलावा नई टिहरी जिला मुख्यालय सहित पूरे जनपद की सड़कें खस्ताहाल हैं, लेकिन बजट में इनके सुधार के लिए कोई ठोस बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है।

जाखणीधार और चंबा विकासखंड को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन सरकार ने इन क्षेत्रों को आध्यात्मिक क्षेत्र घोषित करने जैसी बात कहकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि बजट से स्पष्ट है कि सरकार के पास प्रदेश के विकास के लिए कोई ठोस रोडमैप नहीं है। यह बजट नई बोतल में पुरानी शराब जैसा है, जिससे प्रदेश के किसान, युवा और आम जनता को कोई वास्तविक राहत मिलने वाली नहीं है। आने वाले समय में इस बजट की कई घोषणाएं भी पूर्व की तरह विलोपित होती नजर आएंगी।

रुद्रप्रयाग में होटल-रिजॉर्ट पर पुलिस की सघन चेकिंग, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

एसपी के निर्देश पर जनपदभर में चल रहा अभियान, सीसीटीवी व बाहरी स्टाफ के सत्यापन की जांच

शाह टाइम्स संवाददाता

रुद्रप्रयाग। जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से रुद्रप्रयाग पुलिस ने होटल, होमस्टे और रिजॉर्टों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक सुश्री नीहारिका तोमर के निर्देश पर जिले के सभी कोतवाली और चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में आकस्मिक निरीक्षण कर नियमों के पालन की जांच की गई।

इसी क्रम में पुलिस उपाधीक्षक रुद्रप्रयाग/गुप्तकाशी विकास पुण्डीर के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षकों और चौकी प्रभारियों की टीमों ने विभिन्न होटल, होमस्टे और रिजॉर्टों में पहुंचकर एंट्री रजिस्टर, आगंतुक रजिस्टर और वहां कार्यरत बाहरी स्टाफ के सत्यापन की जांच की। इसके साथ ही प्रतिष्ठानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की स्थिति भी परखी गई।

चेकिंग के दौरान यह भी देखा गया कि विदेशी नागरिकों के ठहरने की स्थिति में उनकी सूचना एलआईयू को दी गई है या नहीं तथा संबंधित अभिलेख और फार्म-सी का सही तरीके से संधारण किया जा रहा है या नहीं। पुलिस टीमों ने होटल व होमस्टे संचालकों को निर्देश दिए कि वे अपने आगंतुक रजिस्टर नियमित रूप से मेंटेन रखें, आने वाले सभी लोगों के पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लें और प्रतिष्ठान परिसर को सीसीटीवी कैमरों से लैस रखें। साथ ही किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या समस्या की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए कहा गया। पुलिस ने स्पष्ट किया कि भविष्य में किसी भी प्रतिष्ठान में अनियमितता या संदिग्ध गतिविधि पाए जाने पर संबंधित स्वामी या प्रबंधक के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

साइबर ठगों ने आरबीआई का कर्मचारी बताकर एक शख्स से 30 लाख ठगे

पुलिस साइबर सेल की मदद से ठगों की कर रही तलाश

शाह टाइम्स संवाददाता

विकासनगर। उत्तराखंड के विक. ासनगर में साइबर ठगों ने खुद को आरबीआई का कर्मचारी बताकर एक शख्स से लाखों रुपये डकार लिए अब पुलिस की टीमें इन 'डिजिटल लुटेरों' की तलाश में जुटी हैं। विकासनगर के मलूक. ावाला निवासी विनोद कुमार, जो मंडी में आढ़ती का काम करते हैं, उनके साथ साइबर ठगों ने 30 लाख रुपये से अधिक की बड़ी ठगी को अंजाम दिया है। ठगों ने ऐसा जाल बिछाया कि पीड़ित किश्तों में पैसे देता रहा और उसे भनक तक नहीं लगी. पीड़ित विनोद के मुताबिक, 5 जनवरी 2026 को उनके पास एक

कॉल आया था. कॉल करने वाले ने खुद को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का कर्मचारी बताया. ठग ने कहा कि आपकी एक फाइल उसके पास आई है, जिसमें आपकी किसी पुरानी पॉलिसी के पैसे रिलीज होने वाले हैं। ठगों ने 'कैपिटल गेन टैक्स' और 'सरकारी बॉन्ड' दिखाने के नाम पर पीड़ित से अलग-अलग किश्तों में पैसे जमा कराए. ठग इतने शातिर थे कि उन्होंने पीड़ित को भरोसा दिलाया कि यह सारा पैसा सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है और बाद में वापस मिल जाएगा. विनोद ने बताया कि जब तक उन्हें ठगी का अहसास हो पाता, तब तक काफी देर हो चुकी थी और उनके बैंक अकाउंट से करीब 30 लाख रुपये से अधिक की रकम गायब हो चुकी थी। ठगों ने अपनी पहचान इतनी पुख्ता तरीके से पेश की थी कि पीड़ित को शुरू में कोई शक नहीं हुआ।

साइबर ठग पीड़ित विनोद से करीब 30 लाख रुपये ठगकर अपने सभी मोबाइल नंबर बंद कर चुके हैं। पीड़ित की शिकायत पर अब विक. ासनगर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली निरीक्षक विना. ेद गुसाई ने बताया कि पुलिस मामले की तहकीकात शुरू कर चुकी है और साइबर सेल की मदद से ठगों की तलाश की जा रही है। संदिग्ध बैंक खातों और मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया जा रहा है ताकि अपराधियों तक पहुंचा जा सके।

परिवहन विभाग टिहरी की बड़ी कार्यवाही, 27 वाहनों के चालान, 07 वाहन सीज

नई टिहरी। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन विभाग द्वारा सघन प्रवर्तन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान मोटर व्हीकल अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में कार्यवाही की गई।इस दौरान बिना हेलमेट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना टैक्स, बिना फिटनेस, ट्रिपल राइडिंग आदि नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 27 वाहनों के चालान किए गए तथा 07 वाहनों को सीज किया गया।एआरटीओ सतेंद्र राज ने बताया कि यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए यह चेकिंग अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।चेकिंग अभियान के दौरान नरेंद्र मियाँ, अनंत राम, अर्जुन, नवीन तथा विपिन, रोहन और मोनिका भी उपस्थित रहे।

एक नजर ....

शिक्षकों ने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने को नए कौशल को सीखा

शाह टाइम्स संवाददाता विकासनगर। द हिमालयन इंटरनेशनल स्कूल विकासनगर में सीबीएसई की ओर से शिक्षकों के सर्वागीण विकास के लिए 'क्षमता निमार्ण कार्यशाला'-राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक दिवसीय आयोजन किया गया। कार्यशाला में विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नए कौशलों को सीखा। विद्यालय के प्रधानाचार्य पंकज शर्मा ने कहा भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यशालाए का आयोजन विद्यालय प्रबंधन की ओर से किए जाएंगे। इस मौके पर रेनू चंदेल, अनामिका, श्रेतलाना, चित्रा, पूनम, लव माथुर, विशाल, सुभान लाल आदि मौजूद रहे।

जनपद में खाद्यान वितरण की अवधि 15 मार्च तक हुई विस्तारित

नई टिहरी। जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल मनोज कुमार डोभाल ने बताया कि शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम जनपद के समस्त राशन कार्डधारकों को माह जनवरी 2026 के खाद्यान्न वितरण की अवधि दिनांक 15 मार्च 2026 तक विस्तारित कर दी गयी है, साथ ही माह फरवरी, 2026 के खाद्यान्न वितरण की अवधि दिनांक 31 मार्च 2026 तक रहेगी।उन्होंने जनपद के समस्त राशन कार्डधारकों से अनुरोध किया है कि सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान से माह जनवरी 2026 का खाद्यान्न दिनांक 15 मार्च, 2026 तक एवं माह फरवरी 2026 का खाद्यान्न दिनांक 31 मार्च 2026 तक बॉयोमेट्रिक ऑथेन्टिकेशन के माध्यम से प्राप्त कर लें। निर्धारित अवधि के पश्चात् भविष्य में उपरोक्त माहों का खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं होगा।

आरएसएस का दो दिवसीय चयन वर्ग हुआ सम्पन्न

नई टिहरी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तराखंड संभाग के नवीन कार्यकर्ताओं का दो दिवसीय चयन वर्ग सरस्वती विद्या मंदिर, नई टिहरी में मंगलवार को सम्पन्न हुआ। समापन सत्र की शुरुआत भारत माता और मां सरस्वती के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के टिहरी जिलाध्यक्ष उदय रावत ने एकल अभियान की सराहना की। कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण वर्ग कार्यकर्ताओं को समाज सेवा के लिए प्रेरित करते हैं और संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्य वक्ता के रूप में उत्तराखंड संभाग के संभाग अभियान प्रमुख अरविंद कनौजिया ने एकल अभियान के उद्देश्य और उसके लक्ष्यों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एकल अभियान के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा, संस्कार और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान स्वयंसेवकों ने दो दिवसीय चयन वर्ग में प्राप्त अनुभव साझा किए और प्रशिक्षण से मिली सीख को समाज में लागू करने का संकल्प लिया। दो दिवसीय चयन वर्ग की परीक्षा में उधम सिंह नगर अंचल की सुनीता रानी ने प्रथम, उत्तरकाशी की आंचल ने द्वितीय और खटीमा (कुमाऊं) की अनीषा रानी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

प्रहरी पड़ाव से मजबूत हो रहा पुलिस-जनता का भरोसा

शाह टाइम्स संवाददाता

रुद्रप्रयाग। पुलिस और आम जनता के बीच संवाद को मजबूत करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा रुद्रप्रयाग पुलिस का विशेष अभियान "अभियान प्रहरी पड़ाव" लगातार प्रभावी साबित हो रहा है। पुलिस अधीक्षक सुश्री नीहारिका तोमर की इस अभिनव पहल के तहत पुलिस टीमें गांव-गांव पहुंचकर रात्रि चौपाल और रात्रि प्रवास के माध्यम से ग्रामीणों से सीधा संवाद कर रही हैं। अभियान अब अपने दूसरे सप्ताह में पहुंच गया है और अब तक कुल 15 गांवों में चौपाल आयोजित की जा चुकी है।

बीती सोमवार रात पुलिस टीमों ने 14वीं और 15वीं चौपाल क्रमशः चौकी गौरीकुंड क्षेत्र के मुनकटिया तथा कोतवाली अगस्त्यमुनि के फलई गांव में आयोजित की। कार्यक्रम में स्थानीय महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान पुलिस

अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान के लिए आश्वस्त किया।चौपाल के दौरान पुलिस टीम ने महिलाओं को गौरा शक्ति एप तथा बाल सहायता हेल्पलाइन 1098 की जानकारी दी। साथ ही घरेलू हिंसा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक रहने और किसी भी घटना की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। ग्रामीणों से मादक पदार्थों की तस्करी और नशे के खिलाफ पुलिस को सहयोग करने का आह्वान किया गया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपने आसपास होने वाली संदिग्ध गति. विधियों की गोपनीय सूचना देने के लिए प्रेरित किया। गांवों की आंत. रिक सुरक्षा मजबूत करने के लिए ग्रामीणों को "स्मार्ट सुरक्षा" की अवधारणा समझाई गई। पुलिस ने गांव के प्रवेश और निकास मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा साम. ुदायिक निगरानी बढ़ाने की सलाह दी।

सेवानिवृत कर्मचारियों की पेंशन पर लगी रोक हटाने की मांग

शाह टाइम्स संवाददाता

नई टिहरी। सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनधारकों की पेंशन पर लगी रोक को हटाने की मांग उठने लगी है। इस संबंध में पूर्व कर्मचारी नेता योगेंद्र सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजकर 16 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश को निरस्त करने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तराखंड में सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के नियमित सेवा. निवृत्त कर्मचारियों को दिल्ली उच्च न्यायालय के 2 सितंबर 2019 के निर्णय और उसके बाद 04 फरवरी 2020 को जारी शासनादेश के तहत फिटर आदि पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को वर्कचार्ज सेवा जोड़कर पेंशन का लाभ दिया जा रहा था।

लेकिन 16 जनवरी 2026 को जारी शासनादेश के तहत पेंशन भुगतान पर रोक लगा दी गई, जिससे कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनधारकों की पेंशन बंद हो गई। इससे पेंशनरों में भारी आक्रोश व्याप्त है। कहा कि 24 दिसंबर 2025 को कैबिनेट बैठक में पूर्व सेवा को जोड़कर पेंशन देने का निर्णय लिया गया था और इसकी सूचना सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम की ओर से भी जारी की गई थी।

इसके बावजूद शासन की ओर से बाद में आदेश जारी कर पेंशन पर रोक लगा दी गई। नेगी ने आरोप लगाया कि शासन ने 2023 में उदय राज बनाम बिहार मामले के निर्णय को आधार बनाया, जबकि न्यायालय ने बाद में स्पष्ट किया था कि उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड से संबंधित मामले में 2019 का प्रेम सिंह बनाम राज्य सरकार का निर्णय ही मान्य होगा।

उन्होंने बताया कि पेंशन बंद होने के बाद कई पेंशनरों ने नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वहीं, निदेशक कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखंड की ओर से 30 जनवरी 2026 को शासन से मार्गदर्शन भी मांगा गया, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं हुए हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि 16 जनवरी 2026 का शासनादेश निरस्त कर न्यायालय के आदेश के अनुरूप वर्कचार्ज सेवा जोड़ते हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनधारकों को पेंशन भुगतान बहाल किया जाए।

आगामी मानसून सीजन के लिए तैयारियों के तहत हुई मॉकड्रिल

शाह टाइम्स संवाददाता

नई टिहरी। देश की महत्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाओं टिहरी बांध एवं कोटेश्वर बांध क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को और अधिक सुदृढ़ करने, संभावित आपदा परिस्थितियों में विभिन्न एजेंसियों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दिनांक 11 मार्च, 2026 को आपदा प्रबंधन संबंधी मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है। यह मॉकड्रिल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार, उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। मॉकड्रिल के अंतर्गत संभावित आपदा की परिकल्पित परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों की भूमिका, उनकी कार्यप्रणाली, संसाधनों की उपलब्धता, आपातकालीन संचार व्यवस्था तथा राहत एवं बचाव कार्यों की रणनीति पर विस्तृत चर्चा एवं समीक्षा की जाएगी। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा।

मॉक एक्सरसाइज के माध्यम से आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, विभिन्न एजेंसियों के मध्य समन्वय तथा संसाधनों के प्रभावी उपयोग का वास्तविक परिस्थितियों के अनुरूप अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में संबंधित सभी एजेंसियां तत्परता, समन्वय एवं दक्षता के साथ प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। इस महत्वपूर्ण अभ्यास में राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, आपदा प्रबंधन से संबंधित एजेंसियां, सुरक्षा बलों के प्रतिनिधि, तकनीकी विशेषज्ञ तथा अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी प्रतिभाग करेंगे। आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न संस्थानों के मध्य समन्वय को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा तथा संभावित आपदा परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की तैयारियों का व्यापक आकलन किया जाएगा।

इसी क्रम में मंगलवार को टेबल टॉप एक्सरसाइज आयोजित की गई, जिसमे सभी संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल एवं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले आधुनिक आपदा प्रबंधन उपकरणों एवं बचाव संसाधनों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गयी। प्रदर्शनी के माध्यम से उपस्थित कर्मचारियों तथा स्थानीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को आपदा प्रबंधन, बचाव तकनीकों तथा आपातकालीन परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले आवश्यक उपकरणों, उपायों के प्रति जागरूक भी किया गया। इस दौरान मुख्य महाप्रबंधक टिहरी कॉम्प्लेक्स एम०के०सिंह, उप जिलाधिकारी टिहरी स्नेहिल कुंवर सिंह, छक्ड। के समन्वयक सेवानिवृत्त मेजर जनरल ए०के०वर्मा, चीफ इंजी. नियर सी०ई०ए० इरफान अहमद, अपर महाप्रबंधक ओ एम एस ए०के०सिंह, अपर महाप्रबंधक विपिन सकलानी, अपर महाप्रबंधक बी०डी०सेमवाल, उप महाप्रबंधक मानव संसाधन एवं प्रशासन मोहन सिंह श्रीसवाल, प्रबंधक जन सम्पर्क मनवीर सिंह नेगी, दीपक उनियाल आदि उपस्थित रहे। यह मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सामूहिक तैयारी, बेहतर समन्वय, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता तथा प्रभावी राहत एवं बचाव व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा, जिससे भविष्य में किसी भी आपदा की स्थिति में जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।

फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब रहा गढ़वाल हीरोज के नाम

शाह टाइम्स संवाददाता

नई टिहरी। टिहरी लेक फेस्टिवल के अंतर्गत बौराड़ी स्टेडियम में आयोजित करियप्पा फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रोमांचक रहा। फाइनल मैच में गढ़वाल हीरोज ने 14 गढ़वाल राइफल को 2-1 से हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। इससे पहले खेले गए दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में गढ़वाल हीरोज ने आईआईएमटी मेरठ को 1द्0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं पहले सेमीफाइनल में 14 गढ़वाल राइफल ने 7 गढ़वाल राइफल को 4-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी।

फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष देखने को मिला, लेकिन अंत में गढ़वाल हीरोज ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए 2-1 से जीत दर्ज की। प्रतियोगिता के समापन पर विजेता टीम गढ़वाल हीरोज को रू 1.5 लाख की पुरस्कार राशि, उपविजेता 14 गढ़वाल राइफल को रू 75,000 तथा तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को रू 25,000/रू 25,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की गई। समापन समारोह में जिलाधिकारी नितिका खण्डेलवाल, सीडीओ वरुणा अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष उदय रावत, नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत द्वारा विजेता टीम को ट्रॉफी एवं चेक प्रदान किए गए। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि विजेता टीम को बधाई दी तथा सभी टीमों के खिलाड़ियों को भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी को अनुशासन के लिए जाना जाता है।

सूचना का अधिकार व सेवा का अधिकार अधिनियम की दी जानकारी

रुद्रप्रयाग। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 एवं सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन और व्यापक प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, नैनीताल के तत्वाधान में कलेक्ट्रेट सभागार में तीन दिवसीय आउटरीच प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा पटल सहायकों ने प्रतिभाग किया।प्रशिक्षण के दौरान उपनिद. ेशक एवं कार्यक्रम अधिकारी (प्रशिक्षण) पूनम पाठक, अकादमी नैनीताल तथा एडवोकेट राजेश डिमरी ने अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 और सेवा का अधिकार अधिनियम की विस्तृत जानकारी दी।

अवैध रूप से निर्मित व संचालित "हेल्पिंग हेल्थ" हॉस्पिटल सील

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून। मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने धौरण रोड पर अवैध रूप से निर्मित एवं संचालित "हेल्पिंग हेल्थ" नामक हॉस्पिटल पर सीलिंग की कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार कुश ऐरन द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र और आवश्यक अनुमति के उक्त निर्माण किया गया था।

प्राधिकरण द्वारा पूर्व में भी संबंधित को नियमों के अनुरूप निर्माण करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब और वैध दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने के कारण यह कार्रवाई की गई। सीलिंग की इस कार्रवाई के दौरान सहायक अभियंता शैलेन्द्र सिंह रावत, अवर अभियंता एवं सुपरवाइजर सहित प्रवर्तन टीम मौके पर मौजूद रही।

इसके अतिरिक्त उपाध्यक्ष के निर्देशों के क्रम में मंगलवार को एमडीडीए की प्रवर्तन टीम द्वारा पछवादून क्षेत्र के विकासनगर के विभिन्न सेक्टरों में संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान क्षेत्र में हो रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की मौके पर जांच की गई और निर्माणकर्ताओं से मानचित्र स्वीकृति सहित अन्य जरूरी दस्तावेजों की पड़ताल की गई। जिन निर्माणकर्ताओं द्वारा आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए या संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, उन्हें चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार आगे की कार्रवाई की रणनीति तैयार की जा रही है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्राधिकरण लगातार अभियान चलाये हुए है।

■ अवैध निर्माण पर एमडीडीए की सख्त कार्रवाई ■ बिना मानचित्र स्वीकृति या निर्धारित मानकों का पालन किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण करना पूरी तरह अवैध - बंशीधर तिवारी'

निर्माण कार्य शुरू करने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराएं:तिवारी

एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में भी यह अभियान जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि बिना मानचित्र स्वीकृति या निर्धारित मानकों का पालन किए बिना किसी भी प्रकार का निर्माण करना पूरी तरह अवैध है और ऐसे मामलों में प्राधिकरण नियमानुसार कठोर कार्रवाई करेगा। उन्होंने आम जनता और निर्माणकर्ताओं से अपील की कि किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। तिवारी ने कहा कि अवैध निर्माण न केवल शहर की नियोजित विकास व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, बल्कि भविष्य में जनसुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकते हैं। इसलिए एमडीडीए द्वारा लगातार निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।

नियम विरुद्ध कार्यों पर हो रही कार्रवाई: बर्निया

एमडीडीए के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान जिन निर्माण स्थलों पर मानचित्र स्वीकृति या अन्य आवश्यक दस्तावेज नहीं पाए जाते हैं, उन्हें चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि विकासनगर सहित पछवादून क्षेत्र में किए गए निरीक्षण में कुछ निर्माणों को चिन्हित किया गया है, जिनके विरुद्ध जल्द ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।

सीएम ने पूर्व विधायक स्व. दिवाकर बलवीर व राजेश जुवांठा को दी श्रद्धांजलि

■ विधान सभा में सत्र के दूसरे दिन सदन में दी गयी श्रद्धांजलि

शाह टाइम्स ब्यूरो

गैरसैंण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा में देवप्रयाग के पूर्व विधायक स्वर्गीय दिवाकर भट्ट को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका संघर्षशील व्यक्तित्व और निर्भीक नेतृत्व उत्तराखंड की जनराजनीति की सशक्त पहचान रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने वही दूसरी ओर मंगलवार को विधानसभा में टिहरी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय बलवीर सिंह नेगी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके निधन को उत्तराखंड की राजनीति और सार्वजनिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि बलवीर सिंह नेगी का पूरा जीवन जनसेवा, सादगी और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहा।

जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधी थे स्व. राजेश

गैरसैंण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को विधानसभा में पुरोला के पूर्व विधायक स्वर्गीय राजेश जुवांठा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके निधन को उत्तराखंड के राजनीतिक और सामाजिक जीवन के लिए अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि राजेश जुवांठा एक युवा, ऊर्जावान और जनसरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधि थे, जिन्होंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में पूरी मजबूती के साथ उठाया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय जुवांठा जी अपने सरल, ईमानदार और मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते थे तथा आमजन के प्रति उनकी संवेदनशीलता उन्हें एक लोक. प्रिय जनप्रतिनिधि बनाती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 दिसंबर 2025 को हृदयगति रुकने से 48 वर्ष की आयु में उनका असमय निधन हो गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी गढ़वाल जनपद के ग्राम थाती में 8 दिसंबर 1947 को जन्मे बलवीर सिंह नेगी जी साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर जनसेवा के क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान बनाने में सफल रहे। 1970 के दशक से ही वे टिहरी क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय रहे और जीवन के अंतिम समय तक क्षेत्रीय विकास तथा जनहित के मुद्दों के लिए निरंतर प्रयास करते रहे।

उन्होंने बताया कि स्वर्गीय नेगी भिलंगना क्षेत्र से दो बार ब्लॉक प्रमुख रहे और स्थानीय विकास की मजबूत नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही वे जिला पंचायत सदस्य भी रहे और ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए लगातार सक्रिय रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बलवीर सिंह नेगी जी ने लखनऊ विश्वविद्यालय से बी.ए. और एल.एल.बी. की शिक्षा प्राप्त की थी। वे पहली बार वर्ष 1989 में जनता दल के टिकट पर टिहरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद वर्ष 2002 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के टिकट पर घनसाली से तथा वर्ष 2007 में कांग्रेस के टिकट पर पुन: विधायक चुने गए।

कृषि, ग्रामीण विकास और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देगा बजट: जोशी

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून। प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा गैरसैंण विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 1,11,703.21 करोड़ का ऐतिहासिक और समावेशी बजट कृषि, ग्रामीण विकास और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने वाला बजट है। । उन्होंने कहा कि यह बजट गरीबों, युवाओं, किसानों (अन्नदाताओं) और नारीशक्ति के उत्थान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रदेश के सतत विकास की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगा। कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का जो सकारात्मक प्रभाव धरातल पर दिखाई दे रहा है, यह बजट उन प्रयासों को और अधिक विस्तार देने का कार्य करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बजट 'विकसित भारत 2047' के संकल्प को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि यह बजट कृषि, ग्रामीण विकास और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने वाला बजट है, जिससे प्रदेश के किसानों, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी।

क्रिकेट बना भाईचारे का माध्यम, निरंकारी युवाओं ने पेश की मिसाल

शाह टाइम्स संवाददाता

देहरादून। सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज एवं निरंकारी राजपिता रमित की कृपा से 26वें बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन आज संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल, समालखा (हरियाणा) में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। इस टूर्नामेंट का शुभारंभ फरवरी 2026 में हुआ था, जिसमें देशभर के विभिन्न राज्यों से चयनित 24 टीमों ने भाग लेकर खेल प्रतिभा के साथ-साथ आपसी भाईचारे और अनुशासन की भावना का उत्कृष्ट परिचय दिया। युवा खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह, समर्पण और खेल भावना के साथ अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया और खेल के माध्यम से उन्होंने सहयोग, सहनशीलता, मर्यादा, आपसी सम्मान जैसे जीवन मूल्यों को व्यवहार में उतारते हुए निरंकारी मिशन की शिक्षाओं को साकार किया।

आज 10 मार्च को खेले गए क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में फिरोजपुर (पंजाब) और श्रीगंगानगर (राजस्थान) की श्रेष्ठ टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें श्रीगंगानगर (राजस्थान) विजेता टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए ट्रॉफी अपने नाम की। टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी सोनू राजपूत (श्रीगंगानगर) को "मैन ऑफ द मैच" के सम्मान से भी नवाजा गया।

कार्यालय जिला पंचायत रुद्रप्रयाग

संख्या : 2101/निर्माण -05/2025-26 | दिनांक 09.03.2026

निविदा सूचना

जिला पंचायत रुद्रप्रयाग में विभिन्न मदों के अन्तर्गत संलग्न सूची के अनुसार विकास कार्यों के निर्माण हेतु पंजीकृत ठेकेदारों से शीलबन्द निविदायें दिनांक 27.03.2026 को 2.00 बजे अपराह्न तक आमन्त्रित की जाती हैं, जो उसी दिन 3.00 बजे सायं को उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा के साथ 3 प्रतिशत धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक की एफ०डी०आर के रूप में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग के पद नाम से बन्धक कर प्रस्तुत करनी होगी। प्रत्येक निविदा के साथ रूपये 100.00 का नान जूडिसियल स्टाम्प पेपर व 1.00 रूपये का रसीदी टिकट लगाकर ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र दिनांक 25.03.2026 को अपराह्न 4.00 बजे तक जिला पंचायत के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। प्रत्येक निविदादाता को निविदा प्रपत्र में अपनी दरों का प्रतिशत में स्पष्ट उल्लेख करना होगा ।

क्र. स.	कार्य का नाम	आंगणन की धनराशि (लाख में)	धरोहर धनराशि 3 प्रतिशत	निविदा की वैद्यता	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का शुल्क / जी.एस.टी. 18 प्रति.
1	ग्रा.पं. सिल्ला बंमणगांव के अन्तर्गत विनौली गदेरा तोक में पक्की सुरक्षा दीवाल	720000	21600	45 दिन	3 माह	1000+ 18 प्रतिशत
2	ग्रा.पं. सिलगांव के घरियाणा में पंचायत भवन निर्माण	400000	12000	45 दिन	3 माह	1000+ 18 प्रतिशत
3	ग्रा.पं. मेदनपुर में सी०सी० सम्पर्क मार्ग निर्माण।	320000	9600	45 दिन	3 माह	1000+ 18 प्रतिशत
4	ग्राम पंचायत पाव जगपुडा के गाँव जगपुडा प्रा.वि. जाने हेतु लॉक टाईल्स रास्ता निर्माण कार्य।	350000	10500	45 दिन	5 माह	1000+ 18 प्रतिशत
5	ग्रा. स. जवाडी के सन्नीमू तोक में प्रसूति गृह निर्माण।	360000	10800	45 दिन	3 माह	1000+ 18 प्रतिशत
6	ग्रा. स. जवाडी के गामागदरा डिग्गी से उकालिंगू तक खण्डिजा / मार्ग निर्माण	360000	10800	45 दिन	3 माह	1000+ 18 प्रतिशत
7	ग्रा.पं. जगोठ के पा.वि. में कीचन निर्माण।	370000	11100	45 दिन	3 माह	1000+ 18 प्रतिशत
8	ग्रा. उछना सडक से पाण्डव चौक तक सी.सी. मार्ग व रैलिंग कार्य ।	500000	15000	45 दिन	3 माह	1000+ 18 प्रतिशत
9	ग्रा. पं. मक्कूमठ के अन्तर्गत मक्कूमठ में आंगणबाडी से राजपुर मोहल्ले तक रास्ता निर्माण कार्य।	470000	14100	45 दिन	3 माह	1000+ 18 प्रतिशत
10	ग्रा. स. सेमलमा के फडम्या में प्रतिक्षालय निर्माण कार्य।	360000	10800	45 दिन	3 माह	1000+ 18 प्रतिशत
11	ग्रा. स. कफना के थापली तोक में प्रतिक्षालय निर्माण कार्य।	360000	10800	45 दिन	3 माह	1000+ 18 प्रतिशत
12	ग्रा. पं. जखोली बॉध में गंगोली गधेरे पर पुलिया निर्माण कार्य।	470000	14100	45 दिन	3 माह	1000+ 18 प्रतिशत
13	ग्रा.पं. फलासी में मिलन केन्द्र का मरम्मत कार्य।	275000	8250	45 दिन	3 माह	1000+ 18 प्रतिशत
14	ग्रा.पं. भौंसाल के वैस्याणी से त्रिशूला तोक तक पेयजल मरम्मत कार्य।	300000	9000	45 दिन	3 माह	1000+ 18 प्रतिशत
15	बुढना के भण्डार तोक में रामलीला मंच निर्माण कार्य।	450000	13500	45 दिन	3 माह	1000+ 18 प्रतिशत
16	बरसीर के मुख्य गेट से कुमडाउ सोड तक इन्टरलॉक टाईल्स।	270000	8100	45 दिन	3 माह	1000+ 18 प्रतिशत
17	ग्रा. मुस्यागांव में इन्टरलॉक रास्ता निर्माण।	500000	15000	45 दिन	3 माह	1000+ 18 प्रतिशत

शेष शर्तें:-

1. फर्म / ठेकेदार को निविदा प्रकाशित होने की तिथि से पूर्व जिला पंचायत रूद्रप्रयाग में ए एंव बी श्रेणी में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
2. अनुबन्ध के समय 5 प्रतिशत धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा के साथ ठेकेदार को अपना बैंक खाता एवं जी०एस०टी० की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. सशर्त निविदा / अपूर्ण निविदा को स्वीकार नही किया जायेगा ।
5. निविदा बिक्रय एवं खोलने की तिथि को अवकाश होने की दशा में, निविदा अगले कार्यदिवस में बेची / खोली जायेगी।
6. एजेन्सी द्वारा किसी अन्य संस्था को कार्य सबलेट नही किया जायेगा।
7. कार्य सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण होने पर ही भुगतान किया जायेगा ।
8. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दर के अन्तर्गत ही प्रत्येक कार्य पर साइन बोर्ड लगाया जाना आवश्यक होगा
9. जिला पंचायत के बकायादार को निविदा बिक्रय नहीं की जायेगी।
10. स्थानीय खनन हेतु भूतत्व एंव खनिकर्म ईकाई कार्यालय रूद्रप्रयाग से अनुमति लेनी स्वंय ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी।
11. अन्य शर्तें एवं कार्य के निमित विशिष्टियों की जानकारी किसी भी कार्यदिवस में जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(संजय कुमार)
प्र.अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत रूद्रप्रयाग

(पूनम कठैत)
अध्यक्ष
जिला पंचायत रूद्रप्रयाग

आपात स्थिति में खाद्यान्न आपूर्ति भंडारण की उत्तराखंड में प्रयाप्त व्यवस्था

मुख्य संवाददाता शाह टाइम्स

देहरादून। केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि आपतकाल की स्थिति में खाद्यान्न आपूर्ति भंडारण को लेकर उत्तराखंड में प्रयाप्त व्यवस्था है। इसी तरह प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के संसद में पूछे गए एक अन्य सवाल में आयुष यूनिवर्सिटी में रैगिंग के बेहद कम मामले सामने आने की जानकारी दी है।

■ राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सदन में किए कई सवाल

उनके द्वारा राज्यसभा के पटल पर प्रदेश में आपात स्थिति के लिए खाद्यान्न भंडारण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी मांगी गई थी। जिसके जबाब में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया ने बताया कि भंडारण क्षमता की आवश्यकता, अर्थात् नए गोदामों, साइलो का निर्माण, मुख्यत: चावल और गेहूं के लिए खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रचालनों पर निर्भर करता है। सरकार भंडारण अंतराल का निरंतर आकलन और निगरानी करती है और इसके आधार पर, भारतीय खाद्य निगम केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के माध्यम से निम्नलिखित योजनाओं द्वारा भंडारण क्षमताएं सृजित या किराए पर ली जाती हैं।

उत्तराखंड में वर्तमान में उपलब्ध भंडारण क्षमता की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड सरकार के स्वामित्व वाली पहाड़ी क्षेत्र के गोदामों में 0.53 लाख टन, गैर-पहाडी क्षेत्र 1.52 लाख टन, एफसीआई के पर्वतीय गोदामों में 0.015 और गैर पर्वतीय क्षेत्रों में 2.039 लाख टन भंडारण क्षमता मौजूद है। इसके अलावा, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में केंद्रीय भंडारण निगम के पास कुल 95698 टन क्षमता वाले 7 गोदाम हैं।

इसी तरह आयुष मेडिकल कालेजों में रैगिंग को लेकर नीतियों की जानकारी मांगने पर आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। उनके द्वारा बताया गया कि वर्तमान वर्ष के दौरान, देश भर के सरकारी आयुष मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग के कुल पांच 5 मामले सामने आए हैं। आयुष मेडिकल कॉलेजों में रैगिंग को रो. कने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग और राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग समय-समय पर सभी आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और सोवा-रिग्पा कॉलेजों, संस्थानों को एंटी रैगिंग प्रयासों को मजबूत करने और रैगिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का सख्ती से पालन करने के निर्देश जारी कर रहे हैं। इसके अलावा, एनसीआईएसएम ने विश्वविघ्द्यालय अनुदान आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार एंटी रैगिंग समिति और एंटी-रैगिंग दस्ते के गठन के लिए विनियम भी अधिसूचित किए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग ने विनियम अधिसूचित किए हैं, जिसमें नए प्रवेशित स्नातक छात्रों के लिए अनिवार्य फाउंडेशन कार्यक्रम के दौरान रैगिंग नीति पर प्रस्तुतीकरण और छात्रों के साथ संवादात्मक चर्चाष जैसी गति. विधियों को अनिवार्य किया है। इसके अलावा, यूजीसी द्वारा बुनियादी उपायों, परामर्श और निगरानी उपायों और रैगिंग मुक्त परिसर बनाए रखने के संबंध में जारी दिशानिर्देशों और कार्य बिंदुओं को समय-समय पर संस्थानों को परिचालित किया जाता है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, सभी कॉलेजों द्वारा एक एंटी रैगिंग समिति का गठन किया जाना और शिकायत दर्ज करने के लिए स्थापित किए गए तंत्र का व्यापक प्रचार किया जाना आवश्यक है।

अब वॉइस के माध्यम से इंटरैक्ट कर रहे भारतीय यात्री

देहरादून। भारत की प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेकमायट्रिप ने आज अपने जेन-एआई आधारित ट्रिप प्लानिंग असिस्टेंट मायरा से मिले कुछ शुरुआती रुझान साझा किए हैं। ये संकेत देते हैं कि भारतीय यात्री अब वॉइस के माध्यम से किस तरह से इंटरैक्ट करना शुरू कर रहे हैं और इसमें एक नया व्यवहारिक रुझान उभर रहा है।

मायरा का यूजर बेस अभी बढ़ रहा है और इस पर रोजाना 50,000 से अधिक बातचीत हो रही है, लेकिन शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि वॉइस सर्च लोगों को अपनी बात ज्यादा खुलकर, संदर्भ के साथ और अपनी पसंदीदा भाषा में रखने का मौका दे रहा है।

केंद्र सरकार से उत्तराखंड को 264.50 करोड़ रुपये की विशेष सहायता स्वीकृत

देहरादून। केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य को शहरी भूमि एवं नियोजन सुधारों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2025-26 के अंतर्गत भाग ख। अरबन लैण्ड एण्ड प्लानिंग रिफॉम्स के तहत उत्तराखंड को 264.50 करोड़ रुपये की विशेष सहायता (ऋण) स्वीकृत की गई है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अनुशंसा के आधार पर यह राशि राज्य सरकार को प्रदान की गई है। उत्तराखंड सरकार ने इस प्रोत्साहन राशि के लिए च्थ्डै पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

शाह टाइम्स

स्वामी शाह पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक एस.एन. राना द्वारा शाह पब्लिकेशन प्रा. लि. सुजड़ू चुंगी, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर से मुद्रित एवं 63/9 ई-राजपुर रोड देहरादून से प्रकाशित।

सम्पादक:
एस.एन. राना
*कार्यकारी सम्पादक
आनन्द बत्रा 'सुमन'
स्थानीय सम्पादक
चेतन गुरूंग
देहरादून कार्यालय 63/9 ई-राजपुर रोड देहरादून
☎0135-2743363
R.N.I. No.UTT HIN 2001/05656
मोबाइल-9720007290
www.shahtimesnews.com
email:shahtimes2015@gmail.com

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु PRB एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद मुजफ्फरनगर न्यायालय के अधीन ही होंगे।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रार्थी का मूल विक्रय विलेख (1) श्री अद्रीश (2) श्री अनीश दोनों स्वर्गीय सुक्कड़ के पुत्र (3) श्रीमती बतूल स्वर्गीय सुक्कड़ की पत्नी द्वारा श्री जहीर अहमद पुत्र श्री जलील जहमद के पक्ष में निष्पादित किया गया। दस्तावेज संख्या 841, दिनांक 17.02.2009. श्री जहीर अहमद पुत्र श्री जलील अहमद द्वारा मौहम्मद उस्मान पुत्र श्री अब्दुल अजीज के पक्ष में निष्पादित मूल विक्रय विलेख, दस्तावेज संख्या 2587, दिनांक 06.06.2011 को विधिवत रूप से दर्ज व पंजीकृत है। यह कि उक्त मूल विक्रय पत्र पटेल नगर के आस-पास कहीं खो गया है जो कि काफी ढूंढने पर भी नहीं मिला है।

मौहम्मद फय्याज पुत्र मौहम्मद इशाक
निवासी- सी-15 निकट हिमालय अकेडमी देहरादून
मो.नं.- 7417535532

कार्यालय नगर पालिका परिषद् गौचर (चमोली)

पंत्राक: 1469/ खुले में शो.मु.प्लस-सूचना/2025-26/ | दिनॉक 10.03.2026

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि नगर पालिका परिषद् गौचर क्षेत्रान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु निकाय द्वारा गठित टीम द्वारा किये गये सर्वे के आधार पर निकाय के समस्त (07) सात वार्डो को खुले में शौच मुक्त प्लस घोषित (ODF+) किये जाने के दावे प्राप्त हुए है। प्राप्त दावों के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है, तो वह नगर पालिका परिषद् गौचर कार्यालय में 15 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नही किया जायेगा।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद्
गौचर चमोली

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्
गौचर चमोली

संक्षिप्त खेल समाचार

मैथ्यू हेडन बने जीटी के बल्लेबाजी कोच

अहमदाबाद, वार्ता। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के लिए गुजरात टाइटंस ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को टीम का नया बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। हेडन टीम के सपोर्ट स्टाफ में मुख्य कोच आशीष नेहरा, क्रिकेट निदेशक विक्रम सोलंकी और सहायक कोच पार्थिव पटेल के साथ काम करेंगे। वह इससे पहले पाकिस्तान पुरुष टीम के साथ बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में भी काम कर चुके हैं। नियुक्ति के बाद हेडन ने कहा कि अच्छी बल्लेबाजी विपक्ष पर दबाव बनाती है, जबकि बेहतरीन बल्लेबाजी मैच पर नियंत्रण स्थापित कर लेती है, और यही मानक टीम स्थापित करना चाहती है। विक्रम सोलंकी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेडन का अनुभव और युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देने की क्षमता टीम की बल्लेबाजी को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएगी।

वनडे सीरीज में नंबर-5 पर बैटिंग करेंगे लिटन दास

ढाका, वार्ता। बांग्लादेश के मुख्य कोच फिल सिमंस ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान के खिलाफ आगामी तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में लिटन दास पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे। लिटन ने 2019 क्रिकेट विश्व कप के बाद से वनडे में पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी नहीं की है। सिमंस को उम्मीद है कि मध्यक्रम में उतरने से वह 50 ओवर के प्रारूप में अपनी खोई हुई लय वापस पा सकेंगे। लिटन पिछली आठ वनडे पारियों में दोहरे अंक तक नहीं पहुंच सके हैं। सिमंस का मानना है कि बल्लेबाजी क्रम में बदलाव से टीम के मध्यक्रम को मजबूती मिलेगी, जो लंबे समय से कमजोर कड़ी रहा है। उन्होंने कहा कि विकेट कीपिंग करने के बाद सीधे पारी की शुरुआत करना मुश्किल होता है, इसलिए मध्यक्रम में बल्लेबाजी करना लिटन के लिए अधिक अनुकूल हो सकता है।

अर्शदीप पर लगा मैच फीस का 15% जुर्माना

दुबई, वार्ता। भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर टी-20 विश्व कप फाइनल के दौरान आईसीसी आचार संहिता के लेवल-1 के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने मंगलवार को यह जानकारी दी। आईसीसी ने एक बयान में कहा कि अर्शदीप को खिलाड़ियों और खिलाड़ी सपोर्ट स्टाफ की आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2-9 के उल्लंघन का दोषी पाया गया।

यह अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान एक गेंद (या कोई अन्य क्रिकेट उपकरण) किसी खिलाड़ी पर या उसकी दिशा में

● अनुचित और खतरनाक ढंग से गेंद फेंकने से संबंधित व अर्शदीप के अनुशासन रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा

अनुचित और खतरनाक ढंग से फेंकने से संबंधित है। इसके अलावा अर्शदीप के अनुशासन रिकॉर्ड में एक डिमेरिट अंक भी जोड़ा गया है, क्योंकि यह बीते 24 माह में अर्शदीप की पहली गलती है। यह घटना टी-20 विश्व कप के फाइनल में हुई जब अर्शदीप ने अपने ही ओवर में डैरिल मिचेल के शॉट को रोका। जब उन्होंने गेंद पकड़ी तो मिचेल रन लेने के लिए क्रीज से दो कदम आगे आ चुके थे, इसलिए अर्शदीप ने गेंद विकेट की ओर फेंकी। इसी समय गेंद मिचेल के पैड पर जा लगी। उल्लेखनीय है कि अर्शदीप ने मिचेल को गेंद लगने के बाद फौरन माफी मांगी थी। उन्होंने मैच खत्म होने के बाद बताया कि उन्होंने एक बार फिर मिचेल से मिलकर माफी मांगी थी और वह बात को कि गेंद गलती से लगी थी। अर्शदीप पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप फील्ड अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ और एलेक्स वार्फ, थर्ड अंपायर अल्लाहुद्दीन पालेकर और फोर्थ अंपायर एड्रियन होल्डस्टॉक ने लगाए थे। अर्शदीप ने आईसीसी मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट द्वारा प्रस्तावित सजा को स्वीकार कर लिया, इसलिए आधिकारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। लेवल-1 के उल्लंघनों के लिए न्यूनतम दंड आधिकारिक फटकार, अधिकतम दंड खिलाड़ी की मैच फीस का 50 प्रतिशत और एक या दो अवमूल्यन अंक हैं। जब कोई खिलाड़ी 24 महीनों के भीतर चार या अधिक अवमूल्यन अंक प्राप्त कर लेता है, तो उन्हें निलंबन अंकों में परिवर्तित कर दिया जाता है और खिलाड़ी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। दो निलंबन अंक एक टेस्ट या दो वनडे या दो टी-20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों से प्रतिबंध के बराबर हैं, जो भी खिलाड़ी के लिए पहले पूरा हो। अवमूल्यन अंक खिलाड़ी या खिलाड़ी सहायक कर्मियों के अनुशासनात्मक रिकॉर्ड में उनके लागू होने की तारीख से 24 महीनों तक बने रहते हैं, जिसके बाद उन्हें हटा दिया जाता है।

पश्चिम एशिया के संकट के कारण आईसीसी की बैठक रद्द

कुछ विशेष बैठकें अगले कुछ सप्ताह में ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी

दुबई, वार्ता। पश्चिम एशिया में जारी सैन्य संघर्ष के कारण इस महीने के अंत में दोहा में होने वाली आईसीसी बोर्ड और कमेटी की बैठकों को रद्द कर दिया गया है। ईएसपीएन क्रिकइंफो को मिली जानकारी के अनुसार फाइनेंस कमेटी से जुड़ी कुछ विशेष बैठकें अगले कुछ सप्ताह में ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। अप्रैल में आमने-सामने बैठकों की संभावना अभी भी खुली है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या हवाई क्षेत्र इतना खुल गया है कि बोर्ड और कमेटी सदस्य सुरक्षित रूप से उड़ान भर सकें। ए बैठकें मूल रूप से 25 से 27 मार्च के बीच तय थीं और इनमें आईसीसी बोर्ड डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, कमेटी सदस्य और आईसीसी के सीनियर लीडरशिप के शामिल होने की योजना थी। चर्चा के लिए तीन मुख्य मुद्दे थे- ग्लोबल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, क्योंकि आईसीसी और जियोस्टार के बीच मौजूदा समझौता 2027 में खत्म होने वाला है, अगला एफटीपी और लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन। इनमें से दूसरे मुद्दे पर अनौपचारिक बातचीत पहले ही शुरू हो चुकी है, जहां कई सदस्य क्रिकेट के अगले चार साल के कैलेंडर की योजना बनाने के लिए आपस में पहले से चर्चा कर रहे हैं। यह पहली बार था, जब आईसीसी की बैठक दोहा, कतर में होने वाली थी।

रिंकू सिंह ने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट लिख कर पिता को किया याद

● रिंकू सिंह के पिता का शुक्रवार सुबह ग्रेटर नोएडा के अस्पताल में चौथे चरण के कैंसर से निधन हुआ था

नई दिल्ली, वार्ता। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद अपने दिवंगत पिता खानचंद सिंह को सोशल मीडिया के माध्यम से भावुक श्रद्धांजलि दी है। रिंकू के पिताजी का शुक्रवार सुबह ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल में चौथे चरण के कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद निधन हो गया था।

बाद में उनका अंतिम संस्कार अलीगढ़ में किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। रिंकू ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि वह अपने पिता से बात किए बिना कभी इतने दिन नहीं रहे और उनके बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि पिता ने उन्हें सिखाया था कि कर्तव्य सबसे पहले होता है, इसलिए, मैदान पर वह हमेशा उनके सपने को पूरा करने की कोशिश करते रहे। रिंकू ने लिखा कि आपसे बात किए बिना इतने दिन कभी नहीं निकले। मुझे नहीं पता आगे कि जिंदगी आपके बिना कैसे चलेगी, पर मुझे हर कदम पर आपकी जरूरत पड़ेगी। आपने सिखाया था कि फर्ज सबसे आगे है, तो मैदान पर बस आपका सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा था। अब आपका सपना पूरा हो गया है तो बस यही लगता है कि काश आप मेरे पास होते।

हर छोटी बड़ी खुशी में आपकी कमी खलेगी। बहुत याद करूंगा आपको पापा, बहुत ज्यादा। टी-20 विश्व कप 2026 के दौरान पिता जी की तबीयत बिगड़ने पर रिंकू टीम से अलग होकर कुछ समय के लिए घर लौटे थे और बाद में टीम से दोबारा जुड़ गए। टूर्नामेंट में उन्हें सीमित मौके मिले और उन्होंने पांच पारियों में 24 रन बनाए।

विश्व कप 2026 में भारत ने कई रिकॉर्ड बनाए

● भारत टी-20 के इतिहास में तीन बार टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम बनी

● दो बार लगातार खिताब जीतने वाली और घरेलू मैदान पर टी-20 विश्व कप जीतने वाली टीम भी बनी

नई दिल्ली, वार्ता। भारत ने आईसीसी पुरुष टी-20 विश्व कप 2026 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर खिताब तो अपने नाम किया ही, साथ ही रिकॉर्ड बुक में दर्ज कई रिकॉर्ड तोड़कर उन्हें अपने नाम किए।

भारत टी-20 के इतिहास में तीन बार यह टूर्नामेंट जीतने वाली पहली टीम बन गया और इस दौरान भारतीय टीम ने कई रिकॉर्ड भी बनाए। भारत ने इससे पहले 2007 और 2024 में टी-20 विश्व कप जीता था। मौजूदा चैंपियन बनने के साथ ही भारत लगातार दो बार खिताब जीतने वाली और घरेलू मैदान पर टी-20 विश्व कप जीतने वाली पहली टीम भी बन गई। आईसीसी की वेबसाइट के अनुसार, भारत और श्रीलंका में आयोजित एक महीने लंबे इस टूर्नामेंट के दौरान कई शानदार व्यक्तिगत और टीम प्रदर्शन देखने को मिले, जिनसे प्रतियोगिता रोमांचक बनी और कई नए रिकॉर्ड भी बने। फाइनल में भारत का 255/5 का स्कोर टी-20 विश्व कप फाइनल का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है।

सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 253/7 बनाने के बाद टीम लगातार दो मैचों में 250 से अधिक रन बनाने वाली पहली टीम भी बनी। टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में भारत ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 256/4 का स्कोर बनाया था, जो इस विश्व कप का सबसे बड़ा टीम स्कोर है। टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान ने 383 रन बनाकर एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। वहीं भारत के संजू सैमसन ने फाइनल में 89 रन बनाकर टी-20 विश्व कप फाइनल की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेली और पूरे टूर्नामेंट में 24 छक्के लगाए। भारत के अभिषेक शर्मा ने फाइनल में 18 गेंदों में अर्द्धशतक लगाकर टूर्नामेंट का सबसे तेज अर्द्धशतक बनाया। वहीं न्यूजीलैंड के फिन एलन ने 33 गेंदों में शतक लगाकर टी-20 विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ा। भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल में कुल 499 रन बने, जो टी-20 विश्व कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन वाला मैच रहा।

महिलाओं के 10 मी. एयर पिस्टल फाइनल में मनु भाकर ने मारी बाजी

● ओलंपियन मनु ने नेशनल सेलेक्शन ट्रायल्स टी3 के 10 मी. एयर पिस्टल महिला वर्ग के फाइनल में पहला स्थान हासिल किया

नई दिल्ली, वार्ता। ओलंपियन मनु भाकर ने डा. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आज समाप्त हुए नेशनल सेलेक्शन ट्रायल्स टी3 (ग्रुप ए) के 10 मीटर एयर पिस्टल महिला वर्ग के फाइनल में पहला स्थान हासिल किया। ट्रायल-2 की विजेता सैन्यम दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि ईशा सिंह ने आठ शूटरों के फाइनल में तीसरा स्थान प्राप्त किया। मनु भाकर फाइनल में आखिरी क्वालिफायर के रूप में पहुंची थीं, लेकिन दूसरे सीरीज के बाद उन्होंने बढ़त बना ली और अंत तक उसे बरकरार रखते हुए 246-1 के स्कोर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। यह स्कोर वर्ल्ड कप फाइनल की रजत पदक विजेता सैन्यम (241-9) से 4-2 अंक अधिक था। एशियन चैंपियनशिप की स्वर्ण और विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता ईशा सिंह 220-6 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। एशियन गेम्स चैंपियन पलक गुलिया 200-2 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहीं। उनके बाद अंजलि चौधरी (179-8) पांचवें स्थान पर रहीं। सुरभि राव 158-2 के स्कोर के साथ छठे स्थान पर रहीं, जबकि प्रांजलि प्रशांत धुमाल और मुस्कान ने क्रमश: 138-7 और 117-0 के स्कोर के साथ शीर्ष आठ में अपनी जगह बनाई। क्वालिफिकेशन में ईशा सिंह ने 580-21X के स्कोर के साथ पहले स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उनके बाद सुरभि राव ने 578-12X का स्कोर किया। मुस्कान 577-15X के साथ तीसरे स्थान पर रहीं, जबकि अंजलि चौधरी (575-19X), सैन्यम (575-16X), पलक गुलिया (574-14X) और मनु भाकर (574-11X) ने भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया।

इंडियन वेल्स के चौथे दौर में पहुंचे नोवाक

इंडियन वेल्स, वार्ता। सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सोमवार को इंडियन वेल्स टेनिस गार्डन में अमेरिका के एलेक्जेंडर कोवासेविक को तीन सेट के मुकाबले में हराकर बीएनपी परिबास ओपन के चौथे राउंड में प्रवेश कर लिया। जोकोविच ने सोमवार को एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के तीसरे राउंड में कोवासेविक को 6-4, 1-6, 6-4 से मात दी।

यह 2017 के बाद इंडियन वेल्स में चौथे राउंड में उनकी पहली मौजूदगी होगी। इस आयोजन में पांच बार के चैंपियन जोकोविच इस हफ्ते की शुरुआत में कामिल माजक्जाक के खिलाफ अपने शुरुआती मैच में भी तीन सेट तक खेलना पड़ा था। जोकोविच ने मैच के बाद कहा कि एलेक्स का प्रदर्शन बहुत अच्छा था। हम एक-दूसरे को जानते हैं। हम एक ही भाषा बोलते हैं। उनका पूरा परिवार सर्बियाई है। मुझे मैच में आते ही पता था कि अगर वह अच्छी सर्विस करते हैं और अपनी जगह चुनते हैं, तो उनकी सर्विस को तोड़ना मुश्किल होगा। रोजर फेडरर के साथ सबसे ज्यादा इंडियन वेल्स टाइटल जीतने का रिकॉर्ड साझा करने वाले जोको. विच हाल के सालों में टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं दे सके हैं। उन्हें 2025 में बोटिक वैन डे जैंड्सचुल्प से पहले ही राउंड में चौंकाने वाली हार का स्वाद चखना पड़ा था।

● नोवाक जोकोविच ने इंडियन वेल्स में अमेरिका के एलेक्जेंडर कोवासेविक को तीन सेट मुकाबले में हराया

चुनौतियों के बावजूद, जोको. विच ने टूर्नामेंट में अपनी 17वीं बार मौजूदगी के दौरान एक और मुश्किल मुकाबला किया और अब उनका सामना ग्रह चैंपियन जैक ड्रेपर से होगा, जिन्होंने फ्रांसिस्को सेरुंडोलो को 6-1, 7-5 से हराकर चौथे चरण में जगह बनाई है। जोकोविच ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो, मैं हर समय सच में खेल का आनंद नहीं ले पा रहा हूं। आप इन हालात में अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे होते हैं जब विरोधी जबरदस्त टेनिस खेल रहा हो लेकिन किसी भी तरह जीतना ही मायने रखता है और मुझे खुशी है कि मैं आज इस चुनौती को पार करने में सफल रहा।

इस जीत के साथ ही जोको. विच 1990 में सीरीज शुरू होने के बाद से एटीपी मास्टर्स 1000 प्रतियोगिता के चौथे राउंड में पहुंचने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए। उनसे आगे सिर्फ इवो कार्लोविक हैं, जिन्होंने 2019 में इंडियन वेल्स में 40 साल की उम्र में यह कामयाबी हासिल की थी। इस बीच, स्पेन की युवा प्रतिभा अल्काराज ने एक सेट से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए फ्रांस के आर्थर रिंडरकनेच को 6-7(6), 6-3, 6-2 से हराकर बीएनपी परिबास ओपन के चौथे दौर में प्रवेश किया।

गोल्डन बुलेट्स और सिल्वर बैंडिट्स के बीच होगा फाइनल मुकाबला

नई दिल्ली, वार्ता। दिल्ली गोल्फ क्लब में आज इतिहास दो. हराया गया, जब टीम गोल्डन बुलेट्स और सिल्वर बैंडिट्स दिल्ली गोल्फ क्लब गोल्डन मैंबर्स लीग के लगातार दूसरे सीजन के फाइनल में पहुंच गईं। 2025 में लीग के पहले एडिशन में, गोल्डन बुलेट्स ने सिल्वर बैंडिट्स को हराकर शानदार जीत दर्ज की थी। रविवार, 15 मार्च, 2026 को दोनों टीमें अपनी तरह के पहले फाइनल में फिर से भिड़ेंगी। दिन के आखिरी गेम में, अनुज चंद्रा ने सिल्वर बैंडिट्स के लिए पिन से एक फुट की दूरी पर 40-यार्ड का चिप शॉट मारकर सबका ध्यान खींचा, जिससे उनकी टीम फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल फोर बॉल बेटर बॉल फॉर्मेट में खेला गया, जहां हर जोड़ी का बेहतर स्कोर होल के हिसाब से गिना गया। चारों टीमों में से हर एक ने 12 खिलाड़ी मैदान में उतारे थे, जो 6 ग्रुप में खेल रहे थे।

विंडीज के खिलाफ संजू की पारी टर्निंग पॉइंट थी : गंभीर

● कहा : विंडीज के खिलाफ कोई ऐसा खिलाड़ी वापसी कर रहा था जिसने जिम्बाब्वे के गेम से पहले चार या पांच मैच नहीं खेले

अहमदाबाद, वार्ता। भारत ने अहमदाबाद में फाइनल में न्यूजीलैंड को आसानी से हराकर अपना तीसरा आईसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता। जियोस्टार के 'फॉलो द ब्लूज' पर बात करते हुए, भारत के हेड कोच गौतम गंभीर ने टीम की टाइटल जीत, खिलाड़ियों के अग्रेसिव अप्रोच और टीम के कैंपेन के टर्निंग पॉइंट पर अपने विचार शेयर किए। गंभीर ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि यह कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा अब भी मानना है कि वेस्टइंडीज के खिलाफ संजू की 97 रन की पारी इस कैंपेन का टर्निंग पॉइंट थी क्योंकि फिर से, यह एक वर्चुअल क्वार्टर-फाइनल था और कोई ऐसा खिलाड़ी वापसी कर रहा था जिसने जिम्बाब्वे गेम से पहले चार या पांच मैच नहीं खेले थे।

वर्ल्ड कप गेम में, चाहे ग्राउंड कोई भी हो, वर्चुअल क्वार्टर-फाइनल में 195 रन का पीछा करना कभी आसान नहीं होता। जिस आसानी और शांति से उन्होंने बैटिंग की, मुझे लगता है कि इससे हमें ग्रुप में बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि अब, शायद, हम सही रास्ते पर हैं। उससे पहले, बहुत बातें होती थीं कि हम बाइलेटरल मैचों में बहुत एग्रेसिव खेलते हैं लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट में नहीं। वेस्टइंडीज गेम के बाद, जब संजू ने अच्छा खेला और ईशान किशन ने नंबर तीन पर बैटिंग की, तो मुझे लगा कि बहुत सी चीजें असल में शेप लेने लगी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक कोच के तौर पर वर्ल्ड कप जीतूंगा।

मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इंडियन टीम का हेड कोच बनने का मौका या खास मौका मिलेगा क्योंकि इंडिया की जर्सी फिर से पहनना या देश के लिए कुछ खास करना बहुत बड़ी बात है। जब आपकी मां आपको विश करती है और कहती है 'बहुत बढ़िया', तो आप उसी के लिए खेलते हैं और उसी के लिए जीते हैं। 140 करोड़ भारतीयों को गर्व महसूस कराने से बड़ी और क्या फीलिंग हो सकती है। मैंने हमेशा यही माना है, और मैंने हमेशा लड़कों से भी कहा है, कि उस ड्रेसिंग रूम में होना एक खास मौका है, हक नहीं। हजारों लोग इंडियन टीम के हेड कोच के तौर पर मेरी जगह पर होना चाहेंगे, और कई लोग उस जगह पर होना चाहेंगे जहां खिलाड़ी हैं। टीम के निडर अप्रोच को अपनाने पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जीत से ज्यादा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लड़कों ने हाई-रिस्क, हाई-रिवॉर्ड की आइडियोलॉजी और फिलॉसफी को कैसे अपनाया।

पहले दिन से ही, मेरा पक्का यकीन था कि टी-20 फॉर्मेट इम्पैक्ट के बारे में है। यह माइलस्टोन या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में नहीं है। यह मैदान पर जाकर इम्पैक्ट डालने के बारे में है, चाहे वह मैदान पर हो, बॉल से हो या बैट से। इस पूरे वर्ल्ड कप में सिंपल आइडियोलॉजी यह थी कि अगर हम प्रेशर में रह सकें और हर डिलीवरी को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकें। जो चला गया वह कभी वापस नहीं आएगा, जो चला गया उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते और जो भविष्य में आने वाला है उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप बस उस एक खास डिलीवरी को कंट्रोल कर सकते हैं। भले ही आपको पांच छक्के लग जाएं, अगली डिलीवरी गेम बदलने वाला पल हो सकती है। आखिरकार, यह कुछ ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में, यह सात रन, एक हिट तक सिमट गया। गंभीर ने कहा कि एक बात जो जिंदगी भर मेरे साथ रहेगी, वह यह है कि लड़कों ने कितनी आसानी से बैटिंग पोजीशन को अपनाया और अपनाया। और यह कैप्टन से शुरू हुआ। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में, शिवम को प्रमोट किया गया और सूर्या को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। फाइनल में, हार्दिक को प्रमोट किया गया और कैप्टन को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। पहले कई बार हमने देखा है कि लोग एक खास पोजीशन पर बैटिंग करना चाहते हैं, लेकिन इस टीम के साथ ऐसा नहीं था। तिलक ने नंबर तीन से शुरुआत की, फिर उन्होंने पांच, छह और यहां तक

विंडीज दौरे के लिए सोफी मोलिनेक्स की टीम में वापसी

मेलबर्न, वार्ता। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए अपनी महिला टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें ऑलराउंडर सोफी मोलिनेक्स की चोट के बाद वापसी हुई है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 19 मार्च से शुरू होने वाले इस दौरे पर तीन टी-20 और तीन वनडे मैच खेलेगी। यह सीरीज आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 की तैयारी का हिस्सा है। मोलिनेक्स हाल ही में पीठ की चोट के कारण भारत के खिलाफ घरेलू बहु-प्रारूप श्रृंखला का बड़ा हिस्सा नहीं खेल सकी थीं। उन्हें अब 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। अनकैप्ड बल्लेबाज ताहलिया विल्सन को भी पहली बार टीम में जगह मिली है, जबकि लूसी हैमिल्टन और निकोल कैरी ने भारत के खिलाफ अच्छे प्रदर्शन के बाद अपनी जगह बरकरार रखी है। ग्रेस हैरिस और एनेबेल सदरलैंड इस दौरे में नहीं खेलेंगी। मुख्य चयनकर्ता शॉन फ्लेग्लर ने कहा कि टी-20 विश्व कप से पहले यह सीरीज टीम के लिए महत्वपूर्ण तैयारी का अवसर होगी। टीम : सोफी मोलिनेक्स (कप्तान), एश्ले गार्डनर (उपकप्तान), ताहलिया मैक्ग्रा (उपकप्तान), डार्सी ब्राउन, निकोल कैरी, किम गर्थ, लूसी हैमिल्टन, अलाना किंग, फीबी लिचफील्ड, बेथ मूनी, एलिस पेरी, मेगन शुट, जॉर्जिया वोल, जॉर्जिया वेयरहैम, ताहलिया विल्सन।

सार्वजनिक सूचना

मेरा नाम WAHIDA BEGUM है जिसको बदलकर मैंने अपना नाम VAHEEDA कर लिया है भविष्य में मुझे VAHEEDA W/O SHADDIK ALI के नाम से जाना जाये। निवासी शाहपुर पोस्ट ऑफिस भगवानपुर जिला हरिद्वार, उत्तराखंड - 247661.

सार्वजनिक सूचना

मेरा नाम MOHD SHAJID है जिसको बदलकर मैंने अपना नाम SAJID कर लिया है भविष्य में मुझे SAJID S/O MAUHATASIM के नाम से जाना जाये। निवासी संघीपुर संघीपुर जिला हरिद्वार, उत्तराखंड - 247664.

सार्वजनिक सूचना

मेरा नाम TASEEN AHMAD है जिसको बदलकर मैंने अपना नाम TAHSEEN कर लिया है भविष्य में मुझे TAHSEEN S/O ALLAH RAKHA के नाम से जाना जाये निवासी मोहल्ला पठानपुरा मंगलौर डाकघर मंगलौर टाउन जिला हरिद्वार, उत्तराखंड-247656.

सार्वजनिक सूचना

मेरा नाम SHABNAM है जिसको बदलकर मैंने अपना नाम SHABNAM JAMAL कर लिया है। भविष्य में मुझे SHABNAM JAMAL W/O ZAHEER HASAN के नाम से जाना जाये। निवासी भंगेडीमहावतपुर पोस्ट मिलापनगर जिला हरिद्वार उत्तराखंड -247666.

लक्सर के नगला खिताब में आधी रात को अज्ञात युवकों ने फैलायी दहशत

अंधाधुंध फायरिंग, मांगी 10 लाख की रंगदारी

शाह टाइम्स संवाददाता

लक्सर। क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगला खिताब में बीती रात बदमाशों ने सरेआम कानून को चुनौती दी।

जानकारी के अनुसार रात करीब 12:10 बजे बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक घर को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर देकर जान-माल की सुरक्षा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। **रंगदारी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम**-पीड़ित चौधरी गौरव कुमार ने बताया कि घटना से पहले उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं। हमलावरों ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए गौरव और उनके एक मित्र से 5-5 लाख रुपये (कुल 10 लाख) की रंगदारी मांगी थी। गौरव ने बताया कि वह शाम को पुलिस थाने में तहरीर लिख ही रहे थे कि उन्हें लगातार फोन और व्हाट्सएप कॉल आ रहे थे, जिसे उन्होंने रिसीव नहीं किया। **फायरिंग की पूरी घटना**-गौरव के मुताबिक, जैसे ही वह थाने से तहरीर देकर घर पहुंचे, तभी दो मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए बदमाशों ने घर के बाहर मोर्चा संभाल लिया और अलग-अलग मौजर (हथियारों) से धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। **चश्मदीद का बयान:** गौरव के चाचा ने बताया, ष्मैं घर पर ही था, रात करीब 12:10 बजे अचानक पटाखों जैसी आवाज आई। बाद में पता चला कि वे गोलियां थीं, जो दरवाजे को चीरती हुई पार निकल गईं। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस की कार्रवाईघटना की सूचना मिलते ही लक्सर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और वहां हुई फायरिंग के निशानों की वीडियोग्राफी की।

❖ लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दी जा रही है पीड़ित को धमकी

❖पीड़ित ने मुंडा खेड़ा खुर्द के कुछ युवकों व साथियों पर शक जताते हुए दी तहरीर

❖पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गोलियों के निशानों की वीडियोग्राफी करने के साथ आप की तलाश में जुटी

पीड़ित ने मुंडा खेड़ा खुर्द के कुछ युवकों और उनके साथियों पर शक जताते हुए नामजद तहरीर दी है। दहशत में परिवारगौरव कुमार ने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि वह अपने बच्चों और परिवार की सुरक्षा को लेकर बेहद डरे हुए हैं। उन्हें डर है कि बाजार या स्कूल जाते वक्त ये लोग किसी बड़ी अप्रिय घटना को अंजाम न दे।

एक नशा तस्कर दबोचा 18.20 ग्राम स्मैक बरामद

शाह टाइम्स संवाददाता

भगवानपुर। थाना पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को दबोच कर उसके पास से 18.20 ग्राम अवैध स्मैक बरामद करते हुए आरोपी खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उतराखण्ड के "ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान" के अन्तर्गत उनके मिशन को साकार करने हेतु ै च हरिद्वार द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तो के विरूद्ध कडी कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। उपरोक्त क्रम में प्रभारी निरीक्षक भगवानपुर के नेतृत्व में थाना भगवानपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए को दौराने चैकिंग खेलपुर रोड भगवानपुर से आरोपित अफजाल पुत्र छोटन निवासी-ग्राम खेलपुर थाना भगवानपुर जिला हरिद्वार को 18.20 ग्राम अवैध स्मैक के साथ पकडा गया। आरोपित के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। पुलिस टीम में अ०उ०नि० प्रदीप चौहान, कानि० राहुल0, कानि० रविन्द्र राणा आदि शामिल रहे।

गोकशी करते एक आरोपी मांस सहित गिरफ्तार

शाह टाइम्स संवाददाता

लक्सर। जनपद में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत लक्सर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। ग्राम रणसूरा में गोकशी की सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जबकि उसके अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे।

क्या है पूरामामला-लक्सर पुलिस को मुखबिर के जरिए ग्राम रणसूरा में गोकशी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। खेतों की ओर जाने वाली सड़क पर कुछ संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें पुलिस ने घेराबंदी कर एक युवक को दबोच लिया।बरामदगी और गिरफ्तारीपकड़े गए आरोपी के पास से भारी मात्रा में गोमांस और गोकशी में इस्तेमाल होने वाले धारदार उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:गिरफ्तार अभियुक्त: अमीर (22 वर्ष) पुत्र समीम, निवासी ग्राम रणसूरा, कोतवाली लक्सर हरिद्वार।फरार आरोपी: अन्य अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए क्षेत्र में दबिश दी जा रही है। आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

सीएफओ ने फायर स्टेशन रुड़की व भगवानपुर का किया निरीक्षण

शाह टाइम्स संवाददाता

रुड़की। मुख्य अग्निशमन अधिकारी वंश बहादुर यादव ने फायर स्टेशन रुड़की एवं फायर स्टेशन भगवानपुर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम अग्निशमन अधिकारी रुड़की वंश नारायण यादव एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी भगवानपुर केशवदत्त तिवारी द्वारा मुख्य अग्निशमन अधिकारी को सलामी दी गई। इसके पश्चात मुख्य अग्निशमन अधिकारी यादव ने फायर स्टेशन प्रांगण में फॉलीन परेड का निरीक्षण कर सभी कर्मचारियों के टर्न-आउट की जांच की। निरीक्षण में सभी कर्मचारी निर्धारित एवं साफ-सुथरी वर्दी में पाए गए। इस दौरान उन्होंने कर्मचारियों से उनकी व्यक्तिगत एवं विभागीय समस्याओं के बारे

में भी जानकारी ली, जिस पर किसी कर्मचारी द्वारा कोई समस्या नहीं बताई गई। परेड निरीक्षण के उपरांत दोनों फायर स्टेशनों में उपलब्ध टर्न-आउट वाहनों का निरीक्षण किया गया। चालकों द्वारा सभी वाहनों को स्टार्ट कर उनकी कार्यशीलता प्रदर्शित की गई। इसके बाद मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने एफएसओ कार्यालय, स्टोर तथा एमटी स्टोर के अभिलेखों का भी अवलोकन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी वाहनों को सदैव उच्च कोटि की कार्यशील स्थिति में रखा जाए तथा समय-समय पर मोबिल ऑयल सहित अन्य आवश्यक तकनीकी जांच नियमित रूप से की जाती रहे। निरीक्षण के दौरान वॉचरूम ड्यूटी की भी जांच की गई, जहां ड्यूटी पर तैनात फायरमैन वर्दी में सतर्क एवं सजग पाए गए तथा संचार व्यवस्था भी पूर्णत: कार्यशील पाई गई। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने निर्देशित किया कि वॉचरूम संचार का मुख्य केंद्र होता है, इसलिए यहां तैनात कर्मियों को सदैव अपडेट एवं सतर्क रहना चाहिए। साथ ही सभी कर्मचारियों को एमडीटी प्रणाली का ज्ञान होना भी आवश्यक बताया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने फायर स्टेशन की बैरकों और भोजनालय का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बैरक एवं भोजनालय का रखरखाव संतोषजनक एवं उत्तम पाया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि अग्निकांड के दौरान टर्न-आउट करते समय निर्धारित वर्दी एवं पीपीई किट का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को अनुशासन में रहकर अपनी ड्यूटी का निर्वहन करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने अग्निशमन अधिकारी रुड़की एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी भगवानपुर को कर्मचारियों की शारीरिक फिटनेस के लिए नियमित पीटी एवं व्यायाम कराने के निर्देश दिए। साथ ही अग्निशमन एवं आपात सेवा मुख्यालय तथा उच्च अधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित करने को कहा। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ राष्ट्र की नींव है, इसलिए सभी कर्मचारियों को सदैव फिट रहने, नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रहने तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों को समय-समय पर प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत करने की भी आवश्यकता है। निरीक्षण के दौरान अग्निशमन अधिकारी रुड़की श्री वंश नारायण यादव, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी भगवानपुर श्री केशवदत्त तिवारी, लीडिंग फायरमैन अतर सिंह राणा, लीडिंग फायरमैन भगवती प्रसाद, लीडिंग फायरमैन राजेश कुमार, चालक विपिन सिंह तोमर, चालक मोहन सिंह नेगी सहित समस्त अंडर ऑफिसर एवं अन्य स्टाफ मौजूद रहे।

दो अलग-अलग पिकअप वाहन से 6 गोवंशीय पशु बरामद, दो गिरफ्तार

शाह टाइम्स संवाददाता

भगवानपुर। थाना कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो अलग-अलग वाहनों में छ : गोवंशीय पशु को बरामद कर दो लोगों को गिरफ्तार किया है वहीं एक युवक भागने में कामयाब रहा।

जानकारी के अनुसार एसएसपी हरिद्वार द्वारा गोवंशीय पशुओं को वाहनो में क्रूरता पूर्वक परिवहन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्द 'पशु क्रूरता अधिनियम' में कार्रवाई किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उपरोक्त क्रम में कोतवाली भगवानपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए दौराने चौकिंग गागलहेडी अंडरपास के पास पिकअप को चौक किया गया तो चालक के साथ बैठा व्यक्ति खिडकी खोलकर मौके से फरार हो गया। चालक से नाम पता पूछने पर चालक द्वारा अपना नाम 'शोयब पुत्र हमीद' निवासी-सिकरोडा कोतवाली भगवानपुर जिला हरिद्वार बताया गया। पिकअप के डाले को चौक करने पर डाले में 04 गोवंशीय पशुओं को क्रूरता पूर्वक परिवहन किया जा रहा था। पशु चिकित्सा अधिकारी को मौके पर बुलाकर गोवंश का मैडिकल करवाया गया है। व साथी फरार अभियुक्त 'शेहरफ पुत्र मकसूद' निवासी-ग्राम सिकरोडा कोतवाली भगवानपुर जिला हरिद्वार की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। उपरोक्त प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। वही अलावलपुर के पास चेकिंग के दौरान एक और पिकअप वाहन से दो गोवंशीय पशु को बरामद करते हुएसलीम पुत्र मौ० इखलाक ग्राम गन्देवडा थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर उ०प्र० गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम-उ०नि० सुनील रमोला, कानि० दीपक मंमगाई, कानि० रविन्द्र राणा शामिल रहे।

सीबीआरआई में फ्लावर शो का आयोजन

शाह टाइम्स संवाददाता

रुड़की। सीएसआईआर केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), रुड़की में मंगलवार को 51वां वार्षिक फ्लावर शो उत्साह और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस वर्ष की थीम ष्पर्यावास और प्रकृति का सामंजस्यष रही, जो आधुनिक मानव आवास और प्राकृतिक संतुलन के बीच एक सेतु का कार्य करती दिखी। रंग-बिरंगे फूलों और दुर्लभ पौधों की खुशबू से पूरा संस्थान परिसर सराबोर रहा।

प्रकृति और विकास का संतुलन-संस्थान के निदेशक प्रो. आर. प्रदीप कुमार ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि फूल न केवल सुंदरता के प्रतीक

हैं, बल्कि वे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सतत विकास तभी संभव है जब हम अपने प्राकृतिक संसाधनों और हरियाली के संरक्षण को प्राथमिकता दें। डॉ. चंदन स्वरूप मीना ने अपने स्वागत उद्बोधन में आयोजन की महत्ता पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने सामूहिक रूप से इस बात को दोहराया कि यह प्रदर्शनी केवल फूलों का प्रदर्शन नहीं, बल्कि प्रतिभागियों की कड़ी मेहनत और प्रकृति के प्रति अटूट प्रेम का जीवंत उदाहरण है। पुष्प प्रदर्शनी के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं ने दर्शकों का मन मोह लिया। इनमें पुष्प सज्जा: फूलों को कलात्मक रूप देकर पर्यावरण का संदेश दिया गया। गमला प्रदर्शनी: विभिन्न सजावटी और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों का प्रदर्शन। बागवानी श्रेणियाँ: विशेषज्ञों और शौकिया बागवानों की रचनात्मकता की सराहना की गई। कार्यक्रम का एक विशेष आकर्षण अस्वथी, दीप्ति कर्माकर और मिस दीक्षा गुप्ता द्वारा आयोजित फैशन शो रहा। इस शो ने पारंपरिक पुष्प प्रदर्शनी में आधुनिकता और उत्साह का एक नया रंग भर दिया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में संयोजिका डॉ. लीना चौरसिया और सह-संयोजक डॉ. सोजू एलेक्जेंडर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉ. लीना चौरसिया ने अंत में सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों का मुख्य उद्देश्य समाज में प्रकृति के प्रति जागरूकता पैदा करना है। प्रदर्शनी ने न केवल रुड़की के निवासियों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सशक्त प्रेरणा भी दी।

विधानसभा सत्र के दौरान पुलिस उपाधीक्षक अखिलेश ने संभाली गार्ड ऑफ ऑनर की कमान

शाह टाइम्स संवाददाता

रुड़की। सोमवार को घर्षण में विधानसभा बजट सत्र से पूर्व महामहिम राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्ति को विधान सभा परिसर में पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया इस गार्ड ऑफ ऑनर की कमान पुलिस उपाधीक्षक अखिलेश कुमार ने संभाली। सोमवार को राज्य की गैरसैण में विधनसभा बजट सत्र का शुभारंभ हुआ इस दौरान महामहिम राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्ति व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तथा विधनसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी आदि जब विधानसभा पहुंचे तो इस दौरान जवानों द्वारा विधानसभा परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कमान नरेंद्र नगर पीटीसी के डिप्टी एसपी अखिलेश कुमार ने संभाली।

लाइनमैन की तैनाती की मांग

रुड़की। भारापुर के प्रधान अजय कुमार, हलवाहेड़ी के प्रधान शौकत अली, नगला खुर्द के प्रधान, बीडीसी सदस्य दीपक राम और मुबारिक अली ने ऊर्जा निगम के अधीक्षण अभियंता विवेक राजपूत से मिलकर रहमतपुर बिजलीघर से जुड़े एक लाइनमैन पर कई आरोप लगाए।

संबंध विच्छेद सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र पुलकित व उसकी पत्नी हिमानी का आचरण मेरे व मेरे परिवार के प्रति ठीक न होने के कारण मैंने पुलकित व हिमानी को अपनी तमाम चल व अचल संपत्ति से बेदखल कर संबंध विच्छेद कर लिया है। आज के बाद उक्त दोनों के किसी भी अनैतिक कृत्य व लेनदेन की मेरे व मेरे परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। **प्रमिला पत्नी मेघराज नि. पुरूषोत्तम नगर पथरी फोरेस्ट रेंज हरिद्वार अम्बुवाला।**

नाबालिग को अपहरण कर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

शाह टाइम्स संवाददाता

बुग्गावाला। थाना बुग्गावाला क्षेत्र में नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सक्रिय हुई पुलिस टीम ने डिजिटल साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को उसके गांव से दबोच लिया।

कोतवाली बुग्गावाला क्षेत्र की एक महिला ने 5 मार्च 2026 को थाने में लिखित तहरीर देकर बताया कि परमजीत पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम बड़ी लाम, थाना भगवानपुर, जनपद हरिद्वार उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। शिकायत के आधार पर कोतवाली बुग्गावाला में मुकदमा संख्या 16/2026 सुसंगत धाराओं में दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई। मामले की विवेचना महिला उप निरीक्षक प्रीति तोमर को सौंपी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अध ीक्षक हरिद्वार ने आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके बाद प्रभारी निरीक्षक बुग्गावाला के नेतृत्व में पुलिस टीमों का गठन कर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया और पुलिस ने आरोपी परमजीत को उसके गांव लाम से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में महिला उप निरीक्षक प्रीति तोमर, अपर उप निरीक्षक अरविंद भट्ट, हेड कांस्टेबल गोपाल कुमार और कांस्टेबल विक्रम शामिल रहे।

उच्च न्यायालय नैनीताल की मुहिम से लक्सर में

गांव के आखिरी छोर तक पहुंचेगा न्याय

शाह टाइम्स संवाददाता

लक्सर। न्याय की पहुँच अब केवल कचहरी की चहारदीवारी तक सीमित नहीं रहेगी। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (नैनीताल) के निर्देशानुसार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार के सहयोग से लक्सर के ग्रामीण क्षेत्रों में आखिरी छोर तक न्याय पहुँचाने के लिए एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े गरीब नागरिकों और वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना है। आपसी समझौते से सुलझेंगे विवाद- अभियान की टीम में शामिल पंकज एडवोकेट (हरिद्वार) ने बताया कि उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया किगाँवों में विधिक जानकारी देकर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा हैछोटे-बड़े विवादों को आपसी समझौते के जरिए निपटाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि कोर्ट-कचहरी के चक्कर कम हों और समाज में भाईचारा बना रहे।न्यायालय की मंशा है कि ष्न्याय सबके लिएष का सपना सच हो

मिलेगा पूरी तरह निःशुल्क इंसाफ-सेवानिवृत्त अधिवक्ता अनीता भारद्वाज ने इस मुहिम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जहाँ गरीब व्यक्ति न्याय की उम्मीद छोड़ देता है, वहाँ सरकार और प्राधिकरण मशाल बनकर पहुँच रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा: किसी भी गरीब नागरिक को अपना केस लड़ने के लिए एक रुपया भी खर्च नहीं

करना पड़ेगा। वकील पूरी तरह निःशुल्क केस लड़ेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन-कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार की मंशा है कि हर नागरिक को उसके घर के पास ही सुलभ और सस्ता न्याय मिलेमुहिम की मुख्य बातेंसेवा विवरण लक्ष्य, समाज के अंतिम व्यक्ति तक कानूनी मदद पहुँचाना खर्च, पात्र गरीब नागरिकों के लिए पूरी तरह मुफ्त तरीका, विधिक शिविर, परामर्श और लोक अदालत के माध्यम से समझौता, क्षेत्र लक्सर के दूरस्थ ग्रामीण इलाके।

अवैध सीवर कनेक्शन पर राजस्व अभियंता का छापा

शाह टाइम्स संवाददाता

रुड़की। शहर में सीवर अवैध कनेक्शन पर उत्तराखंड जल संस्थान गंगा के राजस्व अभियंता मोहित राणा का छापा अवैध सीवर कनेक्शन की जांच के लिए देहरादून से विजिलेंस कारवाई करेगी गौरतलाब है कि जल संस्थान में शासन द्वारा विजिलेंस गठित कर दी गई है रुड़की शहर में लगातार हों रहे निर्माण कमर्शियल कॉम्प्लेक्स प्रतिष्ठानों का निमार्ण युद्ध स्तर पर चल रहा है जिनके सीवर कनेक्शन भी किए जाने मैंडेटरी है आर बड़े प्रतिष्ठानों को नियमानुसार एटीपी एसटीपी पीसीबी के पैरामीटर अनुसार जरूरी है परंतु कुछ प्रतिष्ठान नियमों का पालन ना कर अवैध सीवर हेतु टीम का गठन भी कर लिया गया है जो अवैध कनेक्शंस की जांच कर नोटीस ओर जुर्माने की कारवाई करेगी।

आज टीम ने सिविल लाइंस और हरिद्वार रोड़ पर दो बड़े कॉम्प्लेक्स की माप की है और नॉटिस की तैयारी की जा रही है मलकपुर चुंगी पर एक कॉम्प्लेक्स की रिपोर्ट तयार कर एचआरडीए को भी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी उक्त कॉम्प्लेक्स द्वारा खुले आम रोड़ पर गंदा पानी बहाया जा रहा है जिसकी शिकायत लोगो द्वारा उपखंड अधिकारी जुनैद गौड से की गई थी।रुड़की नगर अनेक सरकारी गैर सरकारी बड़े कार्याल्य है जिनमे सीवर संचालन अनुरक्षण शाखा गंगा विभाग द्वारा किया जाता है रुड़की नगर में घेरलू अघेरलु कनेक्शंस की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम मोहल्लावार जांच करेगी और अवैध कनेक्शंस पाए जाने पर नोटिस और जुर्माने की कारवाई की जाएगी। आज सिविल लाइंस मार्केट में राजस्व अभियंता मोहित राणा ने छापा मारा और अनेक प्रतिष्ठानों और मिठाई की दुकानों पर अवैध कनेक्शन के नोटिस चस्पा किए इसके अतिरिक्त हरिद्वार रोड पर बार पर भी अवैध कनेक्शन पर नोटिस चस्पा कर दिए गए है राजस्व जे ई मोहित राणा ने कहा कार्यवाही अनवरत चलती रहेगी अवैध कनेक्शन धारको पर एफ आई आर की कार्यवाही की जा रही है अगले सप्ताह विजिलेंस भी रुड़की नगर में जांच करेगी। अवैध कनेक्शन पकड़े जाने पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

शाह टाइम्स

सम्पादकीय

बुधवार, 11 मार्च 2026

Dainikshahtimes@gmail.com For Articles

पद की गरिमा

गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नौवें अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन में भाग लेने के दौरान कथित लापरवाही के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह कथित लापरवाही प्रोटोकॉल, मार्ग सुरक्षा और कार्यक्रम स्थल प्रबंधन से संबंधित हैं। पश्चिम बंगाल में आयोजित इंटरनेशनल संथाल कॉन्क्लेव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के दौरे से जुड़ा विवाद केवल कार्यक्रम में व्यवस्था तक सीमित नहीं। यह मामला अब संवैधानिक गरिमा, प्रशासनिक जवाबदेही और चुनावी राजनीति का बन चुका है। राष्ट्रपति का खुद सार्वजनिक रूप से खामियों की ओर इशारा करना भी सामान्य बात नहीं है। विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब कार्यक्रम स्थल आखिरी समय में बदल दिया गया। स्थानीय प्रशासन का तर्क था कि मूल स्थान भीड़भाड़ वाला था, लेकिन राष्ट्रपति ने खुद उस स्थान का दौरा किया और कहा कि जगह पर्याप्त थी। इसके अलावा प्रोटोकॉल के उल्लंघन और दूसरी लाप. रवाही की बात भी कही जा रही है। भारत में राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर माना जाता है। केंद्र और राज्यों में सरकार चाहे किसी की भी हो, लेकिन राष्ट्रपति का कार्यक्रम कभी किसी राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ता। यह पद किसी व्यक्ति की नहीं, देश की गरिमा और प्रतिष्ठा से जुड़ा है। ऐसे में अगर राष्ट्रपति खुद यह महसूस करती हैं कि उनके सम्मान का ख्याल नहीं रखा गया, तो कई सवाल खड़े होते हैं। राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल को लेकर सख्त नियम है, जिनका पालन हर हाल में करना होता है। राष्ट्रपति को आमतौर पर राज्य के मुख्यमंत्री रिसीव करते हैं या उनकी तरफ से नॉमिनेट उनका कोई मिनिस्टर। बताया जा रहा है कि बंगाल में ऐसा नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने इस चुक पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन इस घटना से जुड़ा एक दूसरा पहलू भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और वह है पश्चिम बंगाल की राजनीति। राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और मुख्य टक्कर बीजेपी टीएमसी के बीच मानी जा रही। चुनावी मैदान की यही तल्खी अब संवैधानिक परंपराओं में दिख रही है। टीएमसी ने केंद्र पर राष्ट्रपति पद के राजनी. तिक इस्तेमाल का आरोप लगाया है। सीएम ममता बनर्जी कह रही हैं कि कोई प्रोटोकॉल नहीं टूटा। यह कार्यक्रम संथाल आदिवासियों से जुड़ा था। राष्ट्रपति खुद इस समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन, अब ध्यान मुख्य मुद्दे से हटकर इस विवाद की ओर चला गया। इस मामले से यह भी पता चलता है कि देश में कई बार बड़े आयोजनों तक की तैयारी आखिरी वक्त तक चलती रहती है। अगर राष्ट्रपति के दौरे से जुड़े सारे इंतजाम पहले ही पूरे होते, तो शायद यह विवाद खड़ा ही नहीं होता।

देश की जनता सच्चाई जान ही जाएगी

मोदी सरकार ने लोकसभा अध्यक्ष नाम की संस्था की आजादी खत्म कर दी है, लेकिन विपक्ष उसे बचाने में लगा है, इसी मसले पर व्यापक चर्चा के मकसद से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ये लोग हर संस्था को खत्म करने की कोशिश करते हैं, हम हर उस संस्था को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जिनके ऊपर भारत का लोकतंत्र टिका हुआ है, भाजपा के लोगों को यही बातें पचती नहीं हैं, मेरी दादी इंदिरा जी कहती थीं कि कोई नकली बनने की कोशिश करे या झूठी इमेज दिखाए, देश की जनता उसकी सच्चाई जान ही जाएगी, मेरे भाई राहुल गांधी हमेशा सच बोलते हैं, वो देश में एक ही व्यक्ति हैं, जो मोदी सरकार के आगे झुके नहीं हैं, भाजपा ने उन्हें रोकने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर दिए, सोशल मीडिया कैंपेन चलाए, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। **-प्रियंका गांधी, महासचिव कांग्रेस**

परिसीमन 2026 : लोकतंत्र का संतुलन या राजनीति की नई जंग

रश्मि चौधरी

परिसीमन (डेलिमिटेशन) लोकतंत्र की वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं और प्रतिनिधियों की संख्या तय की जाती है। भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली और 1950 में संविधान लागू हुआ, लेकिन लोकतंत्र की वास्तविक शुरुआत 1952 के पहले आम चुनावों से हुई। इन चुनावों की आधारभूमि 1951 की जनगणना और उसके आधार पर किए गए परिस. ीमन ने तैयार की थी। परिसीमन यह सुनिश्चित करता है कि बदलती जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व संतुलित और न्यायसंगत बना रहे। इसलिए यह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की संरचना को आकार देने वाली केंद्रीय व्यवस्था है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता ने राजनीतिक आजादी दी, संविधान ने शासन की रूपरेखा दी, जबकि परिसीमन और 1952 के चुनावों ने भारत में लोकतंत्र को वास्तविक रूप में स्थापित किया।

परिसीमन की प्रक्रिया: कैसे होता है सीटों का निर्धारण और कौन करता है फैसला

परिसीमन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसकी शुरुआत नई जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों से होती है। जनगणना के बाद केंद्र सरकार एक स्वतंत्रप रिसीमन आयोगका गठन करती है, जिसमें आमतौर पर सर्वोच्च न्यायालय के सेवा. निवृत्त न्यायाधीश यानि अध्यक्ष, चुनाव आयोग के प्रतिनिधि और संबंधित राज्यों के चुनाव आयुक्त सदस्य होते हैं। यह आयोग जनसंख्या के अनुपात के आधार पर लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं तथा सीटों की संख्या निर्धारित करता है, ताकि प्रत्येक प्रतिनिधि लगभग समान जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। आयोग सार्वजनिक सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं तथा उन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व को संतुलित और निष्पक्ष बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था मानी जाती है।

परिसीमन आयोग के फैसलेरू क्यों नहीं दी गई चुनौती की अनुमति?

परिसीमन आयोग की रिपोर्ट को अदालत में चुनौती न देने का प्रावधान इसलिए बनाया गया है ताकि निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण की प्रक्रिया न्यायिक विवादों में उलझकर वर्षों तक न अटके और चुनाव प्रक्रिया बाधित न हो। संविधान निर्माताओं ने गहन विचार के बाद परिसीमन आयोग को एक स्वतंत्र और अंतिम प्राधिकरण का दर्जा दिया, जिसकी अधिसूचित रिपोर्ट बाध्यकारी होती है और उस पर न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

परिसीमन का आधार जनगणना के आंकड़े होते हैं, ताकि जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व संतुलित और न्यायसंगत बना रहे। स्वतंत्रता के बाद यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक था कि लो. कतंत्र केवल कुछ प्रभावशाली वर्गों तक सीमित न रह जाए। इसलिए जनसंख्या बढ़ने के साथ प्रति. निधियों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जिससे नए सामाजिक वर्ग, क्षेत्र और आवाजें राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हो सकें। इस प्रकार, परिसीमन आयोग के निर्णयों को अंतिम रखने का उद्देश्य लोकतंत्र को कमजोर करना नहीं, बल्कि उसे स्थिर, निरंतर और अधिक प्रतिनिधिक बनाना है।

परिसीमन का आम जनता पर प्रभाव: प्रतिनिधित्व, संवाद और लोकतंत्र की सेहत

परिसीमन का सीधा प्रभाव आम जनता और उनके जनप्रतिनिधियों के संबंध पर पड़ता है। लो. कतंत्र में सांसद और विधायक जनता की आवाज होते हैं, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि एक प्रति. निधि कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है। 1970 के दशक में लगभग10 लाख लोगों पर एक सांसदऔरलगभग 1।37 लाख लोगों पर एक विधायकका प्रतिनिधित्व निर्धारित था, ताकि जनता और प्रतिनिधि के बीच संवाद बना रहे, लेकिन दशकों तक सीटों की संख्या स्थिर रहने से आज एक प्रतिनिधि पर पहले की तुलना में कहीं अधिक जनसंख्या का भार है। इससे जनप्रतिनिधि के लिए हर नागरिक या समुदाय तक पहुंचना कठिन हो जाता है और जनता व प्रतिनिधि के बीच दूरी बढ़ जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार, जहां प्रति. निधियों और नागरिकों के बीच सीधा संवाद अधिक होता है, वहां लोकतंत्र अधिक मजबूत और जवाबदेह होता है। इसलिए परिसीमन की प्रक्रिया आवश्यक है, ताकि जनसंख्या के अनुसार सीटों का पुनर्निर्धारण हो सके और लोकतंत्र में संतुलित, प्रभावी और उत्तरदाई प्रतिनिधित्व बना रहे।

परिसीमन और राजनीतिक शक्ति: क्या बदलता है संतुलन?

परिसीमन को लेकर अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या इससे किसी क्षेत्र की राजनीतिक ताकत बढ़ती या घटती है। विशेषज्ञों के अनुसार लोकतंत्र में मूल मुद्दा राजनीतिक ताकत नहीं, बल्किजनता के प्रतिनिधित्व का संतुलनहै। परिसीमन संविधान केअनुच्छेद 82 और 172के तहत निर्धारित एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य बदलती जनसंख्या के अनुसार प्रतिनिधित्व को संतुलित बनाए रखना है। जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ने पर देश में हवाई अड्डे, सड़कें, अस्पताल और अन्य बुनियादी ढांचे बढ़ाए जाते हैं, उसी प्रकार राजनी. तिक प्रतिनिधित्व का विस्तार भी आवश्यक माना जाता है। परिसीमन इसी सिद्धांत पर आधारित है कि बढ़ती जनसंख्या के अनुरूप प्रतिनिधियों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण हो।इसलिए परिसीमन किसी क्षेत्र की राजनीतिक ताकत बढ़ाने या घटाने का साधन नहीं, बल्कि लो. कतंत्र को अधिक संतुलित, उत्तरदाई और प्रभावी बनाने की एक महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था है।

परिसीमन पर रोक: राजनीतिक कारण या लोकतांत्रिक चिंता?

स्वतंत्रता के बाद 1952, 1962 और 1972 में परिसीमन की प्रक्रिया नियमित रूप से हुई, जिसका उद्देश्य जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों और प्रतिनिधित्व को संतुलित बनाए रखना था। परिसीमन केवल सीटों की संख्या ही नहीं, बल्कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं भी बदलता है, जिससे राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों में परिवर्तन आता है और नए नेताओं व वर्गों के लिए राजनीति में प्रवेश की संभावना बनी रहती है, लेकिन 1970 के दशक में आपातकाल (1975-77) के दौरान परिसीमन पर रोक लगा दी गई और संविधान संशोधन के माध्यम से लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या पहले 2001 तक तथा बाद में 2026 तक स्थिर कर दी गई। इसका आधिकारिक कारण यह बताया गया कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्हें प्रतिनिधित्व में नुकसान न हो। हालांकि, आलोचकों का मानना है कि सीटों और क्षेत्रों के लंबे समय तक स्थिर रहने से राजनीतिक संरचना में बदलाव कम हुआ। इसलिए परिसीमन पर लगी रोक प्रशासनिक, जनसंख्या-संतुलन और राजनीतिक तीनों कारणों से जुड़ी बहस का विषय बनी हुई है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव लोकतंत्र की गतिशीलता और प्रतिनिधित्व की समानता पर पड़ता है।

परिसीमन, जनसंख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्वरू आरक्षण, युवा और महिलाओं पर संभावित प्रभाव

परिसीमन का मुख्य आधारजनसंख्या के आंकड़ेहोते हैं, जिनके आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या तथा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय की जाती हैं। यदि किसी राज्य में सीटों की संख्या बढ़ती है, तो उसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिससे सीमाओं का पुनर्गठन होता है। परिसीमन का प्रभावअनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ST के आरक्षण पर भी पड़ता है। वर्तमान में लोकसभा में 131 सीटें एससी/एसटी के लिए आरक्षित हैं और उनका निर्धारण जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया गया है। नई जनगणना के बाद परिसीमन होने पर आरक्षित सीटों की संख्या भी बदल सकती है। इसके अलावा परिसीमनयुवाओं की राजनीतिक भागीदारीको भी प्रभावित कर सकता है। शुरुआती चुनावों में 40 वर्ष से कम आयु के सांसदों की संख्या 30 प्रतिशत से अधिक थी, जो अब घटकर लगभग 12.13 प्रतिशत रह गई है। नए निर्वाचन क्षेत्रों और सीटों के बढ़ने से युवा नेतृत्व के लिए अवसर बढ़ सकते हैं। महिला आरक्षण कानूनके क्रियान्वयन से भी परिसीमन जुड़ा हुआ है, क्योंकि नए निर्वाचन क्षेत्रों के निर्धारण के बाद ही महिला आरक्षण लागू किया जा सकेगा। इसलिए परिस. ीमन केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं, बल्कि आरक्षण, युवाओं और महिलाओं के प्रतिनिधित्व सहित लोकतंत्र के व्यापक ढांचे को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण व्यवस्था है।

परिसीमन पर रोक: लोकतंत्र पर असर या राजनीतिक आशंका?

परिसीमन पर संभावित रोक को लेकर देश में बहस जारी है। परिसीमन का उद्देश्य जनसंख्या के अनुपात में निर्वाचन क्षेत्रों और प्रतिनिधियों की संख्या तय करना है, ताकि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व संतुलित बना रहे। आलोचकों का तर्क है कि यदि इस प्रक्रिया को लंबे समय तक टाला जाता है, तो जनसंख्या और प्रतिनिधित्व के बीच असंतुलन बढ़ सकता है और कुछ क्षेत्रों में राजनी. तिक शक्ति अधिक केंद्रित हो सकती है। भारत में स्वतंत्रता के बाद कई बार परिसीमन हुआ, लेकिन 1970 के दशक में सीटों की संख्या पर रोक लगा दी गई, जिसे बाद में 2026 तक बढ़ाया गया। इसका आधिकारिक कारण यह बताया गया कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों को प्रतिनिधित्व में नुकसान न हो। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को समयानुसार अद्यतन रखना आवश्यक है, अन्यथा राजनीतिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। इसलिए परिसीमन पर बहस केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मजबूती और संतुलित प्रतिनिधित्व से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

क्या परिसीमन में सुधार की आवश्यकता है?

देश में विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर बहस और विरोध होते रहते हैं। परिसीमन के संदर्भ में भी यह प्रश्न उठता है कि क्या मौजूदा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। इस पर मतभेद हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जनसहभागिता आधारित बनाया जा सकता है, जबकि अन्य का कहना है कि मौजूदा संवैधानिक ढांचा पर्याप्त है और उसका समय पर क्रियान्वयन ही सबसे महत्वपूर्ण है।

2026 और उत्तर प्रदेश: क्या होगा संभावित प्रभाव?

2026 के बाद संभावित परिसीमन को लेकर सबसे अधिक चर्चाउत्तर प्रदेशपर हो रही है, क्योंकि यह देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और वर्तमान में इसके पास 80 लोकसभा सीटें हैं। जनसंख्या के अनुपात के आधार पर भविष्य में इसकी सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना पर राजनीतिक और अकाद. मिक स्तर पर विचार हो रहा है।यदि सीटों की संख्या बढ़ती है, तो राज्य का भौगोलिक क्षेत्र वही रहेगा, लेकिन उसे अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय सीमाएं और राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। हालांकि, परिसीमन के आधार पर किसी राज्य कास्वत: विभाजन नहीं होता राज्य पुनर्गठन एक अलग संवैधानिक प्रक्रिया है, जो संसद के निर्णय पर निर्भर करती है। फिर भी, यदि बड़े राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या बहुत बढ़ती है, तो प्रशासनिक सुविधा और सुशासन के लिए राज्य पुनर्गठन की बहस तेज हो सकती है। इसलिए परिसीमन का मुद्दा केवल सीटों तक सीमित नहीं, बल्कि प्रतिनिधित्व, प्रशासनिक संतुलन और लो. कतंत्र की भविष्य की संरचना से भी जुड़ा हुआ है।

परिसीमन पर मांग, संभावित विधाई प्रक्रिया और जनता के लिए संदेश

परिसीमन को लेकर पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा कीसरकार सेमुख्य मांग यह है किइस पर लगी रोक को आगे न बढ़ाया जाए। परिसीमन एक संवैधानिक व्यवस्था है जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल अस्थाई रूप से स्थगित किया जा सकता है।यदि परिसीमन पर लगी समय-सीमा को आगे बढ़ाना हो, तो इसके लिएसंसद में विधेयक लाकर उसे पारित करना आवश्यक होगा। वहीं यदि रोक की अवधि समाप्त हो जाती है और उसे आगे नहीं बढ़ाया जाता, तो परिसीमन की प्रक्रिया स्वत: आगे बढ़ सकती है।इसी कारण इस मुद्दे पर पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा कीनजर संभावित विधाई कदमों पर है। हमारा उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि परिसीमन की प्रक्रिया को और आगे न टाला जाए, और यदि रोक बढ़ाने के लिए विधेयक लाया जाता है तो पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा द्वाराउसका लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा।

पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा का आम जनता के लिए संदेश

परिसीमन को लोकतांत्रिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसका उद्देश्य नागरिकों को उनके जनप्रतिनिधियों से जोड़ना और प्रतिनिधित्व को जनसंख्या के अनुपात में संतु. लित रखना है।लोकतंत्र की मजबूती उसके निरंतर अद्यतन और संस्थागत प्रक्रियाओं के पालन पर निर्भर करती है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि प्रक्रियाएं लंबे समय तक स्थगित रहती हैं, तो उसका प्रभाव धीरे-धीरे दिखाई देता है।पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा कामानना है कि यदि भारत को वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होना है, तो उसके लोकतांत्रिक ढांचे को भी मजबूत और प्रतिनिधिक बनाना होगा। अधिक व्यापक और संतुलित प्रतिनिधित्व से शासन प्रणाली में विविधता और उत्तरदायित्व दोनों बढ़ते हैं। इस प्रकार, परिसीमन पर चल रही बहस केवल तकनीकी विषय नहीं, बल्कि लोकतंत्र की गुणवत्ता, प्रतिनिधित्व की समानता और भविष्य की राजनीतिक दिशा से जुड़ा व्यापक विमर्श है।

(लेखक पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा, राष्ट्रीय सर्वखाप कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय बालियान खाप प्रधान हैं, व्यक्त विचार निजी हैं)

एक दिन का संकल्प: उम्रभर का स्वस्थ भविष्य

योगेश कुमार गोयल

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है लेकिन दुर्भाग्य से धूम्रपान और तंबाकू की लत इस अमूल्य धन को तेजी से नष्ट कर रही है। हर साल मार्च के दूसरे बुधवार को 'नो स्मोकिंग डे' मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को धूम्रपान की आदत छोड़ने के लिए प्रेरित करना और समाज को तंबाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। इस वर्ष यह दिवस 11 मार्च को मनाया जा रहा है। यह एक ऐसा अवसर है, जब लोग अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकते हैं और धूम्रपान मुक्त जीवन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। हर वर्ष इस दिन एक विशेष थीम के साथ लोगों को तंबाकू से दूर रहने का संदेश दिया जाता है। इस वर्ष का संदेश है 'धूम्रपान से मुक्त जीवन की शुरुआत एक धूम्रपान-मुक्त दिन से होती है।' इसका अर्थ स्पष्ट है कि यदि कोई व्यक्ति केवल एक दिन भी धूम्रपान से दूरी बना ले तो वह आगे चलकर इसे पूरी तरह छोड़ने की दिशा में पहला कदम उठा सकता है।

तंबाकू और निकोटीन की लत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं में से एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तंबाकू के कारण हर वर्ष लगभग 80 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। इनमें से करीब 70 लाख लोग सीधे धूम्रपान करने वाले होते हैं जबकि लगभग 12 लाख लोग ऐसे होते है, जो स्वयं धूम्रपान नहीं करते लेकिन दूसरों के धुएं के संपर्क में आने के कारण गंभीर बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। यह स्थिति बताती है कि धूम्रपान केवल करने वाले व्यक्ति को ही नहीं बल्कि उसके आसपास रहने वाले परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। हाल के वर्षों में देखा गया है कि दुनिया के कई देशों में धूम्रपान करने वालों की संख्या में कमी आई है लेकिन इसके बावजूद चिंता का विषय यह है कि युवाओं और किशोरों में तंबा. कू के उपयोग की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है।

वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार 13 से 15 वर्ष की आयु के लगभग 3.7 करोड़ बच्चे किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। ई-सिगरेट और अन्य नए निकोटीन उत्पादों ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है। आकर्षक पैकेजिंग, फ्लेवर और डिजिटल मार्केटिंग के जरिए इन उत्पादों को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने की कोशिश की जा रही है। विज्ञापन प्रति. बंधों के बावजूद सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से युवाओं को लक्ष्य बनाकर प्रचार किया जाता है। इस कारण किशोरों में तंबाकू की लत तेजी से फैल रही है, जो भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप ले सकती है। तंबाकू के दुष्प्रभाव केवल कैंसर तक सीमित नहीं हैं। यह शरीर के लगभग हर अंग को नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान फेफड़ों के कैंसर का प्रमुख कारण है और दुनिया में होने वाली फेफड़ों के कैंसर से लगभग 85 प्रतिशत मौतें धूम्रपान के कारण होती हैं। इसके अलावा तंबाकू हृदय रोग, स्ट्रोक, दमा, ब्रोंकाइटिस और कई अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों को जन्म देता है। लंबे समय तक तंबाकू का सेवन करने से मुंह, गले, पेट, लीवर और आंतों के कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। तंबाकू की समस्या भारत में भी काफी गंभीर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के 25 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। इनमें अधिकांश पुरुष हैं लेकिन महिलाओं में भी इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। भारत में तंबाकू सेवन के कई रूप प्रचलित हैं, जैसे खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा और सुपारी के साथ तंबाकू का सेवन। इन उत्पादों की आसान उपलब्धता और कम कीमत के कारण लोग जल्दी इसकी लत के शिकार हो जाते हैं। विभिन्न शोधों में यह भी सामने आया है कि तंबाकू से होने वाली बीमारियों का इलाज बहुत महंगा होता है। यदि तंबाकू के उपयोग को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका आर्थिक बोझ बहुत अधिक बढ़ सकता है। मुंह के कैंसर के मामलों में भारत पहले से ही दुनिया के कई देशों से आगे है और इसका मुख्य कारण तंबाकू तथा गुटखे का व्यापक उपयोग है। धूम्रपान केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक और सामाजिक समस्याओं को भी जन्म देता है। तंबाकू की लत व्यक्ति को धीरे-धीरे निर्भर बना देती है। कई युवाओं में यह लत अवसाद, चिंता और आत्मविश्वास की कमी जैसी मानसिक समस्याओं को भी जन्म देती है। जब किशोरावस्था में यह आदत लग जाती है तो उसे छोड़ना बेहद कठिन हो जाता है और इसका प्रभाव उनके पूरे जीवन पर पड़ता है। धूम्रपान के खतरों को देखते हुए समाज में व्यापक जागरूकता की आवश्यकता है। सरकारों ने तंबाकू नियंत्रण के लिए कई कानून बनाए हैं, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया है और तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी संदेश भी अनिवार्य किए हैं। इसके बावजूद केवल कानून से इस समस्या का समाधान संभव नहीं है। इसके लिए सामाजिक जागरूकता और व्यक्तिगत संकल्प दोनों जरूरी हैं। पत्रकारिता के अपने लंबे अनुभव के दौरान मैंने नशे के दुष्प्रभावों पर व्यापक अध्ययन किया है। वर्ष 1993 में मेरी पुस्तक 'मौत को खुला निमंत्रण' प्रकाशित हुई थी, जिसमें तंबाकू और अन्य नशों से होने वाले भयानक परिणामों का विस्तार से उल्लेख किया गया था। उस समय भी यह चेतावनी दी गई थी कि यदि समाज ने समय रहते नशे के खिलाफ जागरूकता नहीं बढ़ाई तो इसके दुष्परिणाम आने वाली पीढ़ियों को भुगतने पड़ेंगे। आज तीन दशक बाद भी यह चिंता उतनी ही प्रासंगिक दिखाई देती है। बहरहाल, नो स्मोकिंग डे हमें याद दिलाता है कि जीवन का हर पल अमूल्य है और इसे किसी भी तरह की लत के कारण बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। धूम्रपान छोड़ना कठिन अवश्य है लेकिन असंभव नहीं। यदि व्यक्ति दृढ़ निश्चय कर ले और परिवार तथा समाज का सहयोग मिले तो वह आसानी से इस लत से मुक्त हो सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम स्वयं भी धूम्रपान से दूर रहें और दूसरों को भी इसके खतरों के बारे में जागरूक करें। आखिरकार, एक स्वस्थ समाज की शुरुआत स्वस्थ व्यक्तियों से ही होती है। यदि हम तंबाकू से दूरी बनाकर जीवन को अपनाएं तो न केवल अपना स्वास्थ्य सुरक्षित रख सकते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर और सुरक्षित वातावरण तैयार कर सकते हैं। इसलिए इस नो स्मोकिंग डे पर संकल्प लें कि तंबाकू का साथ छोड़कर हर सांस को कीमती बनाएंगे और जीवन को स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान आलू की कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन करती समाजवादी पार्टी।

तेहरान में इजरायली हमले में कई ऐतिहासिक स्थलों को हुआ नुकसान

तेहरान। इजरायली हवाई हमलों में ईरान के इस्फहान में चहेल सोतून पैलेस सहित विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है। उल्लेखनीय है कि सफाविद काल का यह महल इस्फाहान के गवर्नर कार्यालय के पास स्थित है। रिपोर्टों के अनुसार, पास ही हुए बम धमाके के कारण महल परिसर के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। यह महल अपने भित्ति चित्रों, तालाबों और 17वीं शताब्दी के ऐतिहासिक हॉल के लिए जाना जाता है। इस्फाहान के एक निवासी ने बताया कि चहेल सोतून इमारत और गवर्नर कार्यालय के बीच केवल कुछ ही पेड़ हैं, और स्पष्ट रूप से उन्हें भी नुकसान पहुंचा है।

ईरान जंग: 9 एशियाई देशों में तेल संकट गहराया

बांग्लादेश में यूनिवर्सिटीज बंद, थाइलैंड में लिफ्ट इस्तेमाल पर रोक, पाक में मंत्रियों की सैलरी-विदेश यात्रा रोकी

इस्लामाबाद/ढाका/बैंकाक। ईरान जंग का असर अब एशिया के कई देशों में दिखाई देने लगा है। तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने के कारण कम से कम 9 एशियाई देशों में ऊर्जा संकट गहराने लगा है।

हालात ऐसे हैं कि अलग-अलग देशों को ईंधन बचाने और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े हैं। बांग्लादेश में सभी यूनिवर्सिटीज बंद कर दी गई हैं, ताकि बिजली और ईंधन की खपत कम की जा सके। वहीं थाइलैंड में सरकारी दफ्तरों में लिफ्ट के इस्तेमाल पर रोक लगाकर कर्मचारियों को सीढ़ियों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं और वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है। दूसरी ओर पाकिस्तान में खर्च कम करने के लिए मंत्रियों की सैलरी और विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी गई है, साथ ही सरकारी खर्च और ईंधन उपयोग में कटौती के फैसले लिए गए हैं। दरअसल ईरान और अमेरिका-इजरालय के बीच जंग की वजह से होर्मुज स्ट्रेट बंद है, इसके चलते तेल की सप्लाई ठप्प हो गई है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत अहम समुद्री रास्ता है। हर साल दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। थाईलैंड में सरकार ने ऊर्जा बचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम करने और दफ्तरों में लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए हैं। सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक जिन अधिकारियों को सीधे जनता की सेवा देनी होती है, उन्हें इस नियम से छूट दी गई है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चार्नवीराकुल ने सरकारी कर्मचारियों को ऊर्जा बचाने के लिए जरूरी कदम लागू करने को कहा है। सरकार ने विदेश यात्राओं को अस्थायी रूप से रोक दिया है। ऊर्जा बचत के लिए एयर कंडीशनर का तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने का निर्देश दिया गया है। अधिका. रियों को सूट-टाई जैसे औपचारिक कपड़ों की जगह शार्ट स्लीव शर्ट पहनने की सलाह दी गई है। ऊर्जा मंत्री के अनुसार देश के पास फिलहाल करीब 95 दिन का ऊर्जा भंडार बचा है। सरकार अमेरिका, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका से अतिरिक्त एलएनजी खरीदने की कोशिश कर रही है। सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर संकट और गहरा हुआ, तो दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के विज्ञापन बोर्ड की रोशनी कम करने और पेट्रोल पंपों को रात 10 बजे तक बंद करने जैसे कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। बैंकाक समेत पूरे थाईलैंड में पेट्रोल और डीजल लेने के लिए लाइनें लग रही हैं। चीन ने संभावित ऊर्जा संकट को देखते हुए कच्चे तेल की खरीद बढ़ाकर अपने रणनीतिक भंडार मजबूत करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने साल के शुरुआती महीनों में अतिरिक्त कच्चा तेल खरीदा है और इसे रणनीतिक तथा वाणिज्यिक भंडार में रखा जा रहा है। इसके साथ ही सरकार ने रिफाइनरियों को नए फ्यूल एक्सपोर्ट कान्ट्रैक्ट साइन न करने और कुछ तय शिपमेंट को रोकने के निर्देश दिए हैं। सरकार का मकसद घरेलू बाजार में पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर मिडिल-ईस्ट में संघर्ष लंबा चला और वैश्विक सप्लाई और प्रभावित हुई, तो चीन अपने रणनीतिक तेल भंडार का उपयोग कर सकता है।

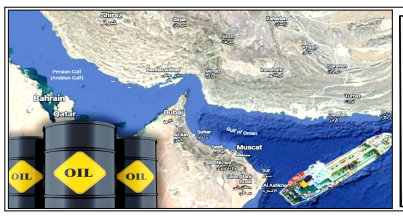

■ थाइलैंड में सरकारी दफ्तरों में लिफ्ट के इस्तेमाल पर रोक लगाकर कर्मचारियों को सीढ़ियों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं और वर्क फ्रॉम होम लागू किया गया है

संक्षिप्त समाचार

यूएई ने इराक में अपने दूतावास पर हमले की कड़ी निंदा की

अबू धाबी। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में अपने महावाणिज्य दूतावास को निशाना बनाकर किए गए एक आतंकी ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक बयान में इस हमले को 'बिना उकसावे वाला आतंकवादी कृत्य' बताया और जोर दिया कि राजनयिक मिशनों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों एवं कानूनों का गंभीर उल्लंघन है।

ईंधन बचाने के लिए वियतनाम में 'वर्क फ्रॉम होम'

हनोई। पश्चिम एशिया बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में आई अस्थिरता को देखते हुए वियतनाम सरकार ने देश में ईंधन की खपत कम करने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। वियतनाम के उद्योग और व्यापार मंत्रालय ने मंगलवार को नागरिकों से जहां संभव हो वहां 'रिमोट वर्क' (घर से काम) करने का आग्रह किया है ताकि यात्रा और परिवहन की मांग को कम किया जा सके। वियतनाम समाचार एजेंसी के अनुसार, मंत्रालय ने एक आधिकारिक अपील जारी कर नागरिकों से ईंधन बचाने के विभिन्न उपाय अपनाने को कहा है।

केन्या में भीषण सड़क हादसा: भीड़ पर चढ़ा ट्रक, 14 की मौत

वेबुए (केन्या)। केन्या के वेबुए-किटाले राजमार्ग पर सोमवार रात भीषण सड़क हादसे में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और 16 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मंगलवार को इस दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। इस हादसे में दो मोटरसाइकिलों के बीच आमने-सामने की जोरदार टक्कर हुई, जिसमें दोनों सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद जब आसपास के लोग और राहगीर घायलों की मदद के लिए वहां जमा हुए, तभी एक अनियंत्रित ट्रक भीड़ को कुचलता हुआ निकल गया।

तेल मुद्दे पर ट्रम्प की ईरान को चेतावनी

कहा: अगर ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग को रोकता है, तो उस पर बीस गुना अधिक भयानक हमला होगा

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को ईरान को चेतावनी दी कि यदि उसकी सेनाएं होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग से होने वाले तेल के परिवहन को रोकती हैं, तो उन पर 'बीस गुना अधिक भयानक' हमला किया जाएगा। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि अगर ईरान ऐसा कुछ भी करता है जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य के भीतर तेल का प्रवाह रुकता है, तो अमेरिका उन पर अब तक हुए हमलों की तुलना में बीस गुना अधिक जोर से हमला करेगा। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, अमेरिका आसानी से नष्ट होने वाले लक्ष्यों को खत्म कर देगा, जिससे ईरान के लिए एक राष्ट्र के रूप में फिर से खड़ा होना लगभग असंभव हो जाएगा।

ट्रम्प ने इस चेतावनी को 'अमेरिका की ओर से चीन और उन सभी देशों के लिए एक उपहार' बताया जो होर्मुज जलडमरूमध्य का काफी उपयोग करते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस 'पहल' की काफी सराहना की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 10 मार्च तक होर्मुज जलडमरूमध्य मार्ग में वाणिज्यिक यातायात लगभग पूरी तरह से ठप हो गया है। हालांकि औपचारिक रूप से इसे बंद करने की कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अत्यधिक जोखिमों के कारण बीमा कंपनियों द्वारा बीमा रद्द करने के कारण इस मार्ग पर यातायात प्रभावी रूप से बंद हो गया है। मार्सक, सीएमए सीजीएम और हैपग-लॉयड जैसी प्रमुख परिवहन कंपनियों ने इस मार्ग से आवाजाही को स्थगित कर दिया है और जहाजों को 'केप ऑफ गुड होप' के रास्ते भेज रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ही ड्रोन और मिसाइल हमलों में कम से कम आठ नाविक मारे गए हैं और कई टैंकर क्षतिग्रस्त हुए हैं। छह मार्च को, संयुक्त अरब अमीरात के ध्वज वाली नौका मुसाफा-2 एक विस्फोट के बाद डूब गई, जिससे चालक दल के तीन सदस्य लापता हो गए। सात मार्च को, माल्टा के ध्वज वाले टैंकर 'प्रिमा' पर कथित तौर पर एक ईरानी ड्रोन द्वारा हमला किया गया था। भारत वर्तमान में इस क्षेत्र में फंसे 36 भारतीय ध्वज वाले जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। फ्रांस ने भी युद्ध की तीव्रता कम होने के बाद जहाजों को सुरक्षित एस्कॉर्ट करने के लिए एक मिशन की तैयारी की घोषणा की है। नाकाबंदी के परिणामस्वरूप, कच्चे तेल की कीमतें 9 मार्च को 120 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक बढ़ गईं, जो बाद में घटकर लगभग 88-90 डॉलर पर आ गईं। कुवैत और कतर ने कुछ ऊर्जा अनुबंधों पर 'फोर्स मेज्योर' घोषित कर दिया है क्योंकि टैंकर सुरक्षित रूप से फारस की खाड़ी से बाहर निकलने में असमर्थ हैं। 'फोर्स मेज्योर' एक सामान्य क्लॉज है जो अनिवार्य रूप से दोनों पक्षों को दायित्व या बाध्यता से मुक्त करता है जब पार्टियों के नियंत्रण से बाहर कोई असाधारण घटना या परिस्थिति आ जाती है।

■ ट्रम्प ने इस चेतावनी को 'अमेरिका की ओर से चीन और उन सभी देशों के लिए एक उपहार' बताया

एक लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देंगे: ईरान

तेहरान। अमेरिका-इजरायल और ईरान जंग का 11वां दिन हैं। इस बीच ईरान ने कहा है कि वह एक लीटर तेल भी बाहर नहीं जाने देगा। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने को लेकर एक नई शर्त रखी है। इजरायली मीडिया वाइनेट की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की सेना इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स (आईआरजीसी) ने कहा है कि कुछ देशों के जहाजों को इस रास्ते से गुजरने दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन देशों को पहले इजरायल और अमेरिका के राजदूतों को अपने देश से निकालना होगा। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का बहुत अहम समुद्री रास्ता है। हर साल दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल की सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती है। हालांकि अमेरिकी चैनल सीएनएन ने कहा है कि ईरान इस रास्ते से गुजरने वाले तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर सिक्योरिटी टैक्स यानी सुरक्षा शुल्क लगाने की योजना बना रहा है, खासकर उन जहाजों पर जो अमेरिका के सहयोगी देशों के हैं।

■ कहा: जो देश इजरायल-अमेरिका के राजदूतों को निकालेंगे, उनके जहाज होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने देंगे

होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी नौसेना का हमें इंतजार: ईरानी सेना

तेहरान। ईरान की सेना के प्रवक्ता ने मंगलवार तड़के कहा कि उनके फौजी होर्मुज जलडमरूमध्य में अमेरिकी नौसैनिक बेड़े का इंतजार कर रहे हैं और युद्ध का अंत ईरान के हाथों में है। सरकारी मीडिया में आई जानकारी के अनुसार इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के प्रवक्ता मेजर जनरल अली मोहम्मद नैनी ने यह टिप्पणी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एक संवादादाता सम्मेलन और होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा को लेकर दिए गए हालिया बयानों के जवाब में की है। नैनी ने कहा कि ईरानी सशस्त्र बल होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक बेड़े और विमान वाहक पोत जेराल्ड फोर्ड का इंतजार कर रहे हैं।

अमेरिका से अब वार्ता संभव नहीं: अराघची

तेहरान। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि अमेरिका के साथ बातचीत का अनुभव 'कड़वा' रहा है और अब उसके साथ नए सिरे से कूटनीतिक वार्ता की संभावना नहीं है। अराघची ने पीबीएस को दिए एक साक्षात्कार में अमेरिका पर बार-बार विश्वासघात और सैन्य आक्रामकता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिकियों से बातचीत या उनके साथ बातचीत करने का सवाल अब एजेंडे में होगा।

हमारे लिए यह अनुभव बहुत कड़वा रहा है। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने पिछले वर्ष जून में अमे. रिका के साथ अच्छे इरादे से बात. चीत शुरू की थी, लेकिन बातचीत के दौरान ही उस पर हमला कर दिया गया। अराघची के अनुसार इस वर्ष भी अमेरिका ने यह भरोसा दिलाया था कि वह हमला नहीं करेगा और ईरान के परमाणु मुद्दे का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है। विद. श मंत्री ने कहा कि तीन दौर की बातचीत में प्रगति के बावजूद हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए। उन्होंने कहा कि अमे. रिकी वार्ता दल ने भी प्रगति को स्वीकार किया था, लेकिन इसके बावजूद हमला किया गया। अराघची ने फारस की खाड़ी के देशों को संदेश देते हुए कहा कि क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के हमले आत्मरक्षा के अधिकार के तहत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यदि अन्य देश अपनी सुविधाओं की सुरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं तो ईरान को भी अपने लोगों की रक्षा करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यह युद्ध ईरान ने नहीं चुना बल्कि उस पर थोपा गया है और देश केवल अपनी रक्षा कर रहा है। अराघची ने यह भी कहा कि ईरान जरूरत पड़ने तक मिसाइल हमले जारी रखने के लिए तैयार है। उन्होंने क्षेत्रीय देशों के साथ संबंधों को लेकर उठ रही चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि ईरानी जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बीच पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण वैश्विक तेल कीमतों में तेजी और ऊर्जा आपूर्ति में बाधा की आशंका बढ़ गई है।

■ इस वर्ष भी अमेरिका ने यह भरोसा दिलाया था कि वह हमला नहीं करेगा: अराघची

लेबनान में उत्पन्न हुआ भीषण मानवीय संकट

बेरुत/जिनेवा। लेबनान पर इजरायल के लगातार बढ़ते हमलों के कारण पिछले 24 घंटों में यहां एक लाख से अधिक लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को मजबूर हुए हैं।

इससे एक गंभीर मानवीय त्रासदी का संकेत मिलता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (यूएनएचसीआर) की प्रतिनिधि कैरोलिना लिडहोम बिलिंग ने जिनेवा में पत्रकारों को बताया कि अब तक लेबनान सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर कुल 667000 से अधिक विस्थापित लोग पंजीकृत हो चुके हैं। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि पंजीकृत विस्थापितों की संख्या में मात्र एक दिन में एक लाख का इजाफा हुआ है, जो बेहद डरावना है। यूएन प्रतिनिधि ने चेतावनी दी कि वर्तमान में विस्थापन की गति 2024 में इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच हुए पिछले युद्ध की तुलना में कहीं अधिक तेज है। इजरायली बमबारी के डर से दक्षिण लेबनान और बेरुत के उपनगरीय इलाकों से लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में उत्तर की ओर पलायन कर रहे हैं। विस्थापितों की भारी संख्या के कारण राहत शिविरों और आश्रय स्थलों पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया है। लेबनान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियां भोजन, दवा और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए संघर्ष कर रही हैं। मानवीय संगठनों ने तत्काल युद्धविराम की अपील की है ताकि विस्थापितों को आवश्यक सहायता पहुंचाई जा सके। संयुक्त राष्ट्र ने यह भी जानकारी दी है कि लेबनान में रहने वाले सीरियाई शरणार्थी अब वापस अपने देश लौटने को मजबूर हैं। गत दो मार्च से अब तक 80000 से अधिक सीरियाई नागरिक इजरायली हमलों से बचने के लिए लेबनान की सीमा पार कर सीरिया जा चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विस्थापन की स्थिति इतनी आपातकालीन है कि कई परिवार बिना अपना सामान लिए ही जल्दबाजी में लेबनान छोड़कर निकल गए।

■ एक दिन में एक लाख लोग विस्थापित, कुल संख्या 6.67 लाख के पार पहुंची

भारत ने की अफगान पर हुए हवाई हमलों की निंदा

हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर व राज्य संप्रभुता के सिद्धांत का 'घोर उल्लंघन' करार दिया

नई दिल्ली/संयुक्त राष्ट्र। भारत ने अफगानिस्तान पर हाल ही में हुए हवाई हमलों की संयुक्त राष्ट्र में कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच बढ़ते सीमा पार संघर्षों के बीच भारत ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और राज्य संप्रभुता के सिद्धांत का 'घोर उल्लंघन' करार दिया है।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने महासचिव की रिपोर्ट में उजागर की गई उन चिंताओं का उल्लेख किया, जो सीमा पार हिंसा के कारण हताहत होने वाले नागरिकों से जुड़ी हैं। हरीश ने कहा कि महासचिव की रिपोर्ट में सीमा पार सशस्त्र हिंसा के कारण नागरिकों के प्रभावित होने पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। हम महासचिव के उस आह्वान का समर्थन करते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत दायित्वों का पालन करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के क्षेत्र पर हुए हवाई हमलों की भारत कड़ी निंदा करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और राज्य संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन हैं। भारतीय दूत ने इस भू-आबद्ध देश पर आर्थिक दबाव के संबंध में भी चिंता जताई। हरीश ने गंभीर चिंता जताते हुए व्यापार के लिए रास्ता रोकने और चारों तरफ जमीन से घिरे देश की पहुंच को जानबूझकर बंद कर व्यापार और पारगमन आतंकवाद के अभ्यास का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों के सामने भू-आबद्ध विकासशील देशों पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणाएं खोखली लगती हैं। इन देशों की व्यापारिक और पारगमन संबंधी मजबूरियों को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। भारत के रुख की पुष्टि करते हुए हरीश ने कहा कि हम इन कृत्यों की निंदा करते हैं और अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और स्वतंत्रता के लिए अपने समर्थन की भी पुष्टि करते हैं। उन्होंने आतंकवाद के निरंतर खतरे का भी जिक्र किया। उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान किया कि आईएसआईएस और अल-कायदा जैसे संगठन अब सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा न दे सकें।

■ भारतीय दूत ने इस भू-आबद्ध देश पर आर्थिक दबाव के संबंध में भी चिंता जताई

ऑस्ट्रेलिया ने पांच ईरानी महिला फुटबॉलरों को दी शरण

कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी महिला फुटबॉल टीम की उन पांच सदस्यों को मानवीय वीजा प्रदान किया है, जिन्होंने एक मैच से पहले राष्ट्रगान गाने से इनकार करने के बाद यहां शरण मांगी थी।

ईरान ने इन महिला खिलाड़ियों को युद्धकालीन गद्दार करार दे दिया था। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस ने कैनबरा में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक इन बहादुर महिलाओं की स्थिति से बहुत मायूस हैं। उन्होंने कहा कि वे यहां सुरक्षित हैं और उन्हें यहां अपने घर जैसा महसूस करना चाहिए। ऑस्ट्रेलियाई गृह मंत्रालय ने इन पांच टीम सदस्यों के नाम कप्तान जहरा घंबारी, मिडफील्डर फातेमेह पसंदीदेह, जहरा सरबाली अलीशाह, मोना हमौदी और डिफेंडर अतेफेह रमजानीजादेह बताए हैं। ऑस्ट्रेलियाई गृह मंत्री टोनी बर्क ने कहा कि ईरानी टीम की शेष खिलाड़ी, गोल्ड कोस्ट के एक होटल में हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने टीम की अन्य सदस्यों को भी ऑस्ट्रेलिया में रुकने का अवसर दिया है। ईरान की महिला फुटबॉल टीम क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 'एएफसी महिला एशियाई कप 2026' में भाग लेने आई थी। टूर्नामेंट के पहले मैच में दक्षिण कोरिया के खिलाफ टीम की खिलाड़ियों ने ईरान का राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया और मौन खड़ी रहीं। इस कदम को ईरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के रूप में देखा गया। इसके बाद ईरानी सरक. ारी मीडिया ने खिलाड़ियों को 'युद्धकालीन गद्दार' करार दिया और उनके इस कृत्य को 'अपमान की पराकाष्ठा' बताया। रविवार को टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद खिलाड़ियों को वापस ईरान लौटना था, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंताएं जताई जाने लगीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑस्ट्रेलिया के इनको मानवीय वीजा देने के फैसले का स्वागत करते हुए इसे एक सही कदम बताया है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर जानकारी दी कि उन्होंने इस बारे में अल्बनीस से सीधी बात की है और वे इस संवेदनशील स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल रहे हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रम्प ने चेता. वनी दी थी कि अगर इन खिलाड़ियों को वापस ईरान भेजा गया तो उनके साथ बुरा बर्ताव हो सकता है या उन्हें मारा भी जा सकता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आगाह किया था कि खिलाड़ियों को वापस भेजना एक 'भयानक मानवीय भूल' होगी।

■ ईरान की महिला फुटबॉल टीम क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 'एएफसी महिला एशियाई कप 2026' में भाग लेने आई थी

तुर्की में अमेरिकी 'पैट्रियट' मिसाइल सिस्टम तैनात

अंकारा। ईरान के साथ बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और हालिया मिसाइल उल्लंघन की घटनाओं के बीच, तुर्की ने मंगलवार को कहा कि उसके प्रांत मालत्या में अमेरिका निर्मित 'पैट्रियट' हवाई रक्षा प्रणाली तैनात कर दी गई है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह कदम उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के 'उन्नत वायु और मिसा. इल रक्षा' उपायों के तहत उठाया गया है।

रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए, अपनी सीमाओं और हवाई क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए नाटो सहयोगियों के साथ परामर्श कर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मालत्या में तैनात पैट्रियट सिस्टम को परिचालन के लिए तैयार किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि मालत्या में नाटो का महत्वपूर्ण 'कुसे. रिक रडार स्टेशन' भी स्थित है। यह तैनाती तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप अर्दोगन के ईरान को दी गई कड़ी चेतावनी के बाद हुई है। रिपोर्टों के अनुसार, ईरान से दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल तुर्की के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी, जिसे पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात नाटो रक्षा प्रणालियों ने नष्ट कर दिया। मिसाइल का मलबा गाजियानटेप इलाके की खाली जमीन पर गिरा। यह पांच दिनों के भीतर इस तरह की दूसरी घटना है। राष्ट्रपति अर्दोगन ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि ईरान द्वारा उकसावे वाले कदम उठाना जारी है, जो हमारे सदियों पुराने पड़ोसी संबंधों पर छाया डाल सकते हैं। हमने उसे आवश्यक चेता. वनी दे दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि तुर्की अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है।

■ तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने उठाया ईरान से बढ़ते तनाव के बीच नाटो का बड़ा कदम